

In Pursuit of Truth

वर्ष : 20 | अंक : 22
16 से 31 अगस्त 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

आक्स

पाक्षिक

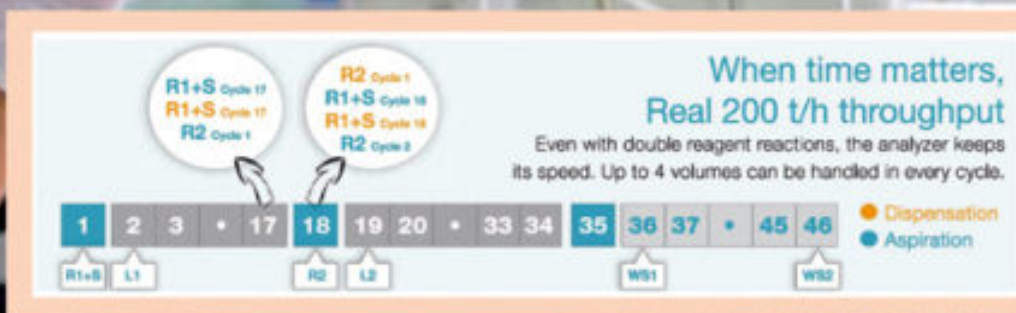


आज़ादी का अमृत महोत्सव आओ... याद करें कुर्बानी

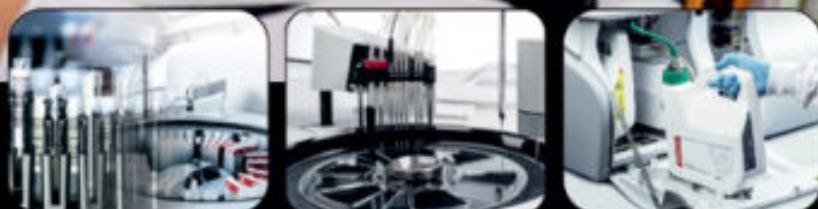
आज के खुशहाल भारत के पीछे छुपा है
लाखों लोगों का बलिदान...

गुमनाम बलिदानियों को करें याद...
जो फांसी का फंदा चूम शहीद हो गए

ANU SALES CORPORATION



We Deal in Pathology & Medical Equipment



Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ 9329556524, 9329556530 ✉ Email : ascbhopal@gmail.com

● इस अंक में

मप्र भाजपा

8

कैलाश को मप्र का ताज!

मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे एक साल पहले यानी इस साल नवंबर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है। जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल इकाई के केंद्रीय प्रभारी से हटा दिया है...

राजपथ

10-11

51 फीसदी का टारगेट

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस मिशन 2023 पर हो गया है। मतदाताओं को साधने के लिए दोनों पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आगामी विधानसभा...

मप्र कांग्रेस

13

2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस

मप्र में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पूरे होते ही कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जिलों के संगठन प्रभारी बदल दिए हैं। जिलों के नए इंचार्ज को पीसीसी की तरफ से ये निर्देश...

खेती-किसानी

15

मवेशी छोड़ने को मजबूर किसान

मप्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय पालने वाले किसानों को शिवराज सरकार ने 900 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। बावजूद इसके किसान बिना दूध वाली गाय-भैंस रखने को तैयार नहीं हैं। सरकार द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

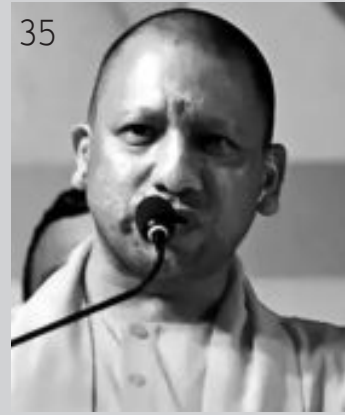


देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस बार देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के समय भारत की पहचान दुनिया के गरीब देश के रूप में थी। लेकिन आज भारतवर्ष दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है और जिस खुशहाली के लिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके पीछे हजारों-लाखों लोगों का बलिदान रहा है।

16-17



35



44



45



राजनीति

30-31

मुद्दों के संकट से जूझता विपक्ष

भारतीय राजनीति और संसदीय प्रणाली का विश्लेषण करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था- 'यह देखकर अफसोस होता है कि समय बीतने के साथ संसदीय प्रणाली चलाने के लिए जो परिपक्वता आनी चाहिए, उसके बजाय संसदीय व्यवहार में निरंतर गिरावट आ रही है।

महाराष्ट्र

34

बिगड़ी बनाने उतरे आदित्य

एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे अब अपनी पार्टी को बचाने में जुट गए हैं। इसके पूर्व उनकी इस बात के लिए आलोचना होती थी कि वे मुंबई में बॉलीवुड सितारों व हस्तियों के साथ व्यस्त रहते हैं, बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वक्त बिताने के...

बिहार

36

मुखर होने लगे क्षेत्रीय दल...

नीतीश कुमार के पाला बदलते ही विपक्षी यकायक भाजपा के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। हालांकि, हमेशा की तरह इनमें एका होना बहुत मुश्किल है। दरअसल, भाजपा और मोदी के खिलाफ बोल-बोलकर ये दल भाजपा के ही वोटों की वृद्धि...

6-7 अंदर की बात

40 समीक्षा

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



बारिश-बाढ़ में बह गई विकास की खुमारी...

कि सी ने क्या खूब लिखा है...

**जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है,
भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना आसान नहीं है।**

इसका नजारा इस बार मानसून की बारिश में देखने को खूब मिल रहा है। विकास के पट्टे पर खराब देश में तेजी से सड़क, पुल, बांध का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इनकी गुणवत्ता पर किसी का ध्यान नहीं है। कह सकते हैं कि देश में विकास की खुमारी इस कदर चढ़ी हुई है कि भ्रष्टाचारी मालामाल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर सड़क, पुल-पुलियाओं का बुलेट की गति से निर्माण हो रहा है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार आकड़ों परोसकर वाहवाही लूट रही है। लेकिन उनकी विकास की खुमारी इस बार बारिश और बाढ़ में बह गई है। नया नवेला बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे हो या मप्र की सड़कों पर बने पुल-पुलिया कोई भी मानसून की बूढ़ों को झेल नहीं पाया है। हद तो यह है कि धार जिले के कारम में बन रहा डैम तो दरका ही उसके बाद रायसेन में एक साल पहले बना ढाई करोड़ की लागत वाला पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पुल का एक हिस्सा ढहने से यहां यातायात बंद कर दिया गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं शिवनी-मंडला को जोड़ने वाला थावर नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे आवागमन बंद हो गया है। उधर, विदिशा जिले के बागरोड़ में स्थित दानमणि डैम में भी लीक होने लगा। इससे पहले भोपाल के पास मंडीदीप रोड पर बने पुल के पास की सड़क दरक गई। यह तो महज कुछ उदाहरण हैं। मप्र सहित देशभर में मानसून के कारण सड़क और पुल-पुलियाओं के टूटने और दरकने के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। दरअसल, रिकॉर्ड बनाने की लालसा में सरकारों और एजेंसियां मानकों का पालन नहीं करती हैं। इसका असर यह होता है कि जनता की कमाई से बनाए गए सड़क और पुल अक्सर ही टूट रहे हैं। कारम बांध के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला सुब्रिंरियों में बना है, लेकिन रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के बीना नदी पर बेगमगंज-हैदरगढ़ मार्ग पर ईदगाह के करीब बनाया गया पुल पहली ही बारिश में अपने निर्माण में हुई भ्रष्टाचार की कहानी बयां करने लगा है। ब्रिज कारपोरेशन द्वारा ठेकेदार के माध्यम से तैयार कराए जा रहे करीब ढाई करोड़ रुपए की लागत के इस पुल का अभी विभाग को सुपुर्द करने से पहले ही एक हिस्सा तीन फीट तक धसक गया है। आसपास के इलाकों के रास्ते बंद हो चुके हैं। करीब दो दर्जन गांव का सड़क संपर्क विदिशा से टूट गया है। पुल के धसकने से आई दरारें भ्रष्टाचार की दास्तान बयां कर रही हैं। पहले पुल की लागत करीब ढेड़ करोड़ रुपए थी, लेकिन बीना बांध के डूब क्षेत्र के सर्वे के उपरांत इस पुल की ऊंचाई को बढ़ाया गया। ताकि आवागमन में किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। ऊंचाई बढ़ाने के बाद लागत ढाई करोड़ पहुंच गई। लेकिन इसके निर्माण में मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया। उधर, थावर नदी का पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। शिवनी-मंडला को सीधे तौर पर जोड़ने वाले राजमार्ग 11-ए पर अंग्रेजों के जमाने के इस पुल का अधिकांश हिस्सा बह जाने से मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। पता चला कि, ब्रिटिशकाल में बड़े-बड़े पत्थरों को टाइल्स के स्वरूप में लगाकर बनाए गए पुल का पूरा स्लैब पानी में बह गया है। साथ ही कई स्थानों पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर वाहन चलाना संभव नहीं है। बताया जाता है कि अधिकारियों ने इस पुल की मरम्मत को लेकर निष्क्रियता दिखाई जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया।

- राजेन्द्र आगाल



वर्ष 20, अंक 22, पृष्ठ-48, 16 से 31 अगस्त, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जेन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफैक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718

MP/PL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संचालक

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव

089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी

075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्क्लेव मायापुत्री

फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,

भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : नवीन खुशवंशी, खुशवंशी कॉलोनी, इंदौर,

मो.-9827227000

देवास : जय सिंह, देवास

मो.-7000526104, 9907353976

स्वाधिकाारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जेन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



हर घर जल मिशन

देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अब मप्र का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। ये बड़ी खुशी की बात है।

● प्रतीक पुरोहित, सीहोर (म.प्र.)



मुफ्त ही मुफ्त

देश की राजनीति मजाकिया होती जा रही है। जनता को लुभाने के लिए नेता मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और तो और मुफ्त बस का सफर तक देने को तैयार हैं। देश में कोरोना महामारी के बाद कई राज्यों ने जनता को खिन्न और मुफ्त योजनाओं की रेवड़ियां बांटकर खुद को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के बीच अब इन वोट बटोरने वाली योजनाओं पर नई बहस छिड़ गई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र पर निर्भर हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा देश भी पाकिस्तान और श्रीलंका की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि कंट तक कर्ज में डूबे राज्य आय का आधे से ज्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे हैं।

● महेंद्र तिवारी, सारंगपुर (म.प्र.)

कांग्रेस की राह आसान नहीं

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ ताबड़तोड़ आक्रामक मुहिम चला रही है। लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा होता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बेवजह कांग्रेस भाजपा पर कीचड़ उठालने का प्रयास कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, जिससे वह देशभर में अपनी साख्र बचा सके और एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आ सके। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे।

● बृजेंद्र सिंह, नई दिल्ली

कमजोर होती कांग्रेस

प्रदेश सहित देशभर में कांग्रेस एक कमजोर पार्टी के रूप में नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हाल ही में निकाय चुनाव में पूर्व मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में ही पार्टी को हार मिली है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को और अधिक मेहनत करनी होगी।

● प्रिया सूर्यवंशी, भोपाल (म.प्र.)

खड़कों का विकास

देशभर में खड़कों के विकास का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इसी तर्ज पर मप्र की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में विकास की कुछ योजनाओं पर काम हो रहा है। जिनसे सीधे देश के बड़े महानगरों में जाने के लिए सीधी खड़कों को निर्माण किया जाएगा।

● राजेंद्र सिंह, इंदौर (म.प्र.)



महंगाई की मार

किस्मानों पर महंगाई की मार दौतरफा है, क्योंकि उनके लिए खेती की लागत तो बढ़ गई लेकिन उपज के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े। राष्ट्र निर्माण के नाम पर कमरतोड़ महंगाई अनेक लोगों के लिए असहनीय होती जा रही है। जैसे तो महंगाई हर वर्ग को प्रभावित करती है, लेकिन जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च हो जाता है उन पर इसकी मार सबसे अधिक है। गरीब और आम आदमी पर महंगाई का बोझ अधिक है।

● शिवानी सोनी, राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



गुटबाजी खत्म करने में जुटी भाजपा

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी राज्य के ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति के काम में जुट गई है। प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ की आबादी का लगभग 47 फीसदी ओबीसी वर्ग है। सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के पीछे सीधे तौर पर एक बड़ा वोट बैंक को साधने की रणनीति माना जा रहा है। दरअसल नए प्रदेश अध्यक्ष बने अरुण साव साहू समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो प्रदेश में ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा है। ओबीसी की आबादी 47 फीसदी है, जो राज्य के हर चुनाव में किंगमेकर की भूमिका में होते हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है। भाजपा ने साव को जिम्मा सौंपकर प्रदेश में गुटबाजी रोकने की कोशिश भी की है। प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता भाजपा से कांग्रेस की ओर चले गए हैं। पार्टी को इसी कारण से राज्य की सत्ता खोनी पड़ी। अब भाजपा को फिर से सत्ता पर आने के लिए प्रदेश में मजबूत ओबीसी चेहरे की जरूरत थी। इसलिए पार्टी ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना। साव का नाम भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में सामने आना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पार्टी अब प्रदेश के ओबीसी मतदाताओं को साधने में लगी है।

अभी और बढ़ेगी गांधी परिवार की मुश्किलें

आपातकाल का वह दौर जब पूरे देश में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ गुस्सा था, और फिर 19 दिसंबर 1978 का वह दिन जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, को छोड़ दिया जाय तो आजादी के बाद गांधी परिवार के लिए, व्यक्तिगत स्तर पर शायद ही कोई बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। लेकिन इस समय 'नेशनल हेराल्ड' और 'यंग इंडियन' केस में ईडी के हर रोज बढ़ते शिकंजे ने गांधी परिवार को अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। और यह मुश्किल अगर और बढ़ी तो इसका असर कांग्रेस पार्टी पर भी सीधे तौर पर दिखाई देगा। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष का पद करीब तीन साल से खाली हो लेकिन पार्टी की राजनीति गांधी परिवार के ही इर्द-गिर्द घूमती रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी सरकार है। जबकि कर्नाटक और मद्रास में सत्ता हासिल करने के बाद वह गंवा चुकी है। ईडी की तलवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर लटक रही है। और भाजपा इसी को लेकर लगातार हमला करती रहती है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर हैं। जाहिर है जिस तरह हाल के दिनों में ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ के साथ नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील किया उससे माना जा रहा है कि ईडी के पास केस को लेकर पुख्ता सबूत हैं।



टीआरएस में होगी बड़ी टूट

तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि सत्तारूढ़ टीआरएस के दर्जनभर विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य में कई सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश नेता कहते घूम रहे हैं कि टीआरएस विधायकों का के चंद्रशेखर राव सरकार में कोई भविष्य नहीं है। भाजपा नेता संजय कुमार की मानें तो यदि अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा 62 सीटें जीतेगी। उनके अनुसार, टीआरएस प्रशासन के प्रति बढ़ती सार्वजनिक शत्रुता के कारण भाजपा के अपेक्षित वोट शेयर में वृद्धि होगी। कांग्रेस सांसद कोमातीरेड्डी वेंकट रेड्डी (मुनूगोड़े विधायक राजगोपाल रेड्डी के भाई) के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा 'जो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करता है उसका पार्टी में शामिल होने का स्वागत है। वेंकट रेड्डी लंबे समय से टीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं।' गौरतलब है कि राजगोपाल रेड्डी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है जिसके चलते उनकी सीट मुनूगोड़े में अब उपचुनाव होने जा रहा है।

भाजपा छोड़ेंगे ब्रिजेंद्र सिंह

आयाराम-गयाराम की राजनीति के लिए मशहूर हरियाणा में कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के बुजुर्ग नेता संपत सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चा है। खबर है कि बिश्नोई के भाजपा में आने के बाद हिसार में भाजपा की राजनीति उन्हीं के हिसाब से होगी। इसलिए संपत सिंह पाला बदल रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि हिसार से भाजपा के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह क्या करेंगे? ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा के जाने-माने नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। आईएएस अधिकारी थे और नौकरी छोड़कर वे अपने पिता की खाली हुई हिसार सीट से चुनाव लड़े। अब कहा जा रहा है कि भाजपा ने बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का वायदा किया है। अगर भाजपा वायदा निभाती है तो क्या ब्रिजेंद्र सिंह 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे? उनके कांग्रेस में जाने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके पिता कांग्रेस छोड़ कर ही भाजपा में शामिल हुए थे।

घर वापसी में जुटी भाजपा

साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी भाजपा सियासी कुनबा बरकरार रखने और बढ़ाने की कोशिश में नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी ने 'घर वापसी' मिशन की शुरुआत कर दी है। पार्टी की इस पहल को दल छोड़ने वालों तक पहुंचने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में पार्टी छोड़कर गए कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा में वापसी की थी। इनमें चेतन बरागटा का नाम शामिल है। बरागटा ने पिता के निधन के बाद जुब्बल-कोठकाई से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव लड़ा था। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर कर दिया गया था। उनके अलावा हमीरपुर से उर्मिल ठाकुर की भी वापसी हुई है। वहीं भाजपा ने कांगड़ा से आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चौधरी को भी दल में लाने में सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि चौधरी कांग्रेस छोड़कर 'आप' में चले गए थे।

अब ऊंट पहाड़ के नीचे

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इन दिनों यह कहावत प्रदेश के सांख्यिकी विभाग पर सटीक बैठ रही है। आंकड़ों की बाजीगरी करने वाला यह विभाग इस समय एक ऐसे पेंच में फंस गया है। दरअसल, कार्यालय प्रधान महालेखाकार ने सांख्यिकी विभाग से प्रदेश में जन्म और मृत्यु का आंकड़ा मांग लिया है। एजी की मांग के बाद से ही विभाग के अधिकारी असमंजस में फंसे हुए हैं। क्योंकि उनके पास प्रदेश में हुए जन्म और मृत्यु का पूरा आंकड़ा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जन्म का आंकड़ा तो हम अस्पतालों से जुटा लेंगे, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा कैसे मिल जाएगा। विभाग की परेशानी यह है कि कोरोना संक्रमणकाल में लोगों की हुई मृत्यु का पूरा हिसाब-किताब किसी के पास नहीं है। ऐसे में विभाग पसोपेश में है कि पूरा आंकड़ा कहां से लाया जाए। उधर, सूत्रों का कहना है कि एजी ने कोरोनाकाल में भी मौतों का पूरा आंकलन करा लिया है। यह बात सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों की भी जानकारी में आ गई है। अधिकारियों को डर सता रहा है कि अगर उन्होंने अनुमानित आंकड़ा पेश किया और अगर वह एजी के आंकड़े से कम रहा तो प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली राशि नहीं मिल पाएगी। अभी तक आंकड़ेबाजी करने वाला विभाग अब ऊंट की तरह पहाड़ के नीचे आया है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए।

किताब के मजमून की खोज

प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी अपनी प्रशासनिक ड्यूटी के साथ ही किताबें लिखने के लिए जाने जाते हैं। साहब ने कई विषयों पर किताबें लिखी हैं। उनकी कई किताबें खासी चर्चा में रही हैं और उस पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इस बार साहब की मंशा ऐसी किताब लिखने की है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बने। बताया जाता है कि नई किताब के मजमून की खोज करने के लिए साहब ने सरकार से अनुमति लेकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के केंद्र बिंदु कोव का दौरा किया है। बताया जाता है कि अगली किताब इस युद्ध पर आधारित हो सकती है। हालांकि साहब के इस दौर को लेकर प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह के गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जहां युद्ध हो रहा है, साहब वहां थोड़ी गए होंगे। वे माहौल बनाने के लिए वहां गए थे ताकि लोगों को लगे कि किताब में जमीनी हकीकत बयां है, जबकि किताब तो टीवी और अखबारों में छपी खबरों और कहानियों को आधार बनाकर लिखी जाएगी। जितने लोग, उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। लोग बातें कुछ भी करें, लेकिन यह तो तय है कि साहब किताब लिखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।



मैं नहीं तो कोई नहीं...

शीर्षक पढ़कर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। मामला ही कुछ ऐसा है। यह मामला ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले का है। यह जिला राजनीतिक सुर्खियों के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस जिले को एक 'महाराज' अपना समझती हैं। उनकी मर्जी के बिना इस जिले में कोई भी काम नहीं होता है। आलम यह है कि महाराज के आब और ताब के आगे अच्छे-अच्छे मंत्री भी अपने आप को नतमस्तक कर लेते हैं। इसका नजारा पिछले 2 सालों से तो स्वतंत्रता दिवस पर देखने को मिल रहा है। दरअसल, सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने की जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि महाराज वाले जिले में प्रभारी मंत्री झंडारोहण करने से पहले ही बीमार हो जाते हैं। यह दृश्य पिछले साल भी देखा गया और इस साल भी। प्रभारी मंत्री के बीमार पड़ने पर कलेक्टर को झंडारोहण करना पड़ा। अब इसे विडंबना समझें या महाराज का आब और ताब की स्वतंत्रता दिवस पर प्रभारी मंत्री बीमार हो जा रहे हैं। वैसे जिले में यह कहा जाता है कि महाराज चाहती हैं कि मैं नहीं तो जिले में और कोई नेता झंडावंदन नहीं कर सकता। आज भले ही राजा-रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन महाराज का राजसी ठाठबाट अब भी कायम है और उसी का परिणाम है कि उनके जिले में और कोई नेता ध्वजारोहण करने की हिमाकत नहीं करता।

जवाबदारी से मुंह मोड़ा

प्रदेश के गांवों के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग में इन दिनों अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। दरअसल, हाल ही में हुए एक ऑडिट में 400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाला सामने आने के बाद प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस अधिकारी पर इसकी जवाबदारी है, वे जवाब देने से कतरा रही हैं। दरअसल, जिस महिला अधिकारी की यहां बात हो रही है, वे 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। मैडम पहले भी एक मामले में काफी सुर्खियों में रही हैं। हालांकि मैडम का कहना है कि 400 करोड़ का यह घोटाला मेरे कार्यकाल का नहीं है। इसलिए मेरी जवाबदारी नहीं बनती है। उधर, जानकारों का कहना है कि मैडम के कार्यकाल में भले ही यह घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जवाबदारी बनती है कि वे इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। वहीं मैडम के जानने वाले कहते हैं कि वे बहुत घाघ हैं। वे ऊपर से जितनी मासूम दिखती हैं, अंदर से उतनी ही शातिर हैं। इसलिए उनसे इस मामले में कुछ भी उगलवाना टेढ़ी खीर साबित होगा।

दो पाटों में फंसे साहब

2010 बैच के एक आईएएस अधिकारी इन दिनों दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच फंसे हुए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। दरअसल, साहब विवादों का गढ़ बने एक संघ में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थ हैं। इस संघ में काला कारोबार करने वाले अफसरों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिसने भी इन्हें उखाड़ने की कोशिश की, वह खुद बाहर चला गया। महाप्रबंधक के पद पर बैठे ऐसे ही एक अधिकारी को लेकर संघ के बड़े साहब और प्रशासन के बड़े साहब के बीच ठनी हुई है। बड़े साहब का प्रबंध निदेशक को निर्देश है कि उक्त महाप्रबंधक को संघ से बाहर करो। वहीं उक्त महाप्रबंधक संघ के बड़े साहब का चेहा है। ऐसे में साहब की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर साहब प्रशासनिक मुखिया की बात मानते हैं तो संघ के बड़े साहब नाराज हो जाएंगे, जो भविष्य में प्रशासनिक मुखिया बन सकते हैं। वहीं बड़े साहब की बात मानते हैं तो प्रशासनिक मुखिया नाराज हो जाएंगे। ऐसे में साहब की समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें।

मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे एक साल पहले यानी इस साल नवंबर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होना है। जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल इकाई के केंद्रीय प्रभारी से हटा दिया है और उनकी जगह सुनील बंसल को नियुक्त किया गया है, उससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि आलाकमान आने वाले दिनों में कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि यह बड़ी जिम्मेदारी मप्र भाजपा अध्यक्ष की हो सकती है। गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय मप्र की राजनीति को बारीकी से जानते हैं। 2018 में भाजपा को मिली हार के बाद आलाकमान की कोशिश है कि 2023 के चुनाव से पहले संगठन की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जाए, जिसका पूरे प्रदेश में एकसमान पकड़ हो। उस फ्रेम में कैलाश विजयवर्गीय फिट बैठते हैं।

गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय मप्र के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें मप्र भाजपा सरकार और संगठन का संकटमोचक भी कहा जाता रहा है। यही नहीं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के प्रिय नेता हैं। विजयवर्गीय भाजपा के साथ ही संघ के नेताओं के बीच भी अच्छी हैसियत रखते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मिशन 2023 में उतरने से पहले पार्टी आलाकमान इस साल नवंबर में विजयवर्गीय को मप्र भाजपा की कमान सौंप सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दूसरे कार्यकाल के दौरान जैसे ही दोनों नेताओं के बीच दरार बढ़ी, विजयवर्गीय को केंद्र में बुलाया लिया गया और हरियाणा का प्रभारी बनाया दिया गया। बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन अब बंगाल में हार के बाद मप्र में उनकी वापसी ने राज्य की राजनीति में फेरबदल की बातचीत के लिए मंच तैयार कर दिया है। दोनों नेताओं ने एक लंबा सफर तय किया है, एबीवीपी में छात्र नेताओं के रूप में, युवा मोर्चा में वे पारिवारिक संबंध भी साझा करते हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद से शिवराज थोड़े कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान की नई दोस्ती प्रदेश भाजपा में एक नया समीकरण बना सकती है। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल की जवाबदारी से फारिग कर दिए गए, क्या खबर बस इतनी है? मप्र की राजनीति में इस वक्त का बड़ा सवाल ये है कि बंगाल से छुट्टी के बहुत पहले ही वहां से अपनी अटैची बांध चुके कैलाश विजयवर्गीय का संगठन की जवाबदारी से मुक्त होना मप्र की सियासत पर क्या और कितना असर दिखाएगा? इसकी एक बानगी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन पर कैलाश



कैलाश को मप्र का ताज!

मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद

विजयवर्गीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद सिपाही हैं। शाह 2014 में भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो उन्होंने विजयवर्गीय को वहां बुलाया। 2014 में विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें हरियाणा का भाजपा प्रभारी नियुक्त किया गया था। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने जिन पहले चार राज्यों में जीत हासिल की, उनमें एक हरियाणा भी था, जहां उस वर्ष पहली बार भाजपा की सरकार बनी। हरियाणा में विजयवर्गीय सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम सिंह इंसा को भाजपा का समर्थन करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। राम रहीम के समर्थन को भाजपा की जीत के प्रमुख कारणों में से एक माना गया। आक्रामक संगठनात्मक कौशल रखने वाले नेता माने जाने वाले विजयवर्गीय शाह के भरोसेमंद आदमी बन गए, जिन्हें तत्कालीन भाजपा प्रमुख ने भाजपा की एक बड़ी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी और यह थी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा होने की रणनीति। 2015 में विजयवर्गीय के पार्टी प्रभारी बनने के साथ भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान न केवल पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि पार्टी का वोट शेयर भी 10 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। हालांकि भाजपा को 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसने 77 सीटों पर जीत हासिल की जो 2016 में जीती तीन सीटों के मुकाबले काफी ज्यादा है और वोट शेयर भी 38 प्रतिशत के करीब रहा। शाह का विजयवर्गीय पर इतना भरोसा है कि जहां जरूरत पड़ी वहां उन्हें काम पर लगाया। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि विजयवर्गीय को मप्र भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है।

विजयवर्गीय का बेबाक बयान है। जिसमें उन्होंने ग्वालियर-चंबल अंचल में पार्टी को मिली हार को भाजपा के लिए अलार्मिंग बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। इसलिए यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल से विदा होने के बाद कैलाश क्या मप्र सक्रिय होंगे? क्या वे अपनी बेबाक बयानबाजी से मप्र भाजपा संगठन और सरकार की खिंचाई करते रहेंगे। जहां हमारी ताकत बढ़ी वहां हारे क्यों? बंगाल के प्रभार से कैलाश विजयवर्गीय की विदाई भले एक दिन पहले हुई, लेकिन मप्र में उन्होंने अपनी सक्रियता काफी पहले से बढ़ा दी थी। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा के पहले से कमजोर हुए प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा बेबाकी से बयान कैलाश विजयवर्गीय के ही आए। ग्वालियर-चंबल अंचल में पार्टी की हार पर विजयवर्गीय ने कहा था कि इस हार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये पार्टी के लिए अलार्मिंग

है। विजयवर्गीय ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए सरकार और संगठन की कार्यशैली पर सीधे-सीधे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि हम वहां एक ग्रुप के आने से ताकतवर हुए थे, वहां हम अगर हारे तो क्यों हारे इस पर विचार करेंगे। विजयवर्गीय ने निकाय चुनाव में पार्टी को मिली हार को लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री शिवराज की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। विजयवर्गीय ने उन्हें सलाह दी कि कार्यकर्ताओं पर भी शिवराज को उतना ही विश्वास करना चाहिए। यदि कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते तो शायद यह गलती नहीं होती। अब पश्चिम बंगाल का प्रभार हट जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है क्या कैलाश वाकई पार्टी में नई जवाबदारी संभालेंगे।

● लोकेंद्र शर्मा

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए स्टेशनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए ग्रीन मेट्रो प्रणाली या ईको फ्रेंडली आधारित स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल, 100 पर्सेंट एलईडी लाइटिंग, बिजली की बचत, पानी की बचत, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, सोलर हीटर का इस्तेमाल, पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रेनों का आवागमन, प्लास्टिक फ्री, वेस्ट सेगरिगेशन, दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं और स्टेशन परिसर में ग्रीन कवर को बढ़ाने व ग्रीनरी को बचाने पर बल दिया जाएगा।

बता दें कि भोपाल में मेट्रो संचालन को लेकर 2024 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। सबसे पहले एम्स से सुभाष नगर तक प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। सात किलोमीटर के इस रूट में 450 करोड़ रुपए खर्च कर विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आठ मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यहां यात्रियों के लिए एटीएम, फूड कोर्ट, आटोमेटिक फेयर कलेक्शन समेत अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। हर स्टेशन पर ई-रिक्शा, पब्लिक बाइक शेयरिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस और पिकअप ड्राप जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। इसके अलावा स्टेशनों में सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, फुटपाथ, एस्केलेटर, आटोमेटिक फेयर कलेक्शन के साथ दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि सभी मेट्रो स्टेशनों को ग्रीन बिल्डिंग की प्लेटिनम रेटिंग के आधार पर बनाया जाएगा, यानी इन स्टेशनों पर बिजली का जितना उपयोग होगा, उतनी यह स्वयं जनरेट करेंगे। इसके लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बरसात के पानी को संग्रहित किया जाएगा।

मेट्रो स्टेशन का निर्माण मेट्रो कॉरिडोर के बीच लगभग 150 मीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, इसमें 22 मीटर का स्टेशन होगा शेष भाग प्रवेश और निकास सहित टिकट काउंटर इत्यादि बनाए जाएंगे। स्टेशन पर विद्युतीकरण सहित ट्रेक इत्यादि का कार्य भी स्टेशन निर्माण करने वाली कंपनी करेगी। इसके अलावा स्टेशन पर पार्किंग इत्यादि की भी व्यवस्था करवाई जा सकती है। वहीं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन को अंडरग्राउण्ड पर भी जोड़कर बनाए जाने की भी रणनीति पर अमल करवाया जा सकता है।

रानी कमलापति स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन का इंटीरियर डेकोरेशन बाकी स्टेशनों से अलग होगा। यात्रियों को बैठने और लगेज कैरी करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं मिलेंगी। यहां स्टेशन का फ्रंट एलिवेशन भी दूसरे स्टेशनों से अधिक आकर्षक होगा। यहां पर आधुनिक लाइट से डेकोरेशन किया जाएगा।

मेट्रो स्टेशन में होंगी सारी सुविधाएं



280 पिलर तैयार, बिछाए जा रहे गार्डर

दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, यह निर्माण 90 फीसदी पूर्ण हो चुका है, इसमें गणेश मंदिर से डीआरएम चौराहा को जोड़ने के लिए निर्माण तीसरी लाइन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जाना शेष है। इसके अलावा सुभाष नगर क्रासिंग पर भी लंबा सेतु बनना शेष है। इस सात किमी लंबे कॉरिडोर में 280 पिलरों को तैयार किया गया है। इनमें 70 फीसदी पिलरों में गार्डर लांच भी किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि भोपाल के लिए मेट्रो कार का टैंडर भी तय हो गया है। सूत्रों के अनुसार एमपीएमआरसीएल की ओर से निकाले गए टैंडर में जिस कंपनी ने सबसे कम दरें भरीं उसे जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जा रहा है। करार के अनुसार भोपाल में करीब सेमी हाईस्पीड मेट्रो कार चलेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है।

विशेष अवसरों पर थीम के अनुसार सजावट होगी। मेट्रो स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन के भीतर और बाहर आने-जाने के लिए स्काई वाक बनाया जाएगा। एम्स से सुभाष नगर फाटक (आजाद नगर बस्ती तक) मेट्रो कॉरिडोर पर आठ स्टेशन बनाए जा रहे हैं, इनमें एम्स, अलकापुरी, हबीबगंज नाका, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, डीबी माल, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर चिन्हित किए गए हैं। हालांकि यूआरसी कंपनी चेन्नई द्वारा इन आठ स्टेशनों में से शहर के बीच के प्रमुख पांच स्टेशनों का पहले चरण में निर्माण करने के लिए चुना है, शेष तीन स्टेशनों हबीबगंज नाका, अलकापुरी, एम्स के स्टेशनों का निर्माण दूसरे चरण में शुरू किए जाएंगे।

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 7 किमी पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। इस चरण में मेट्रो रेल का संचालन सितंबर 2023 में प्रारंभ कर दिया जाएगा। एमपीएमआरसीएल के अनुसार प्रायोरिटी कॉरिडोर के 6 किमी वायडक्ट का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य करीब 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 8 स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। सभी स्टेशनों के लिए कार्यादेश किया जा चुका है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। एमपीएमआरसीएल

की आधिकारिक वेबसाइट पर भोपाल मेट्रो रेल का संचालन 430 दिनों में प्रारंभ करने का दावा किया जा रहा है। भोपाल डिपो के सिविल और ईएंडएम वर्क्स का कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मेट्रो रेल के लिए विद्युत आपूर्ति और कर्षण पैकेज के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग और दूरसंचार की प्रणाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विभिन्न ट्रेक सामग्री की आपूर्ति तथा इंस्टालेशन पैकेज के लिए भी प्रक्रियाएं चालू हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए भी टैंडर हो चुके हैं।

भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ट्रेक और स्टेशन निर्माण के साथ ही भोपाल मेट्रो कार तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके लिए दिल्ली मेट्रॉ रैपिड रेल के कोच निर्माण करने वाली कंपनी को ही ठेका मिला है। न्यूनतम 3248 करोड़ की बोली लगाकर कंपनी ने मद्र के दोनों शहरों यानी इंदौर और भोपाल के मेट्रो कोच निर्माण का ठेका प्राप्त किया है। अधिकारियों के अनुसार अब भोपाल मेट्रो का ट्रेन सेट तैयार होने का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि देश के अन्य स्थानों की तुलना में भोपाल मेट्रो का ट्रेन सेट बेहतर और अत्याधुनिक होगा।

● विकास दुबे

51 फीसदी का लक्ष्य



पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस मिशन 2023 पर हो गया है। मतदाताओं को साधने के लिए दोनों पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में 51 फीसदी वोट पाने के लिए भाजपा का पूरा फोकस 1-1 वोट पर है। यानी पार्टी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। खासकर ओबीसी और एससी-एसटी पर पार्टी का पूरा फोकस है।

20 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक वोट पाने के बाद भी सत्ता से दूर रही भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक-एक वोट पर फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनाकर नेताओं को मोर्चे पर तैनात करना शुरू कर दिया है। उधर, पंचायत और निकाय चुनाव के परिणाम की समीक्षा के बाद संघ, संगठन और सरकार ने कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जमावट शुरू कर दी है। यही नहीं विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा अपने सभी मोर्चों को सक्रिय कर आगामी रणनीति को लेकर प्रशिक्षित करेगी। हर मोर्चे पर भाजपा मप्र की किलेबंदी करेगी। हर वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की रणनीति को आगे बढ़ाने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हर मोर्चे के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर पार्टी की रीति और नीति के हिसाब से व्यूह रचना की जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाकर मिशन 2023 को धार दे रहे हैं। पार्टी ने हर मोर्चे को मिशन की रणनीति सौंप दी है। इसके तहत युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और ओबीसी वर्ग पर सबसे अधिक फोकस करना है। इसके लिए आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन मिलकर इन वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ताकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल सके।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में 51 फीसदी वोट पाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पार्टी का फोकस आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक पर है। हालांकि भाजपा के साथ कांग्रेस भी इस वोट बैंक के लिए प्रयास कर रही है। मप्र के 22 फीसदी आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा और कांग्रेस

मोर्च पर तैनात होगा संघ

मिशन 2023 के मद्देनजर मप्र चुनावी मोड में आ चुका है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणामों का आंकलन कर संघ ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मैदानी जमावट पर काम शुरू कर दिया है। हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला संघ इस बार कई मोर्चे पर फ्रंट पर रहकर भाजपा के लिए चुनावी काम करेगा। इसके लिए इस बार हार्ड हिंदुत्ववादी और सेवा संगठनों को फ्रंट मोर्चे पर तैनाती की तैयारी की गई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए संघ ने इस बार समय से पहले चुनावी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। खास तौर पर कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में संघ के प्रचारक, समयदानी और विस्तारकों की विशेष टोलियों को भेजा जाएगा। संघ के ये वालंटियर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे और क्षेत्र में पार्टी की मौजूदा स्थिति का फीडबैक भी देंगे। जिलों में बढ़ती गुटबाजी को नेताओं के बगावती तेवरों को साधने का रास्ता भी सुझाएंगे। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संघ इस बार सुनियोजित रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत संघ ने हाल ही में अपने नेटवर्क को नए सिरे से पुनर्गठित कर लहार को मध्यभारत प्रांत में संघ का नया जिला बनाकर जिला प्रचारक की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा करीब डेढ़-दो दर्जन जिलों में प्रचारकों के बीच नए सिरे से कामकाज का विभाजन कर दिया है। शुरुआती दौर में जिन जिलों पर फोकस किया गया है उनमें से ज्यादातर ग्वालियर-चंबल संभाग क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

ने जमावट शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि प्रदेश में आदिवासी जिस ओर रहते हैं, उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2018 में आदिवासियों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया था। ऐसे में मिशन 2023 से पहले भाजपा और कांग्रेस की कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए। भाजपा की तरफ से संघ, संगठन और सरकार सक्रिय हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मप्र की सियासत में अभी तक का गणित कहता है कि प्रदेश की इस 22 प्रतिशत आबादी को जिसने साध लिया, सरकार उसी की बनती है। प्रदेश में अजजा के लिए आरक्षित 47 सीट हैं। इसके अलावा 35 सीट पर आदिवासी वोटर्स की संख्या 50 हजार से ज्यादा है। 82 सीट पर आदिवासी वोट अहम हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 करोड़ आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अभी से ताकत लगानी शुरू कर दी है। भाजपा में तीन मोर्चे संघ, संगठन और सरकार सक्रिय हैं तो कांग्रेस ने अपने आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारा है।

भाजपा ने कांग्रेस सरकार को वर्ष 2003 में हिंदू संगम के बाद उखाड़ फेंका था। पार्टी ने 41 में से एकतरफा 37 सीट हथियाकर दो तिहाई बहुमत पाया था। भाजपा अब अजजा की आरक्षित 47 सीट में से 40 जीतने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। भाजपा ने सालभर के आयोजनों का कैलेंडर बनाया है। संघ लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। वहीं एक साल में भाजपा ने आदिवासी वर्ग में पैठ के लिए बड़े आयोजन किए। बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन हुआ। टंट्या मामा की शहादत दिवस पर अमृत महोत्सव मनाया। दो लाख आदिवासी भोपाल में एकत्र हुए। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन

किया। टंट्या मामा की प्रतिमा लगाई गई है। गौरतलब है कि 2018 में कांग्रेस ने अजजा के लिए आरक्षित 47 में से 31 सीट जीती थी। इस वोट बैंक को सहेजने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं की टीम गठित की है। आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम को बनाया गया है। मरकाम प्रदेश के 89 में से अधिकांश ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि आदिवासी वर्ग की कभी भाजपा हितैषी नहीं रही, जबकि कांग्रेस ने कल्याण के कई कदम उठाए। आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मनमोहन सरकार ने 2006 में नियम बनाकर लागू किया, जिसे 16 साल बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार लागू नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हम उठाएंगे। कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों का साहूकारों से लिया गया कर्ज माफ करने की जो योजना बनाई थी, कांग्रेस सरकार आने पर उसके क्रियान्वयन का वादा पार्टी करेगी। दिग्विजय सिंह की दो बार सरकार बनाने में आदिवासियों की अहम भूमिका रही थी। 1993 में अजजा वर्ग की 52 और 1998 में 50 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं।

प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव निपटने के बाद भाजपा और कांग्रेस मिशन मोड में नजर आने लगी है। दोनों पार्टियों का अगला टारगेट 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने पंचायत और निकाय चुनाव की समीक्षा कर संगठन और नेताओं पर नकेल कसने की तैयारी कर दी है। गौरतलब है कि उपरोक्त चुनावों में दोनों पार्टियों के संगठन में बिखराव और नेताओं में तालमेल का अभाव नजर आए। ऐसे में खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

गौरतलब है कि स्थानीय सरकार के चुनावों के बाद अब भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने बूथ नेटवर्क को मजबूत करने के साथ ही भीतरी असंतोष को थामने कसावट का डोज देना तय किया है, तो कांग्रेस ने कोर-एरिया को और मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उधर, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के जीते उम्मीदवारों का शपथग्रहण जारी है। इस बीच



कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पत्नी की जगह पति हावी दिखाई दिए। इस कारण पार्टी की छवि खराब हुई है। अब पार्टी ऐसे नेताओं पर नकेल कसेगी।

इस बार विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है कि ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जहां भाजपा पंचायत और निकाय चुनाव की समीक्षा करके मैदानी मोर्चे पर सक्रिय होने जा रही है वहीं कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में लगातार कई बैठकें कर चुकी है। सूत्रों की मानें तो इन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं को ही 2023 में विधानसभा के टिकट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। संगठन के कामकाज के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं, विधायकों को यह भी हिदायत दी गई है कि क्षेत्र में जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और सरकार की रीति-नीति लोगों तक पहुंचाने का काम करें, उनकी नाराजगी दूर करें। वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि संगठन के काम में पुअर परफॉर्मेंस करने वाले नेताओं पर पार्टी एक्शन लेगी। इस पूरी कवायद पर भाजपा नेताओं का कहना है कि बैठक, काम का वितरण और उसके बाद फीडबैक लेना भाजपा की कार्य पद्धति है। संगठन की ओर से सौंपे गए दायित्वों को सभी को पूरा करना है। यानि भाजपा 2023 के चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।

प्रदेश भाजपा ने स्थानीय चुनाव के हिसाब से

आंकलन शुरू कर दिया है। कटनी, सीधी, सिंगरौली सहित कुछ जगहों पर परिणाम ठीक नहीं आने के बाद वरिष्ठ नेताओं की नजरें इन इलाकों को लेकर टेढ़ी हो गई हैं। क्षत्रप नेताओं को लेकर भी संगठन नाराज है, क्योंकि टिकट वितरण के समय इन क्षत्रपों ने ही दबाव बनाया था। इन इलाकों को लेकर संगठन कसावट की रणनीति तैयार कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आने वाले दिनों में इन इलाकों सहित दूसरे खराब परफॉर्मेंस वाले क्षेत्रों को लेकर कसावट पर काम करेंगे। जिन बूथों पर अच्छे वोट नहीं मिले हैं, उनको भी चिन्हांकित किया जा रहा है ताकि अलग से ध्यान दिया जा सके।

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अब भाजपा से कदम से कदम मिलाकर मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन इससे पहले पार्टी अपनी अंदरूनी खामियों को दूर करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के खेल के बाद अब भाजपा की नजरें कांग्रेस के चुनिंदा विधायकों पर टिक गई हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रॉस वोटिंग करने वाले आदिवासी विधायकों को रडार पर लिया गया है। इसमें अभी केवल बैकग्राउंड तैयारी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस स्थानीय चुनाव में मतदान को लेकर उत्साहित है। पार्टी का मानना है कि उसे बहुमत मिला है, लेकिन जहां कम वोट प्रतिशत मिला वहां को लेकर रणनीति बनाई जा रही है।

● कुमार राजेन्द्र

एससी-एसटी वोट बैंक पर फोकस

भाजपा का फोकस अब आदिवासी और अनुसूचित जाति पर होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग में पैट और बढ़ाना है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन दो वर्ग के रुठने के कारण ही भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी। यह निष्कर्ष भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेताओं के बीच मंथन में निकला है। जाहिर है सत्ता बरकरार रखने की मंशा लेकर भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में पैट बढ़ाने की कवायद तेज करेगी। 2003 से 2013 तक के चुनाव में उसे सत्ता सुख भी तभी मिला, जब एससी वर्ग का साथ मिला, वहीं 2018 में इस वर्ग के मोहभंग की कीमत सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी। 230 सीटों की मप्र विधानसभा में 35 सीटें एससी वर्ग और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में अजा की 35 सीटों में भाजपा की 28 सीटें घटकर 18 पर पहुंच गई थी। वहीं अजजा की 47 सीटों में भाजपा की संख्या 32 से घटकर 16 पर आ गई थी। वहीं कांग्रेस की सीटें इस वर्ग में 14 से 30 पर पहुंच गई थी। यही वजह है कि कुल 82 सीटों पर भाजपा अब फोकस बढ़ाएगी। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साफ समझ आ जाएगा कि भाजपा आदिवासी वोट बैंक पर इतना जोर क्यों दे रही है।

पिछले वर्ष केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने तथा उसका स्रोत बताने के लिए कहा गया था, जिसके माध्यम से उनके परिवार के किसी सदस्य ने कोई संपत्ति खरीदी हो। अगर किसी अधिकारी ने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अचल संपत्ति खरीदी है, तो उसका भी विवरण देना था। लेकिन इस संबंध में लोकसेवकों की उदासीनता ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। बहरहाल, कई अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करना व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है। हालांकि नौकरी करने वाले तक तो ठीक है, लेकिन उनके परिवार की संपत्ति की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पब्लिक सर्वेंट यानी लोकसेवक की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है और नियुक्ति के उपरांत वे राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन सेवक जब अपना सेवक धर्म भूलकर जनता के मालिक बन जाते हैं, तब उन पर कठोर नियंत्रण जरूरी हो जाता है। बता दें कि नौकरशाही एक शक्ति संपन्न संस्था है और शक्ति सदैव सीमा का उल्लंघन करती है। लोकाचार में यह माना भी जाता है कि शक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसीलिए प्रशासन पर नियंत्रण बाबत अनेक नियम, विनियम, अधिनियम तथा लोकसेवक आचरण संहिता बनाया गया है। उसी आचार संहिता में कहा गया है कि लोकसेवक किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेगा, किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य व्यापार करता है तो उसकी जानकारी साझा करेगा, अपने संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा आदि। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद हर साल करीब डेढ़ सौ आईएएस अफसर अपनी संपत्ति का वार्षिक विवरण नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनके नाम संबंधित वेबसाइट पर डाले जाते हैं और विजिलेंस क्लियरेंस रोकने का प्रविधान किया गया है, लेकिन ये उपाय असरदार नहीं हो रहे हैं। अब सरकार ने नए और कड़े उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं। इस बाबत सुझाव भी मांगे जा रहे हैं जिसमें प्रोन्नति रोकने से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं करने जैसे प्रविधानों पर भी विचार किया जा रहा है।

लोकसेवकों के मात्र निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी मूल्यां और उनकी नैतिकता का संकलन होना अनिवार्य है, क्योंकि अधिकारी लोकसेवक के साथ समाज का आदर्श व्यक्ति भी होता है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन वहीं यदि अधिकारी अगर भ्रष्ट और धन कुबेर बनने की लालसा रखता हो तो



भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल

दंड का प्रचार-प्रसार

कुछ समय पहले सरकार ने भ्रष्ट नौकरशाहों पर सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें समय पूर्व ही सेवानिवृत्त कर दिया था। वास्तव में यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भ्रष्टाचार को कम करने की ओर इंगित करता है। प्रतिवर्ष कई हजार सरकारी अधिकारी दंडित होते हैं, किंतु उनके नामों और कारनामों का सही तरह से मीडिया और इंटरनेट मीडिया में न प्रदर्शित करने के कारण लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है कि सरकारी नौकरी में अधिकारी दंडित भी होते हैं। वास्तव में लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी नौकरी पूर्णतया सुरक्षित प्रकार की है। लिहाजा अगर दंडित अधिकारियों को उचित रूप से उनके नाम और कारनामों को प्रचारित किया जाए तो लोकसेवक शायद अपना भ्रष्ट रवैया बदल सकते हैं। लगातार प्रशासन की जवाबदेहिता को बदलने की कोशिश की जाती रही है, किंतु यह अभी भी अपने उचित स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है। इसलिए नौकरशाही को चाहिए कि वह लोकहितवादी तथा जन कल्याणकारी भावना को प्राथमिकता दे। साथ ही नौकरशाही में प्रवेश के तरीकों तथा प्रशिक्षण में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। प्रवेश के समय मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य होना चाहिए, ताकि इनकी मनोस्थिति का पता चल सके। इससे देश के निचले स्तर से भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा तथा देश में समरसता व राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी। साथ ही सुशासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत भी है।

समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए लोकसेवक को अपनी छवि साफ-सुथरी रखनी चाहिए। लेकिन चिंता की बात है कि कार्मिक मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार पिछले साल 158 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण ही नहीं दिया। जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 146 तथा 2019 में 128 थी। इनमें 64 अफसर ऐसे थे, जिन्होंने लगातार दो साल और 44 अफसरों ने तो लगातार तीन साल तथा 32 अफसरों ने तीन साल से भी अधिक समय से संपत्ति का वार्षिक विवरण नहीं दिया है। इनमें सबसे अधिक मद्रास केंद्र के आईएएस अधिकारी हैं। सरकार की ओर से जारी की गई संबंधित रिपोर्ट के अनुसार जिन आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है उनमें 32 मद्रास केंद्र, 16 उप्र, 14 पंजाब तथा 12 ओडिशा केंद्र के हैं।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि अफसर संपत्ति का ब्यौरा देने से भयभीत हो रहे हैं? रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी हर साल अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। यह बात प्रणाली में गहरी खराबी की ओर इशारा करती है। बहरहाल अब जब इन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित ही यह एक नजीर बनेगा जो प्रशासन की स्वच्छता के लिए जरूरी साबित होगा। संपत्ति का विवरण देने बाबत हाल में कोई नियम नहीं बनाया गया है। नौकरशाहों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देने के ये नियम कार्मिक मंत्रालय ने दशकों पहले ही तैयार किए थे। लेकिन विवरण की सूचनाओं के प्रकार में कई बार बदलाव किए गए। इसके बावजूद इसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

● सुनील सिंह

मप्र में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पूरे होते ही कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जिलों के संगठन प्रभारी बदल दिए हैं। जिलों के नए इंचार्ज को पीसीसी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रभार के जिलों में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके संगठन में नए एक्टिव वर्कर्स को जोड़ें। पीसीसी चीफ ने माधवराव सिंधिया के करीबी रहे बालेंदु शुक्ल को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले मुरैना का प्रभारी बनाया है।

मप्र में हुए नगरीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में बढ़त मिली है। ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा नगर निगम में महापौर बनाने में कामयाब होने के बाद कांग्रेस कई जिलों में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष बनाने में सफल हुई है। शहरी क्षेत्रों में बढ़त मिलने से उत्साहित कांग्रेस ने अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिलों में नियुक्त किए गए कांग्रेस के संगठन प्रभारी अपनी रिपोर्ट सीधे पीसीसी चीफ को देंगे। इसके साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडलम, सेक्टर के गठन के संबंध में अपडेट जानकारी लेकर गठन के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराना और जहां पर मंडलम सेक्टर का पूर्ण गठन हो गया हो उसका सत्यापन करना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी।

कमलनाथ जिला प्रभारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में बाल कांग्रेस का गठन कर एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन के नाम प्रदेश कांग्रेस को भेजने के लिए कहा है। पीसीसी चीफ ने नेताओं को निर्देश दिए हैं कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों से कांग्रेस के परिवारजनों के बच्चों को भी बाल कांग्रेस का सदस्य बनाएं। पीसीसी चीफ ने अधिकांश नेताओं को उनके पड़ोसी जिलों की जिम्मेदारी दी है ताकि प्रभार के जिलों में आसानी से जाकर संगठन खड़ा कर सकें। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर (मुरैना) को श्योपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के दतिया जिले का प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर महल की करीबी रहें रश्मि पवार शर्मा को शिवपुरी, पूर्व मंत्री तरुण भनोट को बालाघाट और मुकेश नायक को राजधानी भोपाल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं बृजबिहारी पटेल को अनूपपुर, उमरिया और मुजीब कुरैशी को मंदसौर, नीमच का इंचार्ज बनाया गया है।

मप्र के 52 जिलों में से 13 ऐसे हैं, जहां से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। इन जिलों में 42 विधानसभा की सीटें हैं अगले साल



2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस

इन्हें बनाया गया जिलों का प्रभारी

श्योपुर-दिनेश गुर्जर, मुरैना-बालेंदु शुक्ला, भिंड-वासुदेव शर्मा, ग्वालियर-महेंद्र सिंह चौहान, दतिया-कमलेश्वर पटेल, शिवपुरी-रश्मि पवार शर्मा, गुना-रघु परमार, अशोकनगर-रामसेवक गुर्जर, सागर-अवनीश भार्गव, टीकमगढ़-चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, निवाड़ी-दामोदर यादव, छतरपुर-नारायण प्रजापति, दमोह-धर्मेश घई, पन्ना-मनोज त्रिवेदी, सतना-प्रियदर्शन गौर, रीवा-प्रताप भानु शर्मा, सीधी-बुजभूषण शुक्ला, सिंगरौली-आनंद अहिरवर, शहडोल-राजेंद्र मिश्रा, अनूपपुर-बृहबिहारी पटेल, उमरिया-बृहबिहारी पटेल, कटनी-रमेश चौधरी, जबलपुर-सुनील जैन, डिंडौरी-कदीन सोनी, मंडला-दिनेश यादव, बालाघाट-तरुण भनोट, सिवनी-गंभीर सिंह, नरसिंहपुर-संजय सिंह परिहार, छिंदवाड़ा-नरेश सराफ, नेहा सिंह, शेखर चौधरी, बैतूल-सविता दीवान शर्मा, हरदा-अजय ओझा, नर्मदापुरम-संजय शर्मा, रायसेन-कैलाश परमार, विदिशा-दीपचंद यादव, भोपाल-मुकेश नायक, सीहोर-सैय्यद साजिद अली, राजगढ़-राजकुमार पटेल, आगर-नूरी खान, शाजापुर-जय प्रकाश शास्त्री, देवास-योगेश यादव, खंडवा-कैलाश कुंडल, खरगोन-ठाकुर जय सिंह, बड़वानी-अर्चना जायसवाल, अलीराजपुर-हेमंत पाल, धार-निर्मला मेहता, इंदौर-महेंद्र जोशी, उज्जैन-शोभा ओझा, रतलाम-अमिताभ मंडलोई, मंदसौर-मुजीब कुरैशी, नीमच-मुजीब कुरैशी।

विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए पार्टी ने इन जिलों में वरिष्ठ नेताओं को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया,

अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, अजय सिंह, राजमणि पटेल सहित अन्य नेता शामिल हैं। नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन आया है। खंडवा में मांधाता, बुरहानपुर में नेपानगर, मंदसौर में सुवासरा और निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर सीट पर चुनाव हारने के बाद इन जिलों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है।

मप्र के नगरीय निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के निकाय चुनाव में प्रदर्शन को देखते हुए संघ ने इस बार हार्ड हिंदुत्ववादी और सेवा संगठनों की मोर्चा पर तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें खासतौर पर कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों पर फोकस किया जा रहा है। इन क्षेत्र में संघ के प्रचारकों और विस्तारकों की टोलियों को भेजे जाने की प्लानिंग है। संघ के लोग भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे और क्षेत्र में पार्टी की मौजूदा स्थिति का फीडबैक भी देंगे। इसके अलावा जिन जिलों में नेताओं में आपसी गुटबाजी ज्यादा है या जो लोग बगावत करने के मूड में हैं उन्हें साधने की कोशिश करेंगे।

मिशन 2023 को देखते हुए हाल ही में संघ ने अपने नेटवर्क को नए सिरे से पुनर्गठित कर लहार को मध्यभारत प्रांत में संघ का नया जिला बनाकर जिला प्रचारक की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा करीब डेढ़ से दो दर्जन जिलों में प्रचारकों के बीच नए सिरे से कामकाज का विभाजन भी कर दिया है। शुरुआती दौर में जिन जिलों पर फोकस किया गया है, उनमें से ज्यादातर ग्वालियर-चंबल संभाग क्षेत्र के अंतर्गत हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। इन जिलों में संघ ने नए सिरे से प्रचारकों की जमावट की है।

● अरविंद नारद

म प्र अब धीरे-धीरे विवादित बाबाओं की शरण स्थली बन गया है। रेप से लेकर कई बड़े गंभीर आरोप इन बाबाओं पर हैं। कई बाबा सलाखों के पीछे हैं तो कई के केस कोर्ट में चल रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से ये बाबा इतने बेखौफ हो गए हैं कि धर्म और आस्था की आड़ में राजनीति और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है।

मप्र में विवादित और फर्जी बाबाओं की लंबी फेहरिस्त है। रेप केस में मिर्ची बाबा के सलाखों के पीछे जाने से अब कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। ये बाबा भोली-भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर उन्हें लूट भी रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। वोट बैंक के चक्कर में इन्हें नेताओं और राजनीतिक दलों का संरक्षण मिला हुआ है।

तारीख-9 अगस्त 2022, स्थान-भोपाल- वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची वाले बाबा को भोपाल पुलिस ने रेप के आरोप में ग्वालियर में आधी रात में एक होटल से गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोप है कि मिर्ची बाबा निसंतान महिलाओं को तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ का झांसा देकर उनका शोषण कर रहा था।

तारीख-नवंबर 2020, स्थान-देवास- खुद को भगवान का अवतार बताने वाले बाबा मंगलनाम पर मूक बाधिर से रेप का आरोप है। पुलिस ने बाबा के दो आश्रम से 6 युवतियों को मुक्त कराया था। यह कार्रवाई चूना खदान कांकड़ और जामगोद पहाड़ी पर हुई। रेप का यह मामला तब सामने आया, जब मूक बाधिर युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। आश्रम से पुलिस को हिरण का एक सींग, एक पहाड़ी कछुआ और शक्तिवर्धक टैबलेट का एक रैपर मिला था।

तारीख-2013, स्थान-भोपाल- आसाराम बापू पर साल 2013 में अपनी नाबालिग शिष्या से रेप का आरोप है। वह पिछले कई साल से जोधपुर जेल में बंद हैं। उनका भोपाल में भी एक आलीशान आश्रम है। धर्म की आड़ में उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। उनके आश्रम का मुख्यालय अहमदाबाद में है। उन पर सबसे संगीन आरोप यही है कि वो आशीर्वाद देने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और रेप करते थे। उन पर बड़े स्तर पर जमीन हड़पने के आरोप भी हैं।

तारीख-2020, स्थान-नरसिंहपुर- तेंदूखेड़ा तहसील के नंदिया बिलहारा गांव में बाबा धर्मेंद्र दास का आश्रम अय्याशी का अड्डा बन गया था। बाबा इसी आश्रम से गांजा भी सप्लाई करता था। खुद को भगवान के रूप में पेश कर वह लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता था। बाबा खुद को हनुमान जी का अवतार बताता था।

तारीख-2017, स्थान-अशोक नगर- आनंदपुर ट्रस्ट में ज्ञानदयालानंद चक्की वाले



विवादित बाबाओं की शरण स्थली बना मप्र

एक-दूसरे पर कीचड़

भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही इन बाबाओं को संरक्षण देती हैं। जब कोई फंस जाता है तो ये एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा भाजपा सरकार में बाबाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा सरकार में उन्हें जमीन एलॉट की गई। भाजपा सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा लेने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा मिर्ची बाबा कांग्रेस के बाबा थे। यह जनता जानती है। कम्प्यूटर बाबा से लेकर इन बाबाओं को कांग्रेस ने संरक्षण दिया यह सबको पता है। इसलिए कांग्रेस को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

बाबा पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर बाबा पर एफआईआर दर्ज की थी। दलितों की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास है। वैसे तो 2005 से अभी तक ट्रस्ट में ऐसी 11 घटनाएं हुईं, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इनमें अधिकांश शिकायतें छेड़छाड़ की हैं।

तारीख-नंबर 2022, स्थान-रायसेन- मामला मंडीदीप थाना क्षेत्र के ग्राम पोलाहा का है। उप्र के बांधवगढ़ निवासी फर्जी बाबा बच्चू जोशी, लवलेश गोस्वामी, मिथिलेश गोस्वामी,

विधायक गोस्वामी, गुलाब जोशी और रामस्वरूप गोस्वामी। ये भिक्षा मांगने पोलाहा गांव पहुंचे हुए थे। सभी फर्जी बाबा मनोज लौवंशी के घर पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का दावा कर 500 रुपए नगद और चांदी की पायल ले ली। गांव से रफूचक्कर होने पर ग्रामीणों ने मिलकर सभी बाबाओं की जमकर धुनाई लगाई।

तारीख-फरवरी 2021, स्थान-इंदौर- खुद को अघोरी तांत्रिक बाबा बताने वाले बाबा को महिलाओं से फोन पर अश्लील हरकत और गाली-गालोच करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इंदौर राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस से बाबा की शिकायत की थी। पुलिस ने बाबा का नंबर ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया था।

तारीख-जून 2022, स्थान-इंदौर- इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक झाड़फूक करने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुन्ना बाबा कोरोना जैसी बीमारी का बोलकर लोगों का इलाज कर रहा था। वो कर्बला मैदान में झाड़फूक के नाम पर लोगों को ठग रहा था।

तारीख-2021, स्थान-इंदौर- खुद को महामंडलेश्वर बताने वाले कम्प्यूटर बाबा का विवादों से लंबा नाता है। पहले भाजपा और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन उन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बड़ा आरोप है। इसी आरोप के चलते इंदौर में कम्प्यूटर बाबा के आश्रम पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

● बृजेश साहू

म प्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय पालने वाले किसानों को शिवराज सरकार ने 900 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। बावजूद इसके किसान बिना दूध वाली गाय-भैंस रखने को तैयार नहीं हैं। सरकार द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर सार्वजनिक स्थान पर पशु छोड़ता है और इससे किसी व्यक्ति, संपत्ति को नुकसान व ट्रैफिक में बाधा पहुंचती है तो 5 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बावजूद ज्यादातर सड़कों पर गाय का कब्जा है। मौजूदा समय में सड़कों पर गाय का झुंड बड़ी समस्या बन चुकी है।

आखिर गायों को घर से निकालने के लिए किसान क्यों मजबूर हो रहे हैं। मप्र की राजधानी भोपाल से करीब 55 किमी दूर बैरसिया तहसील के अंतर्गत ललरिया गांव को भूसा हब के नाम से भी जाना जाता है। यहां से पूरे देश में भूसे की आपूर्ति की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि किसान अपने पशुओं के लिए भूसे का इंतजाम न करते हुए पूरे देश में इसे ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि भूसा की बिक्री मुनाफे का धंधा है। ललरिया के आसपास के करीब 30 गांव के किसान यही सोचते हैं और सभी इसी धंधे में लगे हैं। यहां 1400 रुपए क्विंटल तक भूसा बिक जाता है और यहां से ट्रकों पर लदकर भूसा देश के अलग-अलग हिस्सों में मांग के अनुसार बेरोकटोक भेजा जाता है।

इसी गांव के प्रकाश ठाकुर के पास 6 भैंस थीं, जिसे उन्होंने पिछले एक साल में एक-एक करके बेच दी। सिर्फ एक भैंस अपने परिवार के दूध, घी के लिए बचाकर रखी है। इसी तरह रामबाई के पास 4 गायें थीं, जिसे उन्होंने सड़क पर छोड़ दी। रामबाई बताती हैं कि गाय दूध देना बंद कर दे तो उसे कोई नहीं खरीदता। गाय के पोषण के लिए चारा और भूसा चाहिए। जो अब बहुत महंगा हो चुका है और हमारे पहुंच से बाहर है। ललरिया के ही मुस्ताक भाई के पास 5 गायें थीं। अब केवल एक है, बाकी उन्होंने भी सड़क पर छोड़ दी। विनोद ठाकुर के पास 5 भैंस थी, अब केवल 2 है, बाकी उन्होंने अपनी खरीदी हुई रकम से 75 फीसदी कम कीमत में बेच दी। इन सभी पशुपालकों ने चारा और भूसे की महंगाई को इसका कारण बताया। एक गाय को पालने के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए खर्च बैठता है। चरनोई की



मवेशी छोड़ने को मजबूर किसान

जमीन नहीं है। सरकार ने अधिकतर जमीन पूंजीपतियों को या फिर पट्टे में दे दी। रही सही जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। इसलिए हरा चारा तो मिलता नहीं। 40 रुपए प्रति किलो भूसा खरीदना पड़ता है। एक गाय के खुराक के लिए प्रतिदिन 5 किलो भूसा और 25 रुपए की अन्य चीजें लगती हैं। अब महीनेभर का हिसाब लगा लीजिए। ऐसे में शिवराज सरकार का 900 रुपए कहां ठहरता है और वह भी केवल देसी गाय के लिए। इसी गांव के सबसे बड़े भूसा व्यापारी एक्का सेठ बताते हैं कि दरअसल यहां भूसे के कारोबार में ग्रामीणों को मजदूरी भरपूर मिल जाती है। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में उनके पिता ने बहुत छोटे स्तर पर भूसे का कारोबार शुरू किया था। उस वक्त यहां से सिर्फ इंदौर तक ही भूसा भेजा जाता था जो गत्ता बनाने के व्यवसाय में उपयोग किया जाता था। धीरे-धीरे इसका व्यावसायिक उपयोग बढ़ता गया। महाराष्ट्र में मशरूम उगाने के लिए भूसे का उपयोग होने लगा। इसके अलावा पशुओं के लिए भी किसान भूसे की मांग करते हैं। साथ ही गत्ता बनाने में ईंधन के लिए भी भूसे की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ी तो दाम भी बढ़ गए। इस तरह आसपास के सभी गांव के किसान भूसे का व्यवसाय करने लगे। इसका एक चेन बना है। जहां आढ़ती भूसे का ऑर्डर देते हैं। वहां से भूसे की आपूर्ति का ऑर्डर मिलता है। फिर किसानों के दरवाजे से भूसे की तौलाई कर गोदाम में लाया जाता है। इसके बाद ट्रक पर लादकर उसे भेजा जाता है।

उन्होंने कहा एक ट्रक में 150 क्विंटल भूसा

भरा जाता है, इसके लिए काफी मजदूरों की जरूरत पड़ती है, यहां से एक सीजन में प्रतिदिन 200 ट्रक निकलती है, जिसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी मिलती है। इसलिए यहां पलायन भी नहीं है। सभी को काम मिल जाता है। यहां आसपास के 30 गांवों के किसान अपना भूसा 400 रुपए प्रति एकड़ बेचने आते हैं, इसी तरह मजदूर भी यहां काम मांगने आते हैं और कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहां तक कि दिव्यांग को भी यहां काम मिल जाता है। उन्होंने कहा पहले पशुधन और जमीन से लोगों की प्रतिष्ठा आंकी जाती थी, अब नजरिया बदला है और दरवाजे पर खड़ी लग्जरी गाड़ी देखकर लोग प्रतिष्ठा का अनुमान लगाते हैं। लिहाजा यहां घरों के दरवाजे पर गाय नहीं, बल्कि लग्जरी गाड़ियां दिख जाएंगी और वह भी भूसे की कमाई से ही है। रबी और खरीफ के अलावा जायद फसल में भी भूसे का धंधा खूब चलता है। बरसात में बड़े करीने से उसे तिरपाल से ढककर रखा जाता है। एक्का सेठ ने यह भी बताया कि मशीनीकरण ने भी जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। जिसके चलते 70 फीसदी लोगों ने जानवरों को सड़कों पर छोड़ दिया है, जिनकी जान प्रायः सड़क दुर्घटना में चली जाती है। ललरिया के सरपंच बल्लू बताते हैं कि सबसे ज्यादा भूसा गेहूं की कटाई के बाद निकलता है। इसके बाद सरसों, मसूर धान जैसे फसलों से भी भूसा मिल जाता है। सरसों का भूसा मवेशी नहीं खाते इसलिए इसका तो व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

● अक्स ब्यूरो

जानवरों के लिए क्यों आया भूसे का संकट ?

उग्र के झांसी स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के क्रॉप प्रोडक्शन डिवीजन के प्रमुख सुनील तिवारी बताते हैं कि मशीनीकरण का उपयोग, खेती का विविधीकरण और हीट स्ट्रेस (फसलों की वहन क्षमता से अधिक गर्मी) मौजूदा चारे के कमी के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई से भूसा कम निकल रहा है। जिसके कारण जानवरों के लिए चारा कम पड़ रहा है। केवल भूसे का परिवहन इसकी समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में पशुओं के लिए चारा मांग के अनुपात में बहुत कम है। वहां तो भूसे की आपूर्ति होनी है लेकिन इसके व्यावसायिक उपयोग को रोका जाना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मौलाना मसूद खान बताते हैं कि 1975 तक 4-7 गाड़ी भूसा ही यहां से निकलता था लेकिन अब प्रतिदिन 200 ट्रक निकलता है। आज भी 80 फीसदी चारा पशुओं के लिए ही जाता है। शेष 20 फीसदी व्यावसायिक उपयोग के लिए।

नी ति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर ईकोनॉमी बनाने में मप्र के 550 बिलियन डॉलर के योगदान की जो घोषणा की है उस पर अमल भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने का निर्देश दे दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मप्र अभियान शुरू किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विकास का ऐसा खाका तैयार कर क्रियान्वित किया है कि मप्र आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश को मिल रही आर्थिक मजबूती के कारण ही मुख्यमंत्री ने इंडियन इकोनॉमी में मप्र के 550 बिलियन डॉलर के योगदान का ऐलान किया है।

मप्र की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत...

विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर ईकोनॉमी बनाने में मप्र के 550 बिलियन डॉलर के योगदान का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक विजन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत के निर्माण में नीति आयोग की बड़ी भूमिका है। नीति आयोग किस तरह राज्यों की ताकत बनता है, मप्र उसका प्रमुख उदाहरण है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश ने साल 2020 में ही आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप बना लिया था। मप्र ने साल 2021-22 में 19.74 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत पूंजीगत व्यय कर रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 48 हजार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अगले एक साल में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। हितग्राही मूलक योजनाओं में 100 प्रतिशत सेचुरेशन के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मप्र में सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग के रकबे में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मप्र में गेहूँ और धान के स्थान पर कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दाल, रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो-कुटकी, रामतिल, तिल,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोरोना संक्रमण के कारण मोदी के मिशन की गति थोड़ी सी धीमी हुई है। ऐसे में गत दिनों नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि मप्र भारत की अर्थव्यवस्था का सारथी बनेगा और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर ईकोनॉमी (अर्थव्यवस्था) बनाने में मप्र 550 बिलियन डॉलर का योगदान देगा। मुख्यमंत्री के इस कदम की देशभर में सराहना हो रही है।



समित की तैयारियां तेज

इनवेस्टर्स समित में आने वाले निवेश के प्रस्तावों को देखते हुए देवास में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। यहां इंडीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, कमर्शियल, रेसीडेंशियल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। देवास, सोनकच्छ, आधा व सीहोर तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की योजना है। वहीं पुणे के पिनेकेल उद्योग समूह ने 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दे रखे हैं। यह समूह पीथमपुर में 2000 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट लगाना चाहता है। इससे 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें बस और छोटी लाइट कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन होगा। जेएसडब्ल्यू पेंट समूह ने 1500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट व फोर्स मोर्टर्स समूह ने भी निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। जेके टायर समूह ने मुरैना में प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। 750 करोड़ से प्लांट लगेगा। हाइड्रोजन समूह एथेनॉल प्लांट लगाने की तैयारी में है। यह प्लांट सिवनी में लगना है। यह कंपनी लंदन की एथेना कैपिटल्स के साथ प्रदेश में बड़ा निवेश करेगी। इसी तरह एथेनॉल प्लांट के लिए तीन और कंपनियों से प्रारंभिक बातचीत हुई है। जल्द ही प्रस्ताव आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

मसाले, औषधीय फसलें, फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना में आईटीसी, पतंजलि, देहात जैसी प्राइवेट कंपनियों से 1 लाख 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि विविधीकरण में 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा देवारण्य योजना शुरू की गई है, जिसमें तीन वर्षों में 10 हजार हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिशन मोड में बांस उत्पादन किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मप्र में राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है।

खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल बीमा पंजीयन को राज्य के लैण्ड रिकार्ड से जोड़ा गया है, जिससे ओवर और डुप्लीकेट इन्श्योरेंस को रोकने में सफलता मिली है। साथ ही बीमा भुगतान में उपज आकलन के लिए सेटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के इन प्रभावी उपयोग से कृषि सेक्टर में लगभग 2500 करोड़ रुपए की बचत संभावित है। किसानों और राजस्व अमले को सुविधा के लिए ई-गिरदावरी एप्लीकेशन लागू कर दिया गया है। किसानों को अपनी उपज का विक्रय अपने घर से उचित मूल्य पर करने के लिए फार्म गेट एप भी विकसित

किया गया है। प्रदेश में कृषि यंत्रों में सब्सिडी का भुगतान ई-रूपी व्हाउचर से करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मप्र देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एडाप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान से आंगनवाड़ियों के कायाकल्प में जनता को जोड़ने का सफल अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-प्राइमरी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्च गुणवत्ता वाले 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पिछले वित्त वर्ष में लगभग 18 हजार 500 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की गई है। स्कूल में विद्यार्थियों को साइकल वितरण में भी ई-रूपी का उपयोग किया जाएगा।

नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रदेश में लगभग 600 करोड़ रुपए की अनुपयोगी संपत्तियों को चिन्हित कर मॉनेटाइज किया जा चुका है। जीआईएस और दूसरी तकनीकों का उपयोग कर सभी शहरों में विकास योजना तैयार की जा रही है और पीएम गतिशक्ति में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लॉजिस्टिक हब तैयार करने का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए नगर गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विकासखंड से लेकर राज्य स्तर तक आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने का कार्य किया जाएगा। नीति आयोग के सहयोग से मप्र नीति एवं योजना आयोग में एक वर्टिकल बना कर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव आंकलन हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 50 आकांक्षी विकासखंडों का निर्धारण कर उनके विकास का तंत्र विकसित किया गया है। प्रदेश में नई जल नीति और नई सहकारिता नीति का भी निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि मप्र में मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सत्र 2022-23 से एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में शुरू की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक कार्यक्रम और 6 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की हिन्दी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यार्थियों को पीएम गतिशक्ति परियोजना से



देशी-विदेशी निवेश पर फोकस

मप्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में 7 और 8 जनवरी 2023 को इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट को सक्सेस करने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने इनवेस्टर्स को रिझाने के लिए समिट के पहले प्रदेश के कई क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना की गिरफ्त से निकलकर प्रदेश निवेश की राह पर बढ़ने की तैयारी में है। जनवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश का नया रोलमैप तैयार हो जाएगा। 10 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं। इनमें से कुछ से प्रारंभिक सहमति बन गई है तो कुछ जगह को लेकर मशकत में लगी हैं। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन उद्योग से लेकर टैक्सटाइल-वेयरहाउसिंग जैसे परंपरागत उद्योगों तक में नए क्लस्टर आकार लेंगे। बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण विदेशी निवेश लगभग बंद हो गया था। ऐसे में बर्दियों के कारण मप्र विदेशी निवेश को लेकर खास काम नहीं कर रहा था। अब स्थिति बदलने से वापस विदेशी निवेश पर फोकस किया गया है।

जोड़ने के लिए एक सुनियोजित रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही प्रदेश में नई खेल संस्कृति का विकास किया जा रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि देशभक्ति और अनुशासन विकसित करने के लिए एनसीसी और एनएसएस में विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रदेश में कुल विद्यार्थियों का तीन प्रतिशत तक बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुशासन की दिशा में की जा रही पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विकासखंड से लेकर राज्य स्तर तक आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने का कार्य किया जाएगा। नीति आयोग के सहयोग से मप्र नीति एवं योजना आयोग में एक वर्टिकल बनाकर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव आंकलन हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 50 आकांक्षी विकासखंडों का निर्धारण कर उनके विकास का तंत्र विकसित किया गया है। प्रदेश में नई जल नीति और नई सहकारिता नीति का

भी निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को साकार करने की दिशा में मप्र कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम नेशनल एजेंडा के सभी लक्ष्य हासिल करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के प्रयास से अब मप्र ऑटोमोबाइल का हब बनेगा। मई में इंदौर में आयोजित ऑटो शो में इसकी संभावना सामने आई। एमपीआईडीसी के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश नीति बनाई गई है, उसी तरह अब ई-व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी। इससे इंदौर, पीथमपुर सहित मप्र में ऑटोमोबाइल के ई-सेक्टर में उद्योग लगाने या निवेश करने वाली कंपनियों को कई प्रकार की छूट व रियायतें दी जाएंगी। गौरतलब है कि देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 35 फीसदी हिस्सेदारी ऑटो इंडस्ट्री की है। देश की जीडीपी में ऑटोमोबाइल उद्योग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी कर रहा है। साथ ही यह क्षेत्र 3 करोड़ रोजगार भी दे रहा है।

● राकेश ग़ोवर

मप्र के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में मृतकों को पेंशन योजना की राशि दिए जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बीते एक साल में हजारों मृतक पेंशनधारियों के खातों में करीब 2 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है। अब मामला खुला तो अधिकारी एक-दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर हड़कंप मचने के बाद अब ग्राम पंचायतों के सचिवों को 7 दिन के अंदर यह राशि वापस जमा करने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय विभाग भोपाल की ओर से डिंडोरी जिले के सभी पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। इसमें सैंकड़ों ऐसे पेंशनधारी पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको पेंशन जारी की जा रही है। भौतिक सत्यापन में सैंकड़ों की तादात में मृत हितग्राहियों को पेंशन योजना की राशि जारी किए जाने के खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक अब करीब दो करोड़ रुपए की राशि मृत हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है। उसकी वसूली के लिए अब सामाजिक न्याय विभाग भोपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उसी आदेश के आधार पर जिले के जिम्मेदारों ने ग्राम पंचायतों के सचिवों को 7 दिन के अंदर राशि जमा करने का फरमान जारी किया है। अकेले करंजिया जनपद की 42 ग्राम पंचायतों में 665 पेंशनधारी मृत पाए गए हैं। उनके बैंक खातों में पिछले एक साल से बाकायदा पेंशन योजना की राशि जमा कराई जा रही थी। जनपद करंजिया के ग्राम पंचायतों में मृत पेंशनधारियों के बैंक खातों में जमा राशि का आंकड़ा 43 लाख 2 हजार रुपए है। अगर जिले के सभी ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो मृत पेंशनधारियों की तादात काफी अधिक है। उसकी राशि करीब 2 करोड़ रुपए है।

मृत पेंशनधारियों के परिजनों से जब इस मामले में बात की गई तो उनका कहना था कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। बैंक खातों को बंद करवा दिया गया था। दूसरी तरफ लापरवाही उजागर होने के बाद करंजिया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मरावी अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए गलती का ठीकरा ग्राम पंचायत के सचिवों पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मृत पेंशनधारियों से संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत सचिवों की तरफ से समय पर अपडेट नहीं की गई। इसके कारण ये स्थितियां पैदा हुई हैं। मृत लोगों को पेंशन योजना की राशि जारी करने के मामले में स्थानीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने गुड गवर्नंस को आड़े हाथ लेते हुए जिले के अधिकारियों और प्रदेश



‘भूत’ भी ले रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन

देश में सबसे ज्यादा फर्जी गरीब मग्न में

गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन में कई धनाइय लोग राशन ले रहे हैं। देशभर में फर्जी गरीब बनकर राशन लेने वाले लोग मग्न में पकड़े गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बीते एक साल (2021) में देश में सबसे ज्यादा 14 लाख 24 हजार 115 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए हैं। खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता विभाग द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक तीन साल पहले यानि साल 2019 में देश में सबसे ज्यादा 41,52,273 फर्जी राशन कार्ड उग्र में कैसिल किए गए थे। लेकिन एक साल बाद ही मग्न ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया और साल 2021 में 14 लाख 24 हजार 115 राशन कार्ड निरस्त किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में सबसे ज्यादा फर्जी राशनकार्ड निरस्त हुए। मग्न में 2019 में 61,265 कार्ड, 2020 में 1,65,829 और 2021 में 14,24,115 कार्ड निरस्त किए गए। वहीं उत्तरप्रदेश में 2019 में 41,52,273, 2020 में 8,54,025 और 2021 में 4,15,259 कार्ड निरस्त किए गए। राजस्थान में 2019 में 72,276, 2020 में 5,80,241 और 2021 में 1,35,283 कार्ड निरस्त किए गए। केरल में 2019 में 2,543, 2020 में 52,475 और 2021 में 1,04,511 कार्ड निरस्त किए गए। वहीं कर्नाटक में 2019 में 1,09,312, 2020 में 31,753 और 2021 में 42,558 कार्ड निरस्त किए गए।

सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

राजधानी में आधार कार्ड से राशन वितरण होने के बाद भी पिछले 4 साल में करीब 7 हजार मुर्दे राशन ले रहे थे। मृत्यु होने के बाद भी किसी को एक तो किसी को 6 माह तक दुकानदारों ने राशन बांटा। खाद्य विभाग की जांच के बाद इनके नाम दुकानों से काटे गए। वहीं लगभग 27 हजार लोग अलग-अलग क्षेत्रों से पलायन कर गए उनके नाम के अलावा 6 हजार डबल नाम वाले उपभोक्ताओं के नाम काटे गए हैं, जो दो दुकानों से राशन ले रहे थे।

आधार कार्ड सिस्टम लागू होने के बाद राशन दुकानों पर हर माह होने वाली जांच में ये जानकारी होने के बाद विभाग नाम काट देता है। वरना कुछ दुकानदार तो इनके नाम पर ही सरकारी राशन ठिकाने लगाते रहते हैं। वहीं पिछले 4 साल में 42 राशन दुकानों को राशन कोटे में गड़बड़ी करने पर सस्पेंड किया जा चुका है। 4 दुकानों पर चोर बाजारी निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर भी हुई। इसमें कई दुकानदारों ने पूरे एक माह का राशन खुद के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर निकालकर बाजार में ठिकाने लगाया। उन्हें उपभोक्ताओं को बांटा ही नहीं गया। कुछ दुकानदारों के यहां स्टॉक से अधिक गेहूं, चावल, शक्कर, नमक का संग्रह पाया गया जो पूरी तरह से फर्जीवाड़े का सबूत है। वहीं कुछ दुकानदारों ने 1 तारीख की बजाय माह की 11 तारीख से राशन बांटा था। कार्रवाई के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिला। जिले में 463 राशन दुकानें हैं, जिनसे उपभोक्ता राशन लेते हैं।

● जितेंद्र तिवारी

म प्र में फैली राज्य शासन की ऐसी संपत्तियां जो मृतप्राय हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, सरकार उनको बेचकर अपना खजाना भर रही है।

शासन का मानना है कि इन संपत्तियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। इसी के लिए सरकार ने लोक

परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया है। विभाग प्रदेशभर की अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को सूचीबद्ध कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने बीते सवा महीने में 107 करोड़ रुपए में दस परिसंपत्तियों को नीलामी के जरिए बेच दिया है।

दरअसल, सत्ता में आने के बाद से ही खजाना खाली होने के चलते प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार आय के साधन को बढ़ाने में जुटी हुई है। राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आए दिन बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार प्रदेशभर में मौजूद अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की कहां, कितनी संपत्ति है, उसका क्या व्यावसायिक या अन्य उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रबंधन करने के लिए सरकार ने एक अलग लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया है। यह विभाग प्रदेशभर में सरकारी संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है। विभाग संपत्ति के रखरखाव के साथ उसके औचित्य का निर्धारण भी कर रहा है। सरकार को इस संपत्ति के बारे में राय दे रहा है कि उसे बेचना उचित है या नहीं। उसका किस तरह से व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने बीते सवा महीने में 107 करोड़ रुपए में दस परिसंपत्तियों को नीलामी के जरिए बेच दिया है। इन परिसंपत्तियों के लिए रिजर्व प्राइस से सरकार को डेढ़ से तीन गुना तक फायदा हुआ है। अभी तक सरकार 43 परिसंपत्तियों को बेच चुकी है और 39 संपत्तियों को बेचने की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सवा माह के भीतर सरकार ने 68,965 वर्गमीटर जमीन बेची है। बेकार पड़ी परिसंपत्तियों को बेचने के कारण केंद्र से मप्र को 1,005 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। मप्र सरकार ने 26 सितंबर 2020 में अनुपयोगी परिसंपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया। इसके बाद 69 विभागों की 2 हजार परिसंपत्तियों की सूची तैयार की गई। जिसमें से 444 शासकीय कार्य के लिए उपयोगी पाई गई। इन परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित मूल्य से सरकार को तीन गुना तक फायदा हुआ है। बीते

अनुपयोगी संपत्तियों को बेचकर खजाना भर रही सरकार...



ये संपत्तियां बेचने की तैयारी

संपत्ति का स्थान	वर्गमीटर	राशि
उज्जैन विनोद मिल-1	19,069	25.41
उज्जैन विनोद मिल-2	17,529	24.61
ग्वालियर ग्राम सिरोल	1,730	1.89
राऊ में खादी ग्रामोद्योग	0.310	3.81
भातखेड़ी ग्वालियर	4,915	7.17
वेयरहाउस ग्वालियर	1,987	17.20
नरसिंहपुर स्कूल प्लाट	0.620	3.59
कोलार हिनोतिया	12,500	8.63
इंदौर तलावली चांदा	7,690	10.00
दमोह के वार्ड-2 में	2,615	5.11

स्त्रोत-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (राशि करोड़ में)

सवा महीने में दस परिसंपत्तियों को 107 करोड़ 42 लाख रुपए में बेचा गया।

सरकारी प्रवक्ता एवं गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सालों से बेकार पड़ी बस डिपो, वेयर हाउस, बस स्टैंड, स्कूल प्लाट आदि परिसंपत्तियों को बेच रही है। इन संपत्तियों की नीलामी में तय रिजर्व प्राइस से भी ज्यादा टेंडर आने पर उन्हें बेचा जा रहा है। सरकार को इससे फायदा हो रहा है। प्रदेश में तकरीबन सभी विभागों के पास अचल संपत्तियां हैं। लोक निर्माण विभाग के पास जो रेस्ट हाउस हैं, उनमें निर्माण तो एक या डेढ़ हजार वर्गफीट पर है लेकिन ढाई से सात एकड़ तक जमीन खाली पड़ी हुई है। साथ ही वो अचल संपत्ति, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उनके निराकरण की समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। ऐसी सभी संपत्तियों का उपयोग अब राज्य हित में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने लोक निर्माण और सड़क परिवहन निगम की कुछ संपत्तियां नीलाम करने की तैयारी

शुरू कर दी है।

मप्र के बाहर शासकीय परिसंपत्तियों से आय बढ़ाने के लिए सरकार उनका नए सिरे से उपयोग करेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पुनर्धनत्वीकरण नीति 2016 में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत मप्र के स्वामित्व वाली वे संपत्तियां जो अन्य राज्यों में हैं और अविवादित हैं, उन्हें नीति में शामिल किया जाएगा। वहीं, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों की अनुपयोगी परिसंपत्तियों को नीलाम करने कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन और परिसरों के नए सिरे से उपयोग के लिए पुनर्धनत्वीकरण नीति 2016 में लागू की गई थी। इसका दायरा सीमित था लेकिन अब इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नीति में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक निगम, मंडल, प्राधिकरण और नगरीय निकायों के भवन या परिसर भूमि का नए सिरे से उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश के बाहर स्थिति अविवादित और अनुपयोग संपत्ति भी नीति के दायरे में आएगी। प्रदेश की उप्र, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में संपत्तियां हैं। पुनर्धनत्वीकरण के अलावा उन संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जो अनुपयोगी हैं। इसके लिए अब लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया गया है। सभी विभागों ने अपनी परिसंपत्तियों की जानकारी इस विभाग के पोर्टल पर दर्ज की है। विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की लगातार समीक्षा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व, वित्त, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों का अभिमत लिया जा रहा है।

● जय सिंह

अभी तक बदनामी के तौर पर जानी जाने वाली महुआ की शराब अब देश-विदेश में हेरिटेज शराब के रूप में धूम मचाएगी। आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए महुआ शराब को स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार इसे अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी ले जाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले हेरिटेज शराब की बिक्री पर्यटन विभाग के होटल और बार में की जाएगी। उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद हेरिटेज शराब की बिक्री शराब दुकानों पर किए जाने की योजना है। फिलहाल हेरिटेज शराब की कीमत तय नहीं की गई है।

गौरतलब है कि मप्र देश का पहला राज्य है, जो महुए से शराब का निर्माण कर उसे वैध तरीके से बेचने जा रहा है। इसे हेरिटेज शराब नाम दिया गया है। महीनेभर में हेरिटेज शराब का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान हेरिटेज शराब की शुद्धता पर है, क्योंकि सरकार हेरिटेज शराब की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि यदि हेरिटेज शराब की ठीक से ब्रांडिंग की जाए, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान बन सकती है।

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हेरिटेज शराब निर्माण के लिए आदिवासी बहुल अलीराजपुर और डिंडोरी जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यहां आदिवासी स्वसहायता समूह हेरिटेज शराब का निर्माण करेंगे। अलीराजपुर में शराब निर्माण की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। यहां महीनेभर के अंदर उत्पादन शुरू हो जाएगा। डिंडोरी में उत्पादन इकाई लगाने की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार महुए से बनने वाली शराब को कई तरह की रियायतें देने की तैयारी कर रही है। शराब बनाने वाले स्वसहायता समूहों को एक साल तक वेट नहीं देना होगा और उन्हें पांच साल तक एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलेगी। साथ ही उद्योग विभाग की अपात्र सूची से शराब को बाहर निकाला जाएगा, ताकि उन्हें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान मिल सके। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे का कहना है कि हेरिटेज शराब के उत्पादन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलीराजपुर में टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसी महीने उत्पादन भी शुरू होने के आसार हैं। डिंडोरी में उत्पादन शुरू होने में एक-डेढ़ महीने का समय लग सकता है। शराब का उत्पादन स्वसहायता समूहों के जरिए किया जाएगा। हेरिटेज शराब निर्माण में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

हेरिटेज शराब का निर्माण महुए के फूलों से



प्राकृतिक वन संपदा से भरपूर मप्र में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। आज भी अधिकांश आदिवासियों की निर्भरता वनोपज पर रहती है। इसको देखते हुए मप्र सरकार ने महुआ की शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की तैयारी की जा रही है।

देश-विदेश में धूम मचाएगी आदिवासियों की हेरिटेज शराब

मिलेंगी कई रियायतें

मप्र में महुए से बनी हेरिटेज मदिरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई रियायतें देने की तैयारी कर रही है। इसमें शराब बनाने वाले स्वसहायता समूहों को एक साल तक वेट नहीं देना पड़ेगा। साथ ही 5 साल तक एक्साइज ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री (उद्योग विभाग) की निगोटिव लिस्ट से 'शराब' को बाहर निकाला जाएगा, ताकि उन्हें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के तहत अनुदान मिल सके। कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेज दिया गया है। उद्योग विभाग की निगोटिव लिस्ट (अपात्र सूची) का मतलब यह है कि इस लिस्ट में जितने भी सेक्टर होते हैं, उन्हें अनुदान नहीं दिया जाता। हेरिटेज मदिरा के लिए पहली बार शराब इस लिस्ट से बाहर होगी। शासन का तर्क है कि आदिवासी स्वसहायता समूहों को ही हेरिटेज मदिरा बनाने का लाइसेंस दिया जाना है, इसलिए औद्योगिक अनुदान से उन्हें मदद मिलेगी।

किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया की एकमात्र शराब है, जो फूलों से बनाई जाती है। भारत में अकेले मप्र में इसका निर्माण किया जाता है। इस शराब में मिथाइल एल्कोहल नहीं होता, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अन्य सभी प्रकार की शराब में मिथाइल एल्कोहल होता है। मप्र में बनने वाली हेरिटेज शराब के निर्माण में किसी भी तरह के कैमिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला पानी उच्च गुणवत्ता का होगा। हेरिटेज शराब की उत्पादन इकाई में हाईजीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हेरिटेज शराब बनाने वाले हर स्वसहायता समूह को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेट लेना होगा।

प्रदेश सरकार ने मप्र टूरिज्म के होटलों में महुआ शराब की बिक्री को अनुमति दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महुआ शराब को सबसे पहले मप्र टूरिज्म द्वारा संचालित 18 होटलों और बार में बेचा जाएगा। आपको बता दें कि महुआ शराब की कीमत अभी तय नहीं की गई है। लेकिन शराब की गुणवत्ता किसी भी प्रतिष्ठित ब्रांड के बराबर होगी। प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार बिक्री काउंटर खोलने पर फैसला करेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार है कि स्थानीय स्तर पर महुआ शराब पेशेवर तरीके से बनाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि विनिर्माण प्रक्रिया पुणे में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए शोध का पालन करेगी।

● राजेश बोरकर

देश के ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर बच्चों की लंबाई अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन राज्यों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे न सिर्फ बौने हो रहे हैं, बल्कि उनके अंदर और भी तमाम तरीके की दिक्कतें इस वजह से आ सकती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ है। केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश और गोवा से लेकर आंध्रप्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जो तमाम कोशिशों के बाद भी अपने राज्य में होने वाले बच्चों के बौनेपन को दूर नहीं कर पा रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 में जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार और 2019-21 में जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुल मिलाकर देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या तो कम हुई है, लेकिन देश के कई राज्य अभी भी इस मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में 5 साल से कम उम्र के 43.8 फीसदी बच्चे बौनेपन का शिकार थे। जबकि उसके 5 साल बाद जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रतिशत 40.9 के करीब पहुंच गया। यानी कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या कम तो हुई, लेकिन देश के कई राज्य राष्ट्रीय औसत आंकड़े से अलग चलते रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में केरल एक ऐसा राज्य है, जहां पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि केरल में 5 साल से कम उम्र के 23.9 फीसदी बच्चे ही बौनेपन के शिकार थे। जबकि 2019-21 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा तकरीबन 13 फीसदी से बढ़कर 36.9 फीसदी पर पहुंच गया है। यानी कि केरल में 5 साल के भीतर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या बढ़ी है।

इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या बढ़ी हुई पाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट में 5 साल से कम उम्र के 22.3 फीसदी बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक लंबाई नहीं पा सके थे। यानी इन्हें बौनेपन की कैटेगरी में रखा गया था। हाल में रिलीज हुई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 32.9 फीसदी हो



5 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे बौने!

खानपान और पौष्टिक भोजन का अभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े डॉक्टर राजेश कुमार कहते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है उन्हें बौनेपन की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों में बौनापन बेहतर खानपान की कमी और पौष्टिक भोजन के अभाव के चलते होती है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों में इस तरीके की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए देशभर में न सिर्फ विशेष अभियान चलाए जाते हैं बल्कि बेहतर खानपान और पौष्टिक भोजन की पूरी व्यवस्था संबंधित महकमे और अन्य जिम्मेदार महकमों के साथ मिलकर पूरी की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि यही वजह है कि पूरे देश में कुल मिलाकर बच्चों में बौनेपन की समस्या में कमी हुई है। वह कहते हैं कि धीरे-धीरे यह समस्या और कम होती जाएगी।

गई है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके के हालात सामने दिख रहे हैं। बीते 5 सालों में आंध्रप्रदेश में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या बढ़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट के मुताबिक 31.7 फीसदी बच्चे बौनेपन का शिकार थे। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 10 फीसदी से बढ़कर अब 41 फीसदी पर पहुंच गई है। यानी आंध्रप्रदेश में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनापन बढ़ रहा है। सिर्फ आंध्रप्रदेश ही नहीं बल्कि गोवा में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनापन बढ़ता हुआ पाया गया है। रिपोर्ट बताती है कि

बीते 5 सालों में 8 फीसदी से ज्यादा बच्चों में बौनापन बढ़ा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों से लेकर हरियाणा तक के बच्चों में बौनापन बढ़ रहा है। त्रिपुरा ने बीते 5 साल के भीतर 10 फीसदी से ज्यादा बच्चों में बौनेपन की समस्या देखी गई है। जबकि तमिलनाडु में इसी उम्र के बच्चों में छह फीसदी के करीब बौनेपन की समस्या बढ़ी हुई पाई गई। नागालैंड में जहां 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 50 से ज्यादा बच्चों में बौनापन पाया गया, वहीं मेघालय में यह प्रतिशत तकरीबन डेढ़ फीसदी रहा। हरियाणा में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में इस वक्त 5 साल से कम उम्र के पैदा होने वाले तकरीबन 39.5 फीसदी बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं पा रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा उम्र के बच्चे बौनेपन का शिकार हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती थी कि उस वक्त भी पूरे देश में सबसे ज्यादा बौने बच्चे उम्र में ही पाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 50.9 फीसदी यानी आधे से ज्यादा बच्चे बेहतर खानपान और पौष्टिकता की कमी के चलते अपनी उम्र के मुताबिक लंबाई नहीं पा रहे थे। हाल में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बौनेपन की पूरे देशभर के राज्यों की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी उम्र पहले पायदान पर खड़ा है। हालांकि इसमें डेढ़ फीसदी का सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी 49.2 फीसदी बच्चे 5 साल से कम उम्र के बौनेपन का शिकार हो रहे हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

म प्र के सागर जिले में स्थित लगभग 1200 वर्ग किमी में फैला नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य बाघों का नया बसेरा बनता जा रहा है। इतिहास में बाघों की उपस्थिति के कई प्रमाण होने के बाद भी नौरादेही बाघों को लेकर

कभी भी चर्चा का विषय नहीं रहा, शायद इसलिए कि यहां बाघ दिखाई नहीं देते थे, या शायद यहां से बाघ विलुप्त हो चुके थे। पर फिर भी कभी-कभी भूले भटके पास में स्थित पन्ना के जंगलों से बाघों का आना-जाना यहां हमेशा से ही बना रहा है। वर्ष 2010 में यहां पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बाघ यहां आ गया था, जो उसके बाद से अगले कुछ सालों तक लगातार आता-जाता रहा, परंतु कोई साथी न मिल पाने या किसी और अन्य कारण से वो यहां स्थाई रूप से रुक नहीं पाया।

बाघों के लिए अनुकूल आवास होने के बाद भी यहां बाघों का न होना वन विभाग को हमेशा से ही खटकता रहा, और बाघों को यहां दोबारा बसाना एक चुनौती भरा कार्य था। अभयारण्य के अंदर कई गांव मौजूद थे, जिसके कारण यहां जैविक दबाव भी बहुत ज्यादा था। साथ ही शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या भी संतोषजनक नहीं थी, शायद एक ये भी कारण था कि बाघ जो पन्ना या अन्य संरक्षित क्षेत्रों से इलाकों की तलाश में यहां पहुंच रहे थे, वो स्थाई नहीं हो पा रहे थे। परंतु मप्र वन विभाग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बाघों को दोबारा नौरादेही में बसाने की कवायद शुरू की। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018, कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघिन नौरादेही लाई गई, ये बाघिन कोई और नहीं बल्कि पेंच टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघी-नाला बाघिन के शावकों में से एक थी। जिनको उनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद कान्हा में रखा गया था। इस बाघिन को नाम दिया गया एन1 (राधा)। एन1 नौरादेही में बाघ पुनर्स्थापना की बुनियाद थी और इस बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ एन2 को लाया गया। एन1 एवं एन2 दोनों ही नौरादेही बाघ पुनर्स्थापना के मील का पत्थर साबित होने वाले थे।

नौरादेही वन प्रबंधन के द्वारा बाघ पुनर्स्थापना को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, दोनों नए बाघों को कुछ दिन मनुष्य हस्तक्षेप से दूर पानी एवं उचित आवास सुविधा युक्त विशाल बाड़े में रखा गया एवं उसके बाद इन्हें जंगल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया गया। अभयारण्य के अंदर कई गांव स्थित थे, बाघों के आने से इन गांव में रहने वाले लोगों एवं बाघों के बीच संघर्ष बढ़ने की आशंका थी जो इस योजना को विफल कर सकती थी। परंतु इन गांव में रहने वाले लोगों का रवैया बाघों एवं अन्य वन्यप्राणियों के प्रति हमेशा से ही सकारात्मक रहा है और

नौरादेही बना बाघों का बसेरा



गांव की निर्भरता से जैविक दबाव बढ़ रहा

बाघों की बढ़ती संख्या हर्ष का विषय तो है परंतु इसे यूं ही बनाए रखने के लिए और भी पड़ाव पार करने हैं। इनमें सबसे ज्यादा कठिन है जैविक दबाव को रोकना। नौरादेही के अंदर 72 गांव थे, जिनमें से 22 गांवों को स्वैच्छिक विस्थापन प्रक्रिया के तहत विस्थापित किया जा चुका है परंतु 50 गांव अभी भी अभयारण्य के अंदर ही हैं। इन गांव के निवासी पूरी तरह अभयारण्य के जंगल पर ही निर्भर हैं। गांव के पालतू पशुओं की चराई भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जंगल पर इन गांव की निर्भरता से जैविक दबाव बढ़ता जा रहा है। अभयारण्य में अन्य शाकाहारी जानवरों की संख्या कम होने के कारण बाघों द्वारा पालतू मवेशियों का शिकार कर लिया जाता है जिसके कारण मानव-बाघ संघर्ष बढ़ने की संभावना एवं गांव वालों में असंतोष की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए अंदर स्थित गांवों से सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है।

इन्होंने बाघों को सहर्ष स्वीकार किया। वन प्रबंधन द्वारा गांव वालों की सहमति के आधार पर कुछ गांवों का पुनर्वास भी किया गया एवं कुछ बचे हुए गांवों का पुनर्वास होना अभी बाकी है। इन गांवों के पुनर्वास के बाद इनकी खाली जगहों पर वन प्रबंधन द्वारा चारागाह का विकास किया गया एवं दूसरे अन्य संरक्षित वनों जहां चीतल एवं अन्य शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या काफी अच्छी है, वहां से इन्हें लाकर अभयारण्य में छोड़ा गया। जिससे यहां इनकी आबादी में विकास हो सके और बाघों को आवास के साथ भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसके अलावा कई अन्य प्रयास जैसे जल प्रबंधन की योजनाओं पर भी कार्य किया गया। इन सब प्रयासों का परिणाम मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगी, और मई 2019, बाघिन एन1 तीन नन्हें बाघ शावकों के साथ इनकी निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप में नजर आई और नौरादेही में बाघों की संख्या दो से बढ़कर 5 हो गई। इन नन्हें बाघ शावकों को एन111, एन112 एवं एन113 नाम दिया गया, जो कि बाघों को नामकरण करने की एक सामान्य प्रक्रिया है।

नौरादेही का प्रबंधन इन 5 बाघों की निगरानी और देखरेख की योजना बना ही रहा था, कि जनवरी 2021 में कैमरा ट्रैप की फोटो को चेक करते समय अभयारण्य के स्टाफ को एक नया मेहमान बाघ (एन3) नजर आया, जो यहां मौजूद बाघों से बिलकुल अलग था। आसपास के संरक्षित

क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप की फोटो मिलान करने पर भी ये मालूम न चल सका कि ये नया बाघ आखिर कहां से आया है? ऐसा माना गया कि शायद ये बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से यहां आया है, या शायद ये यहां पहले से ही था और निगरानी बढ़ने पर अब नजर आने लगा। कुछ भी हो, नौरादेही को उसका छठवां बाघ मिल गया था। नवंबर 2021, बाघिन एन1 दूसरी बार दो नन्हें शावकों के साथ नजर आई। हाथी दल के द्वारा निगरानी करने पर ज्ञात हुआ कि उसने दो नए शावकों को जन्म दिया है। ये नौरादेही प्रबंधन जिसने बाघों के संरक्षण में एवं पुनर्स्थापना में दिन-रात एक कर दिए थे के लिए एक अविस्वरणीय समय था। अप्रैल 2022, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया की टीम नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य में अखिल भारतीय बाघ आंकलन-2022 के कार्य में वन विभाग का सहयोग कर रही थी। तभी खबर आई कि हाथी गस्ती दल, जो कि रेडियो कॉलर बाघिन एन112 की निगरानी कर रहा था, उसने बाघिन के साथ दो नन्हें शावकों को देखा है। अभी हाल ही में ये पता चला है कि बाघिन एन1 ने दूसरी बार दो नन्हें बल्कि चार शावकों को जन्म दिया था। और अब नौरादेही में बाघों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो गई है (एन1 के पिछले तीन शावक (एन111, एन112, एन113) एवं अभी वर्तमान में चार शावक, एन2 एवं एन3 और एन112 के दो शावक)।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड में जल सहेलियों ने पानीदार पंचायतें चुनी हैं। जिले में काम करने वाली जल सहेलियों ने जल संकट के निदान पर आधारित घोषणा पत्र तैयार कर सरपंच पद के प्रत्याशियों और मतदाताओं तक पहुंचाया। चुनाव में खड़े ऐसे लोगों से समर्थन देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जो अपनी पंचायत को जल संकट से निदान के लिए प्रयासरत हैं, और आगे भी रहने का वादा कराया। एक दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऐसे सरपंच चुने गए हैं, जो पानीदार पंचायत के लिए काम करेंगे। छतरपुर की जल सहेलियों ने जून के दूसरे पखवाड़े में बैठक कर तय किया कि पंचायत चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए जो गांव के मूलभूत विकास के साथ-साथ जल संकट को दूर करने के विशेष प्रयास करेगा। परमार्थ समाज सेवा संगठन के राज्य संयोजक मानवेंद्र सिंह और अन्य पदाधिकारियों से मिलकर जन घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसे प्रत्याशियों और लोगों तक पहुंचाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने अभियान का शुभारंभ कराया।

छतरपुर में बनाई गई पानीदार पंचायतों में ग्राम पंचायत बरेठी में सुनील आदिवासी, जगतनगर में ललिता आदिवासी, मस्तापुर में धनवंती खंगार, नादिया में फूलमती कुम्हार, भेलदा से जगदीश राजे, भगवां से रामदेवी सोनी, मोयरा से जसोदा बाई अहिरवार, सेवार से सूरज अहिरवार, ढडौरा से अनीता घोसी, पनवारी से नाथूराम लोधी, बन्ना से हरि सिंह लोधी, पुरा पट्टी से परमलाल आदिवासी, मड़ीखेरा से गुड्डडी राजे बुंदेला, हरदौल पट्टी से माया देवी कुशवाहा को सरपंच चुना गया है। ग्राम पंचायत नदिया की सरपंच फूलमती कुम्हार बताती हैं कि हमने चुनाव में लोगों के बीच जाकर आम मूलभूत सुविधाओं के साथ जल संकट को दूर करने की बात रखी। लोगों ने भरोसा कर हमें सरपंच बनाया है। हम पानीदार पंचायत के लिए काम करेंगे। ग्राम पंचायत बरेठी के सरपंच सुनील आदिवासी का कहना है कि **जल संकट हमारे यहां** बड़ा मुद्दा है। सभी लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या को दूर करेंगे। इसमें प्रशासन की मदद भी लेंगे। हमारी पानीदार पंचायत में पुराने तालाबों को जीवित किया जाएगा। जल जन जोड़ी अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जल सहेलियों ने पानीदार पंचायतें बनाने की मुहिम शुरू की है। निश्चित ही ऐसी मुहिम बुंदेलखंड के सूखे को खत्म करेगी। जागरूकता मुहिम से जल सहेलियों की यह मुहिम रंग लाई है। एक दर्जन ग्राम पंचायतों को पानीदार पंचायत के रूप में चुना गया है।

वैसे तो बुंदेलखंड उप्र के 7 जिलों और मप्र के 7 जिलों को मिलाकर बनता है, मगर हम यहां बात

सहेलियों ने बनाई पानीदार पंचायतें



लागू होगा जन घोषणा पत्र

बिल्हारी गांव की जल सहेली स्वाती सिंह और केशर सेन ने बताया पानीदार पंचायतों में जन घोषणा पत्र लागू किया जाएगा। पंचायत में जल अधिकार नियम लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाने पर काम होगा। गांव के तालाब, मृत नदियों को जीवित करने की मुहिम शुरू की जाएगी। जल योजनाओं में मूल्यांकन कार्य में जल सहेलियां शामिल होंगी। जल संरचनाओं को चिन्हित कर सीमांकन कराने की मांग की जाएगी। गांव स्तर पर जल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। स्वाती सिंह ने बताया कि पंचायत सबसे छोटी, लेकिन जमीन से जुड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। पंचायतों में जल संरक्षण के लिए जितनी तेजी से काम किया जाएगा, उम्मीद है कि बुंदेलखंड से जल संकट उतनी जल्दी दूर होगा।

मप्र के 7 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया की करने जा रहे हैं। यह ऐसा इलाका है जो कभी पानीदार हुआ करता था क्योंकि चंदेलकालीन और बुंदेला राजाओं के दौर में जल संरचनाओं पर खासा जोर था। वर्तमान में तस्वीर एकदम उलट है और यहां के बड़े हिस्से में पानी के संकट की कहानियां खूब सामने आती हैं। गर्मी का मौसम आते ही यहां के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में पहुंचते ही आपको जल संकट की तस्वीरें नजर आने लगती हैं, हर तरफ जल स्रोतों पर लोगों का जमावड़ा होता है, पानी के लिए तो खून तक बहाने को लोग तैयार हो जाते हैं। इस इलाके के जल संकट को खत्म करने के लिए प्रयास न हुए हो, ऐसा भी नहीं है। वर्ष 2007-08 में मप्र के हिस्से में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज के तहत आए, मगर स्थितियां नहीं बदली, क्योंकि बड़ी रकम की बंदरबांट हुई। कई रोचक मामले सामने आए, यहां निर्माण कार्य की सामग्री का परिवहन जिस ट्रक और डंपर के अलावा ट्रैक्टर के जरिए दिखाया गया, जब वाहन नंबरों की तहकीकात की गई तो पता चला कि वह नंबर दो पहिया वाहनों के थे। वहीं जो तालाब और जल संरचनाएं बनीं भी, वे दूसरी और तीसरी बारिश में ही धराशाई हो गई। पैकेज में हुई गड़बड़ी को लेकर लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पवन घुवारा का कहना है कि इस इलाके में बुंदेलखंड पैकेज में 1296 संरचनाओं का निर्माण हुआ था जब परीक्षण किया

गया तो उसमें से 1098 संरचनाएं अनुपयोगी पाई गई थीं, इस गड़बड़ी में लिप्त अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई होती तो और लोग सबक लेते मगर ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर सरकार जिस तरह अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है उसे इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए, नहीं तो अभियान कुछ लोगों के लिए लूट के अलावा कुछ नहीं होगा।

सूखा, जलसंकट और पलायन को लेकर देशभर में चर्चित बुंदेलखंड की महिलाओं ने जल सहेली बनकर कई गांवों की तस्वीर बदल दी है, उन्होंने अपने श्रम से पुराने जलस्रोतों को पुनर्जीवित कर दिया है और बर्बाद होते पानी को उपयोगी बना डाला है। बुंदेलखंड की ये जल सहेलियां केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण के लिए शुरू किए गए जल क्रांति अभियान के लिए आदर्श बन सकती हैं। केंद्र सरकार जहां देश व्यापी अभियान पर काम कर रही है, तो वहीं बुंदेलखंड में महिलाओं ने पानी बचाने और संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। यह वह इलाका है, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहीं उमा भारती का संसदीय क्षेत्र झांसी-ललितपुर आता है। बुंदेलखंड के तीन जिलों हमीरपुर, जालौन और ललितपुर की 60 ग्राम पंचायतों के 96 गांव की जल सहेलियों ने तस्वीर ही बदल दी है।

● सिद्धार्थ पांडे



आजादी का अमृत महोत्सव आओ... याद करें कुर्बानी

देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस बार देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के समय भारत की पहचान दुनिया के गरीब देश के रूप में थी। लेकिन आज भारतवर्ष दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है और जिस खुशहाली के लिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके पीछे हजारों-लाखों लोगों का बलिदान रहा है।

● राजेंद्र आगाल

आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हम भारत की प्रगति की गाथा गा रहे हैं, लेकिन यह अवसर उन रणबाकुरों को याद करने का भी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें आजाद भारत दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई

पटेल आदि ने तो आजादी की सुबह देखी, लेकिन शहीद भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे हजारों गुमनाम बलिदानी ऐसे भी हुए जिन्होंने देश के लिए हंसते-हंसते फंसी का फंदा चूम लिया या कुर्बान हो गए। आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे बलिदानियों की कुर्बानी को याद करने का भी अवसर है। देश में असंख्य बलिदानी

ऐसे हैं जिनका न तो इतिहास में जिक्र है और न ही सरकार के साक्ष्यों में। लेकिन वे आज भी अपने क्षेत्र में किवंदती बने हुए हैं। इन लोगों ने देश को आजाद कराने में किसी महान बलिदानी से कम योगदान नहीं दिया है। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे देशभक्तों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है।

देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस बार देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल पहले और आज के भारत में जनसंख्या से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक और आर्थिक मोर्चे से लेकर तकनीकी क्षेत्र तक में भारत बहुत आगे निकल गया है। आजादी के समय भारत की पहचान दुनिया के गरीब देश के रूप में थी। लेकिन आज भारतवर्ष दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने की तरफ निरंतर अग्रसर है। इतना ही नहीं आजादी के समय से लेकर देश की प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा बदलाव आया है। लेकिन यह तभी संभव हो पाया है, जब आजादी के परवानों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आजाद करवाया।

2 वर्षों का कड़ा संघर्ष

देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने अमृत महोत्सव पर्व मना रहा है परंतु ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है बल्कि इसके लिए 200 वर्षों तक भारतीयों ने कड़ा संघर्ष किया है, देशवासियों ने हजारों बलिदान दिए हैं, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। 9 अगस्त 1942 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर और क्रूर कार्यवाही की परंतु उस दौरान अंग्रेजों की अत्यंत दमनकारी नीतियों से उब चुके थे कि उन्होंने अंग्रेजों को आंदोलन के माध्यम से भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया और ब्रिटिश सरकार के पास भी भारत से अपनी सत्ता को समाप्त करना ही एक आखिरी मार्ग बचा था। करीब 80 साल पहले, 9 अगस्त 1942 को, भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक और अंतिम चरण की शुरुआत की, ये अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एक जन आंदोलन था जो बिना किसी नेतृत्व के प्रसारित हुआ, इस आंदोलन की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि भारतीय बिना किसी नेतृत्व के कोई आंदोलन कर सकते हैं, इस आंदोलन ने विश्व को एक संदेश दिया कि भारतीय अब और अधिक समय तक ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी नहीं सहेंगे।

15 अगस्त, 1947 को हम अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुए थे। 130 करोड़ की मौजूदा जनसंख्या वाले हिंदुस्तान को यूँ ही अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली थी, देश की आजादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। इस देश को आजाद कराने वाले सच्चे देशभक्तों के संघर्ष, हौसले और जुनून की जितनी तारीफ की जाए, वो हमेशा कम ही रहेगी।



पन्ना के पांडव फॉल से चंद्रशेखर ने फूँका था आजादी का बिगुल

जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब क्रांतिकारी छिप-छिपकर आजादी की लड़ाई के लिए रणनीति बना रहे थे, तब ऐसी ही बैठक की साक्षी पन्ना की धरती बनी थी। 4 सितंबर 1929 को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने पन्ना के घने जंगल में पांडव फॉल में क्षेत्र के क्रांतिकारियों की बैठक लेकर विंध्य में आजादी की क्रांति का बिगुल फूँका था। पांडव फॉल में ही चंद्रशेखर आजाद ने देश से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। इस बैठक में क्षेत्र के 500 से अधिक क्रांतिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में क्षेत्र के 500 से अधिक क्रांतिकारी शामिल हुए थे। इसका मुख्य कारण यह था कि आजाद ब्राह्मण परिवार से थे और अपना आदर्श महाभारत के उन पाँचों पांडवों को मानते थे जिन्होंने सत्य की जीत के लिए पूरा कौरवों का साम्राज्य खत्म कर दिया था। आजाद ने पांडव फॉल में क्रांतिकारियों की बैठक लेकर पूरे देश में आजादी की अलख जगाई थी। मप्र टूरिज्म ने अमर शहीद आजाद की यादों को संरक्षित करने यहाँ उनका स्मारक बनाया है। सांडर्स हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती और दिल्ली असेंबली बम कांड के बाद आजाद का ज्यादातर समय बुंदेलखंड और उससे लगे इलाकों में बीता। वे मथुरा और बुंदेलखंड के झांसी में कुछ वक्त गुजारकर बांदा में हस्तरेखा विशारद बनकर अज्ञातवास में छिपे रहे। जानकार बताते हैं कि दिल्ली असेंबली विस्फोट के बाद आजाद कुछ दिनों तक मथुरा में रहे। इस बीच तत्कालीन उग्र सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। तब मथुरा को सुरक्षित स्थान न मानकर आजाद झांसी आ गए और यहाँ एसपी के ड्राइवर के रूप में रहे। उसी दौरान बांदा का दो बार भ्रमण कर गए। कुछ दिनों बाद झांसी के एसपी को उन्हें गिरफ्तार करने का पत्र मिला, जो आजाद के हाथ लग गया। जिसे पढ़कर वे वहाँ से भाग गए।

भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1857 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले, 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त, 1947 के दिन आजादी मिली। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी साल 1857 में निकली थी। उस वक्त का विद्रोह, सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडेय के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और जेआरडी टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी को-ऑप स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था।

किसानों का अमूल्य योगदान

आजादी की लड़ाई के बलिदानों को स्मरण करते समय हमें उन अनेक किसान व आदिवासी आंदोलनों को नहीं भूलना चाहिए, जिनमें शोषित-पीड़ित ग्रामीण जनता ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई व जागीरदारों-जमींदारों से मिले औपनिवेशिक शासकों का भी विरोध किया। ये आंदोलन लगभग अंग्रेज शासन की स्थापना के साथ ही शुरू हो गए थे। इन्हीं दिनों कुछ किसानों की प्रधान भूमिका वाले विरोध-गोरखपुर (1778-81), रंगपुर (बंगाल, 1783) व सुबादिया (बंगाल, 1792)



देश जश्न मना रहा था, बापू भूखे-प्यासे भटक रहे थे

पूरा देश इस वक्त आजादी के 75 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। हर कोई नीले आसमान के नीचे स्वतंत्र सांस ले रहा है। ना कोई बंधन ना कोई रोक-टोक हर किसी को हर चीज की आजादी है। लेकिन इस आजादी को हासिल करने के लिए देश के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते-हंसते दे डाली। वीरों की शहादत से देश को आजादी तो बड़ी मिली, लेकिन यादें छोटी हैं। जब भी आजादी की बात आती है तो महात्मा गांधी का नाम जरूर याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन बापू इस जश्न में शामिल नहीं हुए। बल्कि भूखे और प्यासे बैठे थे। देश की आजादी के जश्न के वक्त महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे। बापू यहां हिंदू-मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था उस वक्त महात्मा गांधी भूखे और प्यासे थे। अनशन पर होने की वजह से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जवाहर लाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिन दिया। उस वक्त इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना क्योंकि उस दिन वे जल्दी सोने चले गए थे। महात्मा गांधी को जब बताया गया कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि को देश आजाद हो जाएगा और इसके जश्न में आपको शामिल होना है तो उन्होंने भी जवाब में एक खत लिखा। इसके जरिए कहा था, जब हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ।

में हुए। बंगाल और बिहार में 1766-72 तक चुआड़ आदिवासी विद्रोह हुआ, जो 1795 से 1816 तक फिर हुआ। 1814-17 में अलीगढ़ के तालुकदारों ने विद्रोह किया। गुजरात के कोली लोगों ने 1824-25, 1828-39 और 1849 में विद्रोह किए। 1824 में हरियाणा व पश्चिमी उप्र के जाटों तथा कई आदिवासी विद्रोह हुए। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में आदिवासी मुखियाओं द्वारा 1840 और 1845 में विद्रोह हुए। 1855 में संथाल आदिवासियों का विद्रोह हुआ। किसानों की प्रमुख भूमिका वाले कुछ विद्रोह थे- बरासात (बंगाल) के टीटू मीर का विद्रोह, मैसूर की रैयत का विद्रोह व फरीदपुर (बंगाल) का विद्रोह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसानों, दस्तकारों, मजदूरों आदि ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया तथा धनुष, तलवार, भाला, खंजर जो भी हथियार उन्हें मिला, उसी से उन्होंने

युद्ध किया। 1859-60 में बंगाल में नील के किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। बिहार में दरभंगा और चंपारण में 1866-68 में नील की खेती के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुए। सूदखोरी और वनाधिकारों के हनन के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के गोदावरी रांपा क्षेत्र में आदिवासियों ने 1858, 1861 और 1862 में आवाज उठाई। पुणे और अहमदनगर जिलों में वर्ष 1875 में 33 स्थानों पर साहूकारों के विरुद्ध ग्रामीणों के विद्रोह हुए। रांची और सिंहभूमि के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बहुचर्चित आदिवासी विद्रोह हुआ। उस विद्रोह ने रांची के अंग्रेजों में दहशत फैलाई थी, पर कुछ समय बाद उसे निर्ममता से कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद सरकार आदिवासियों के असंतोष को कम करने के लिए कुछ कानून बनाने को विवश हुई। 1893-94 में लगान बहुत बढ़ने के विरुद्ध असम के

आजादी से पहले फहराया गया तिरंगा

आजादी के मतवालों ने इससे कई साल पहले तिरंगा फहराना शुरू कर दिया था। 4 ऐसी जगह हैं जहां आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया गया था, हालांकि उस समय तिरंगा वर्तमान स्वरूप में नहीं था।

धर्म स्तूप आजादी का गवाह- राजस्थान के चूरू जिले से तिरंगा का अनूठा इतिहास जुड़ा हुआ है। यहां का धर्म स्तूप आजादी का प्रतीक है। देश के



आजाद होने से पहले 26 जनवरी 1930 यानि 17 साल पहले स्वतंत्रता सेनानी चंदन मल बहड़ ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। इसमें उनके साथियों ने भी सहयोग किया था। रात में तिरंगा फहराने के बाद बहड़ और उनके साथियों को काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थीं। बता दें कि चूरू के धर्म स्तूप को लाल घंटाघर भी कहा जाता है। इसका निर्माण पिलानी के बिड़ला परिवार ने कराया था। धर्म स्तूप पर महापुरुषों की कही गई बातें लिखी गई हैं।

1937 में लखनऊ विवि में बदला झंडा- उप्र के लखनऊ विश्वविद्यालय में साल 1937 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल सर हेटली और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के भी शामिल होने का कार्यक्रम था। ऐसे



में लविवि के अध्यक्ष रह चुके जय नारायण श्रीवास्तव ने अपने साथियों के साथ मिलकर विवि में झंडा फहराने की योजना बनाई, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की आग को देखते हुए विवि की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। ऐसे में जय नारायण और उनके कुछ साथी एक दिन पहले ही विवि के कला प्रांगण की छत पर छिपकर बैठ गए। अगले दिन गवर्नर जनरल हेटली और मुख्यमंत्री पंत के आने से कुछ देर पहले उन्होंने ब्रिटिश झंडे को उतारकर तिरंगा फहरा दिया था।

1922 में हरियाणा के झज्जर में फहराया तिरंगा- हरियाणा के झज्जर जिले का टाउन हाल आजादी का गवाह है। 15 जनवरी 1922 को



स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा ने टाउन हाल पर लोगों की भीड़ के साथ यहां तिरंगा झंडा लहराया था। हालांकि, स्वतंत्रता सेनानी और उनके सहयोगियों को अंग्रेजी हुकूमत ने इसकी कठोर सजा दी। लोगों की भीड़ पर लाठीचार्ज कर झंडा उतरवा दिया गया। वहीं, श्रीराम शर्मा को कोड़े मारे गए और जीप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा गया, लेकिन यह यातना उनके हौंसले को नहीं तोड़ पाई।

जबलपुर के टाउन हॉल में लहराया तिरंगा- मप्र के जबलपुर जिले में पहली बार अक्टूबर 1922 में विक्टोरिया टाउन हॉल पर तिरंगा फहरा



दिया गया था। देश में आजादी के लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे। असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस की एक समिति जबलपुर आई थी। शहर के विक्टोरिया टाउन हॉल में आंदोलन को लेकर सदस्यों को अभिनंदन पत्र दिए जा रहे थे। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल की इमारत पर तिरंगा फहरा दिया। तब से यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।

कामरूप और दरंग जिलों में किसान के आंदोलन हुए। 1896-97 में महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन चले। 1896 और 1900 के बीच के अकालों में 90 लाख से अधिक देशवासी मारे गए। 1910 में बस्तर व 1913 में दक्षिण आंध्रप्रदेश में आदिवासियों ने वनाधिकारों के हनन के विरुद्ध विद्रोह किए। ओडिशा के खोंड आदिवासियों का एक विद्रोह 1915 के आसपास हुआ, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहां के अनेक गांवों को जला दिया था। दक्षिण राजस्थान में गोविंद गुरु के समाज सुधार प्रयासों ने 1913 में एक जन विद्रोह का रूप ले लिया। मनगढ़ के पहाड़ पर 4,000 भीलों ने अंग्रेजी फौज का डटकर सामना किया, जिसमें 12 आदिवासी मारे गए व 900 गिरफ्तार हुए।

मेवाड़ की बिजोलिया जागीर में किसानों को 86 तरह के कर देने पड़ते थे। इसके विरुद्ध एक साधु सीतारामदास के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1917 में वह चंपारण गए, जहां के किसानों के आंदोलन के फलस्वरूप सरकार उनकी समस्याओं को कम करने के लिए बाध्य हुई। अगले वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूले जाने पर गांधी के नेतृत्व में हुए प्रयासों से लगान में छूट मिली। अलवर के नीमूचाणा में 50 फीसदी लगान वृद्धि का विरोध कर रहे किसानों पर गोली चलाई गई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। 1928 में बारदोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने कर न देने का आंदोलन चलाया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के नाम का पहला राष्ट्रीय स्तर का किसान संगठन बना। उसके बाद आजादी मिलने तक अनेक स्थानों पर आदिवासी व किसान आंदोलनकारी सक्रिय रहे। इस तरह देश को स्वतंत्र कराने में किसानों और आदिवासी आंदोलनों का भी काफी अहम योगदान रहा है।

भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अजली लाश छोड़कर भागे थे अंग्रेज

24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। भगत इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। 22 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखे आखिरी खत में भगत ने कहा- जीने की इच्छा



कानपुर के बूढ़ा बरगद पर 133 क्रांतिकारियों को हुई थी फांसी

कानपुर का जो बूढ़ा बरगद है, इसकी जड़ों में पानी नहीं आजादी के मतवालों का खून है, आंसू हैं। टहनियां बेशक सूख चुकी हैं लेकिन जखम अब तक हरे हैं। दरअसल, यह बरगद का पेड़ गवाह है 1857 की उस क्रांति का जो क्रांति भूमि कानपुर में ज्वालामुखी बनकर भड़की थी। कैसे भारतमाता के वीर सपूतों का खून खोला था। यह सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, भुक्तभोगी भी है अंग्रेजी हुकूमत के आतंक का। इस बूढ़े बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों पर 4 जून, 1857 को एक साथ 133 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह यह बूढ़ा बरगद आज भी नानाराव पार्क में है। बूढ़े बरगद को लेकर इतिहासकार बताते हैं कि वर्ष 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 विद्रोह की ज्वाला भड़की, जो कानपुर तक पहुंच गई। कानपुर के क्रांतिकारी देश को आजाद कराने का संकल्प ले चुके थे। उनसे घबराकर अंग्रेजों ने कानपुर छोड़ने का फैसला किया था। 27 जून, 1857 को सैकड़ों अंग्रेज अपने परिवार के साथ समझौते के लिए सतीचौरा घाट से नावों में सवार होकर इलाहाबाद के लिए रवाना हो रहे थे तभी तात्याटोपे, बाजीराव पेशवा और अजीमुल्ला खां भी वहां पर मौजूद थे। नानाराव पेशवा करीब दो किलोमीटर दूर थे। उसी दौरान गलतफहमी में कुछ अंग्रेजी अफसरों ने गोलियां चला दीं, जो कई क्रांतिकारियों को लग गईं। इसके जवाब में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया था। इसमें करीब 250 से अधिक अंग्रेज मारे गए थे।

मुझमें भी है, ये मैं छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में फांसी से बचने का लालच कभी नहीं आया। मुझे बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। जल्दी ही वो दिन भी आया और 23 मार्च 1931 को तय वक्त से 12 घंटे पहले ही, शाम 7 बजकर 33 मिनट पर भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। गंगापुर से करीब 20 किलोमीटर दूर फैसलाबाद-जड़ानवाला रोड पर भगत सिंह के गांव बंगा को लोग भगतपुर के नाम से पहचानने लगे हैं। उनका घर ये एकदम आम घरों जैसा ही नजर आता है। हालांकि, इस गांव के लोगों ने इस घर और इससे जुड़ी चीजों को काफी संभाल कर रखा हुआ है। भगत का घर अब जमात अली विर्क की संपत्ति है। बंटवारे के बाद उनके दादा सुल्तान मुल्क को यह घर सरकार की तरफ से मिला था। भगत के घर को अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहां भगत, उनके साथियों और परिवार की दुर्लभ तस्वीरें मौजूद हैं। भगत की हवेली में दो कमरे और एक आंगन है। भगत के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और सोरन सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस गांव में आज भी वो स्कूल मौजूद है, जहां भगत ने अपनी पढ़ाई की थी। अब इस स्कूल का नाम भगत सिंह के नाम पर ही रख दिया गया है। जमात अली बताते हैं- बंटवारे के बाद भगत सिंह के भाई कुलबीर सिंह 1985 में पहली बार यहां आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि यह घर भगत सिंह के परिवार का है। हमने तभी से इसे संभाल कर रखा है। गांव के लोगों का दावा है कि भगत सिंह के हाथ का लगाया हुआ आम का पेड़ आज भी इस घर के आंगन में मौजूद है।

काकोरी कांड की एकमात्र गवाह बनी सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर

देश की आजादी तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराया था। इतिहास के पन्नों में इन शहीदों की शौर्य गाथा दर्ज है। चाहे वो चौराचौरी की घटना हो या फिर काकोरी कांड इन सभी घटनाओं का मकसद ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाना था। आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस आजादी के पीछे क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं झेलीं इस बात की गवाही आज भी सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन दे रही है। ये वही पैसेंजर गाड़ी है जो सरकारी खजाने को लेकर सहारनपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी लेकिन काकोरी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर युवा क्रांतिकारियों ने इस खजाने को देश की आजादी के लिए लूट लिया था। बता दें कि, काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 में हुई। उस वक्त देश की आजादी के लिए संघर्ष तेज हो चुका था और युवा क्रांतिकारियों का एकमात्र मकसद था कि आजाद भारत का सपना कैसे भी साकार हो। तभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के लिए सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। जिसमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह समेत अन्य क्रांतिकारियों की भूमिका थी। उस दौर में सहारनपुर क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहां अक्सर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस समेत कई बड़े क्रांतिकारियों की बैठकें आयोजित की जाती थी। बता दें कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर पैसेंजर सरकारी खजाने को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई और इस खजाने को लूटने के लिए कुछ क्रांतिकारी हरदोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन की बोगी में सवार हो गए। जबकि अन्य क्रांतिकारी काकोरी रेलवे स्टेशन में ट्रेन की अलग बोगी में चढ़ गए।



याद रहनी चाहिए विभाजन की विभीषिका

देश का विभाजन एक अमानवीय त्रासदी थी। वह अपने साथ भारत का दुर्भाग्य लाई थी। इतिहास के इस कलंकित अध्याय से सबक लेने के लिए ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की पहल हुई। विभाजन के बाद बने पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ क्रूरता की पराकाष्ठा की गई। मंदिरों-गुरुद्वारों में शरणागतों को जलाकर मार डालती उन्मादी भीड़ का बोलबाला था। उत्पीड़न से मजबूर होकर पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। वहां से आने वाली शवों से अटी पड़ी रेलगाड़ियों की स्मृतियां आज भी सिहरन पैदा करती हैं। ऐसे भीषण सांप्रदायिक संघर्ष के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिलहाल हम एक अस्थायी युद्धविराम में हैं। इसका ही प्रमाण है कि पाकिस्तान और बाद में उससे अलग हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या निरंतर घटने पर है। उनकी प्रताड़ना जारी है। आए दिन नाबालिग हिंदू बच्चियों का अपहरण कर उनका बलात मतांतरण कराकर निकाह करा दिया जाता है। अब तो इसे लेकर वहां सवाल भी

नहीं किए जाते हैं। लगता है कि सारी संवेदनाएं मर गई हैं। हमारे देश की वोटपरस्त राजनीति ने भी कभी उनकी सुध लेना गवारा नहीं समझा।

जहां पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार हो रहे थे, वहीं भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों की ढाल बने हुए थे। उन्होंने न केवल मुस्लिमों की रक्षा की, बल्कि उन्हें आश्वस्त कर भारत में बसे रहने के लिए प्रेरित भी किया। यहां नेहरू-लियाकत पैक्ट को नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें यही शर्त थी कि दोनों देश अपने-अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। वर्ष 1950 में हुए इस समझौते का भारत ने तो अक्षरशः पालन किया, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते गए। समझौते का उलटा ही असर हुआ। इसने पाकिस्तान के हिंदुओं का भारत आना रोक दिया। इस कारण हिंदू और सिखों को या तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ा या फिर वे मौत के घाट उतार दिए गए। वहां जो आज बचे-खुचे हिंदू हैं, वे विश्व के सबसे प्रताड़ित समाजों में से एक हैं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सभा के बाद भड़की थी विद्रोह की आग

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में उत्साह फूंकने के लिए देश भ्रमण पर निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1941 में मनीगाछी पहुंचे थे। यहां आयोजित सभा में उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को आंदोलित किया था। इसके बाद यहां के लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की थी। मनीगाछी प्रखंड के मकरंदा गांव निवासी महान स्वतंत्रता सेनानी स्व. कंटीर झा उर्फ गांधी ने अपनी डायरी में इस बात का उल्लेख किया है। डायरी के अनुसार मनीगाछी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम की रूपरेखा कंटीर झा ने ही तैयार की थी। स्व. कंटीर झा उर्फ गांधी जी की डायरी में लिखी बातों को यारों की याद नामक पुस्तक में भी संकलित किया गया है। इस पुस्तक को उनके पौत्र प्रो. टुनटुन झा अचल ने लिखा है। पुस्तक के पृष्ठ 12 पर भी इन बातों का उल्लेख है। प्रो. टुनटुन झा अचल ने बताया कि वर्ष 1941 में सुभाष बाबू का भाषण सकरी-राघोपुर के बीच एक मैदान में हुआ था। वहां आम लोगों के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे भी उन्हें देखने-सुनने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उस समय बलौर मध्य विद्यालय की पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले स्व. सीताराम झा ने बताया था कि सुभाष बाबू का नाम सुनकर ही स्कूल के बच्चे उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सुभाष बाबू के भाषण से क्रांतिवीरों में नया जोश पैदा हो गया था। यहां से सुभाष बाबू गोमो के लिए प्रस्थान कर गए जो पुनः लौटकर नहीं आए। प्रो. झा ने इस दौरान हुए एक और वाक्य के बारे में बताया कि वर्ष 1941 में सुभाष बाबू ने दरभंगा महाराज स्व. कामेश्वर सिंह से उनके निवास स्थान नरागौना पैलेस में मुलाकात की थी। सुभाष बाबू के आगमन की सूचना पाकर महाराज लिफ्ट के बदले पैदल ही सीढ़ियों से नीचे उतरे और सुभाष बाबू का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सुभाष बाबू को मुहरों से भरी एक थैली भी भेंट की।

अब भ्रष्टों पर कसेगा शिकंजा



उच्चतम न्यायालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिले अधिकारों के खिलाफ कई नेताओं समेत अन्य लोगों की ओर से दायर 200 से अधिक याचिकाओं का निपटारा करते हुए जिस तरह इन अधिकारों को उचित ठहराया, वह इस जांच एजेंसी को बल प्रदान करने और साथ ही अपनी काली कमाई को सफेद करने की कोशिश में लिप्त तत्वों को हतोत्साहित करने वाला है। यह किसी से छिपा नहीं कि काले धन का काला धंधा किस तरह बढ़ता जा रहा है और इस धंधे में किस तरह नेता और नौकरशाह भी लिप्त हैं? इसका ताजा उदाहरण बंगाल के हटाए गए वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी हैं, जिनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों से करीब 50 करोड़ रुपए की नकदी के साथ सोना, विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त जमीन-जायदाद के कई दस्तावेज मिले हैं।

काला धन अर्जित करने वालों पर लगाम लगाने के लिए पीएमएलए वर्ष 2002 में लाया गया था, ताकि भारत अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता के तहत काले धन को सफेद करने के तौर-तरीकों पर रोक लगा सके। यह कानून लागू हुआ 2005 में, जब मनमोहन सरकार सत्ता में थी। इसके बाद इसमें समय-समय पर संशोधन हुए। एक संशोधन तो तब हुआ, जब वित्तमंत्री पी. चिदंबरम थे। बाद में वह और उनके बेटे ईडी की जांच के दायरे में आए। उक्त संशोधन से ईडी की शक्तियां बढ़ीं। निसंदेह मनमोहन सरकार के समय ईडी उतनी सक्रिय नहीं थी, जितनी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दिख रही है, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसकी ओर से जब्त की गई संपत्ति यही बताती है कि काले धन को सफेद करने का सिलसिला तेज हुआ है। एक अनुमान के अनुसार ईडी अब तक एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। यह संपत्ति विभिन्न घपलों-घोटालों के जरिए हासिल की गई थी। इनमें बैंकिंग घोटाले भी थे।

ईडी ने कुछ संपत्ति की नीलामी कर बैंकों को वापस भी की है। एक समय था, जब ईडी के निशाने पर आमतौर पर उद्योगपति ही रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे नेता और नौकरशाह भी उसकी जांच के दायरे में आते गए। आज ऐसे नेताओं और नौकरशाहों की गिनती करना कठिन है, जो ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, लालू यादव, महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख, नवाब मलिक आदि शामिल हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि ईडी के अधिकारों के खिलाफ तमाम याचिकाएं ऐसे ही अनेक नेताओं की ओर से भी दाखिल की गई थीं। ईडी ने जिस तरह 2019-20 में 28 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति

जब्त की, उससे यही पता चलता है कि काला धन बटोरने वाले किस तरह बाज नहीं आ रहे हैं। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि ईडी की सक्रियता कायम रहे। जो लोग ईडी के अधिकारों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे, उनकी एक शिकायत यह थी कि इस एजेंसी को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के मनमाने अधिकार दे दिए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय इस दलील से सहमत नहीं हुआ। उसने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि औपचारिक शिकायत के बगैर ईडी को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को भी सही नहीं माना कि खुद को बेगुनाह साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर नहीं होना चाहिए। वास्तव में यदि किसी के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अकूत संपत्ति मिली हो तो यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसी पर होनी चाहिए कि उसके पास इतनी संपदा कहां से आई? उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यह आशा की जाती है कि ईडी जिन तमाम मामलों की जांच कर रही है, उनमें तेजी आएगी और इस तरह के राजनीतिक स्वर थमंगे कि मोदी सरकार ईडी का मनमाना इस्तेमाल कर रही है। इन दिनों इस तरह के आरोप लगाने में कांग्रेस सबसे आगे है। इसका कारण नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ करना है। कांग्रेस नेता ईडी की कार्रवाई का जैसा विरोध संसद के भीतर और बाहर कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वे गांधी परिवार को कानून से ऊपर समझते हैं। चूंकि कांग्रेस नेता इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी जमानत पर हैं, इसलिए आम जनता इस तरह के आरोपों को महत्व देने को तैयार नहीं कि ईडी का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है।

काला धन हासिल करने वालों के खिलाफ

सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि खुद उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मनी लाँड्रिंग न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करती है, बल्कि आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी जैसे अपराधों को भी बढ़ावा देती है। जो यह आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के कारण लोकतंत्र का गला घुट रहा है, वे यह समझें तो बेहतर कि लोकतंत्र का गला अकूत रूप में जुटाए गए काले धन से भी घुट रहा है।

● विपिन कंधारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित... **75**
अमृत महोत्सव
राजिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बैरसिया, जिला - भोपाल

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित... **75**
अमृत महोत्सव
राजिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, पचोर, जिला - राजगढ़

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित... **75**
अमृत महोत्सव
राजिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, नरसिंहगढ़, जिला - राजगढ़

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित... **75**
अमृत महोत्सव
राजिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, बरेली, जिला - रायसेन

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित... **75**
अमृत महोत्सव
राजिव ● भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरा, जिला - रायसेन

6

पिछले 8 साल से देश में तेजी से विपक्षी पार्टियों का पतन हो रहा है। आज स्थिति यह है कि सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष सत्तापक्ष को घेरने में फेल हो रहा है। इसकी वजह है विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव। दरअसल, विपक्षी दल की अपनी कोई एक लाइन नहीं है। देश में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष मौके पर उन मुद्दों को उठाने में असफल हो रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि भाजपा दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है और विपक्ष का जनाधार घटता जा रहा है।



मुद्दों के संकट से जूझता विपक्ष

भारतीय राजनीति और संसदीय प्रणाली का विश्लेषण करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था- 'यह देखकर अफसोस होता है कि समय बीतने के साथ संसदीय प्रणाली चलाने के लिए जो परिपक्वता आनी चाहिए, उसके बजाय संसदीय व्यवहार में निरंतर गिरावट आ रही है। आज राजनीति करने के दो ही उद्देश्य रह गए हैं- समाज में लोगों का समर्थन कैसे मिले? कुछ भी, कैसे भी करके; चाहे गलत करके, चाहे सही करके। दूसरा, पैसे कैसे मिलें?'

यह भारतीय राजनीति का वह सत्य है, जिससे मुंह तो मोड़ा जा सकता है, किंतु नकारा नहीं जा सकता। पक्ष-विपक्ष की कौन कहे, यहां कमोबेश सब एक जैसे ही हैं। लेकिन इस समय **चर्चा का विषय विपक्ष** है। एक संतुलित एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए एक जागृत एवं सशक्त विपक्ष होना आवश्यक है। लेकिन भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर ऐसा नहीं है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह कालखंड संघर्ष-हीन विपक्ष के दौर के तौर पर गिना जाएगा, जहां चुनाव-दर-चुनाव हार के बाद आज विपक्ष हताश-निराश और भ्रमित हैं। उसमें सत्तापक्ष के समक्ष खड़े होने का जज्बा नहीं दिखता। विपक्ष मुद्दों की राजनीति के बजाय अनर्गल विरोध प्रसंगों में लिप्त हैं, जिससे जनता में उसके प्रति लगाव एवं समर्थन न्यून स्तर पर पहुंच चुका है।

ताजा विवाद नए संसद भवन में लगे अशोक स्तम्भ को लेकर शुरू है। विपक्ष का आरोप इतिहास से छेड़छाड़ तथा अशोक स्तम्भ के शेरों को ज्यादा आक्रामक प्रदर्शित करने

का है। कोई इसे सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते कह रहा है। किसी के अनुसार यह राष्ट्र विरोधी है। इस पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का विरोध है कि अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। कांग्रेस नाराज है कि कार्यक्रम में उसे न्यौता क्यों नहीं दिया गया? तो सीपीएम का विरोध प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पूजा-पाठ करने को लेकर है। इन आरोपों पर सत्तापक्ष भी कहां खामोश रहने वाला था, सो जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रवक्ताओं का पूरा समूह टूट पड़ा।

प्रतीत होता है कि देश की राजनीति में मुद्दों का संकट है। वास्तव में यह संकट उस चेतना की अनुपस्थिति का है, जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को अंगीकार कर सके। विपक्ष को इस बात की चिंता है कि राष्ट्रीय चिन्ह के शेर खतरनाक दिख रहे हैं, जो शांत थे। यह अजीब-सा हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण विवाद है। शेर कैसे दिख रहे हैं? देश की 135 करोड़ से ज्यादा आबादी को इससे कहीं ज्यादा रुचि अपनी रोजी-रोटी और सिर पर छत पाने, अपराध से मुक्ति, मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन जीने जैसे मूलभूत मसलों में है। वास्तव में विपक्ष को जिन मुद्दों को लेकर

सत्ता से बाहर होने की वजह नहीं तलाश पा रही विपक्षी पार्टियां

समस्या यह है कि इस राजनीतिक दुर्गति के पश्चात आज भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल यह समझने को तैयार नहीं हैं कि वे क्यों पिछले 7-8 वर्षों से राज्य हो या केंद्र, हर जगह से सत्ता से बाहर धकेले जा रहे हैं? क्योंकि वे आम जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सत्तापक्ष मुद्दों से देश को भटका रहा है। लेकिन वह नहीं समझ रहा है कि वह खुद भी सही मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। इसीलिए सत्तापक्ष जिस चक्रव्यूह में विपक्षियों को फंसाना चाहता है, वे उसमें फंस रहे हैं। संभवतः विपक्ष समय की धारा को पहचानने में चूक कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि क्यों भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में जमी हुई है, और निरंतर आगे बढ़ती जा रही है? किसी भी व्यक्ति, संस्था या समाज की मृत्यु तब होती है, जब वह जिज्ञासा की भावना खो देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखते हैं कि किसी बात की जानकारी न हो, तो उतना बुरा नहीं है, जितना कि जानने की इच्छा न होना।



विपक्षी को मोदी की कार्यशैली का अध्ययन जरूरी

विपक्ष को भाजपा और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार को समझने की जरूरत है। संप्रग सरकार के कार्यकाल में सन् 2014 के लोकसभा चुनावों के कुछ महीने पहले तक सत्ता विरोधी लहर चरम पर पहुंच चुकी थी। देश में राजनीतिक वातावरण क्षुब्ध था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सरकार की गरिमा रसातल में पहुंच चुकी थी। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने उन कमियों को जोर-शोर से लोगों के बीच उठाया और साथ में अपने नेतृत्व का विकल्प सामने रखा। उस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के सुशासन ब्रांड गुजरात मॉडल का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार हुआ। साथ ही गैर-वंशवादी पृष्ठभूमि, स्वनिर्मित छवि एवं साफ-सुथरी छवि ने नरेंद्र मोदी के कद को बड़ा केंद्रीय फलक दिया। अब इस कसौटी पर विपक्ष को देखिए, जिसके लिए यह तसखुर की कंगाली का दौर है। वर्तमान राजनीति ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, जहां सत्तापक्ष द्वारा खींची गई लकीर पार करने का विपक्ष में साहस ही नहीं दिख रहा है। सत्तापक्ष हावी है एवं अपने पक्ष में व्यापक जन-समर्थन को मोड़ने के साथ ही अपनी कार्यनीति को बहुत हद तक लागू करने में सफल भी हुआ है, क्योंकि वह ज्यादा जागृत एवं गतिशील है। अब इसी के बरअक्स विपक्ष को स्व-मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

आक्रोशित होना चाहिए, वे उसकी प्राथमिकता सूची में हैं ही नहीं।

राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर 7.80 फीसदी है। इस वर्ष यह दर 0.68 फीसदी बढ़ी है। साथ ही कुल श्रमबल में काम करने वालों की संख्या घटकर 39 करोड़ रह गई है। सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है? कब तक स्थितियां बेहतर होने की उम्मीद है? निजीकरण के कारण घटती नौकरियों की भरपाई सरकार कैसे करेगी? केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक लाखों की संख्या में विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियां अब तक क्यों नहीं भरी गईं? इन्हें कब तक भरा जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों के चयन के अवसर सिमटते क्यों जा रहे हैं? इसके लिए दोषी कौन है? अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे लोगों को आतंकवादी एवं देशद्रोही कहने वाले पार्टी नेताओं से जवाब कब लिया जाएगा? हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नमामि गंगे परियोजना कितनी सफल रही? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पौराणिक महत्व की गंगा नदी की इतनी बुरी हालत क्यों है? मेक इन इंडिया योजना (2014) ने इतने वर्षों में अर्थ-व्यवस्था को कितना लाभ पहुंचाया, और कितने रोजगार सृजित किए?

सरकार के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर कब तक अंकुश लगेगा? उग्र सरकार में लोक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल शक्ति विभाग में तबादलों में हुई धांधली एवं पशुपालन विभाग में होने वाले 50 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई कब तक होगी? उग्र लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में की जा रही मनमानी पर रोक कब तक लगेगी? आयोग में नियुक्तियों में हुई धांधली पर इतने वर्षों से चल रही जांच कहाँ तक पहुंची? जांच कब तक पूरी होगी? अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? निकट में हुई कई भर्तियों में जैसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-50 के अंतर्गत विभिन्न विषय में सहायक प्रोफेसर पर हुई नियुक्ति पर भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपों का संज्ञान कब तक लिया जाएगा?

ऐसे ही और भी कई मूलभूत मसले हैं, जिन पर विपक्ष को आंदोलित होना चाहिए। लेकिन उसे न इनसे कोई मतलब है और न सार्थक राजनीति से कोई सरोकार है। ले-देकर उसके पास सिर्फ धार्मिक, असहिष्णुता और अघोषित आपातकाल के नारे हैं, जिन्हें वह बार-बार दोहराता रहता है। विपक्ष की राजनीति को

देखकर लगता है कि वह इस भरोसे बैठा है कि सत्तापक्ष और गलतियां करें, और नाराज जनता विकल्प के रूप में उसे चुन ले। लेकिन वह भूल रहा है कि वास्तव में देश के मतदाताओं के लिए विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो चुकी है। मप्र के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सशक्त उपस्थिति मतदाताओं की इसी कुंठा का प्रतिफल है। हालांकि आम आदमी पार्टी से उम्मीद पालना ठीक नहीं। क्योंकि दिल्ली में जो इनकी हालत है और पंजाब में हत्याओं और भ्रष्टाचार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे इनकी कार्यशैली के प्रति निराशा ही उपजती है। हालांकि छवि तो किसी भी दल की साफ-सुथरी नहीं है। पर इस समय देश की जनता की मनोस्थिति यह है कि वह कई मसलों पर सत्तापक्ष से निराशा और क्रोधित होने के बावजूद भी विपक्ष को अपना विकल्प नहीं समझ रही क्योंकि विपक्ष को जो परिपक्वता दिखानी चाहिए, वह नहीं दिखा पा रहा है। रही-सही कसर विपक्ष के वाग्वीर पूरी कर रहे हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अनर्गल बोलकर वे अल्पसंख्यक और कुछ विशेष वर्गों का पुरजोर समर्थन पा पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत होता यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग उन्हें समर्थन दे दे, तो बहुसंख्यक वर्ग पूरे दमखम से उससे घृणा करना शुरू कर देता है।

दरअसल विपक्षी दलों के नेता अपने परिजनों की राजनीतिक वृत्ति (कैरियर) से परे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। उनकी प्राथमिकता अपनी राजनीतिक विरासत को बचाकर अपने बेटे-बेटियों के लिए सुरक्षित रखने में है। साथ में ईडी और सीबीआई की जांच से बचने का दबाव है ही। वास्तव में विपक्ष अकर्मण्य वंशवादियों की जमात बन चुका है। राजनीति में अभिजनवाद का रोग बड़ा पुराना है। यह रोग एक बार किसी को जकड़ ले, तो बर्बाद करके ही छोड़ता है। वर्तमान में जो विपक्षी नेतृत्व दिख रहा है, उनमें ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेताओं, जैसे- जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आदि के राजनीतिक अवशेष मात्र की तरह हैं। उपरोक्त नेताओं के इन अभिजन (एलीट) उत्तराधिकारियों के पास न सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की क्षमता है, न जनता को देने के लिए कोई परिकल्पना (विजन) है। अगर कुछ है, तो सिर्फ भावनात्मक कहानियां, जिनका जनता के लिए कोई विशेष जुड़ाव या मतलब नहीं है। इसके अतिरिक्त विपक्ष के पास जातिवाद और धर्म के परम्परागत मुद्दे तो हैं, किंतु दिक्कत यह है कि इन मुद्दों से संबंधित अधिक पैने हथियार सत्तापक्ष के पास भरे पड़े हैं, जो विपक्ष से कहीं ज्यादा कारगर भी साबित हो रहे हैं।

● इंद्र कुमार

छत्तीसगढ़ में बदलाव हो रहा है, इस बात के संकेत यहां होने वाली नक्सली घटनाओं में तेजी से आ रही गिरावट से मिल रहे हैं। कभी यहां हर साल 500 से 600 घटनाएं हुआ करती थीं जो अब महज 250 पर आकर सिमट गई हैं। आधिकारिक तौर पर मिले आंकड़े बताते हैं कि बीते साढ़े तीन सालों से राज्य में नक्सली घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। वर्ष 2008 से लेकर 2018 तक के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस दौरान राज्य में नक्सलियों द्वारा हर साल 500 से लेकर 600 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, जो कि बीते साढ़े तीन सालों में घटकर औसतन रूप से 250 तक सिमट गया है। वर्ष 2022 में अब तक मात्र 134 नक्सल घटनाएं हुई हैं, जो कि 2018 से पूर्व घटित घटनाओं से लगभग चौथाई है।

राज्य में वर्ष 2018 से पूर्व नक्सली मुठभेड़ के मामले प्रतिवर्ष 200 के तकरीबन हुआ करते थे, जो अब घटकर दहाई के आंकड़े तक सिमट गए हैं। वर्ष 2021 में राज्य में मुठभेड़ के मात्र 81 तथा वर्ष 2022 में अब तक 41 मामले हुए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामलों में भी तेजी आई है। बीते साढ़े तीन सालों में 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़ा 10 सालों में समर्पित कुल नक्सलियों की संख्या के एक तिहाई से अधिक है। राज्य में आ रहे बदलाव पर गौर करें तो बस्तर संभाग के 589 गांवों के पौने छह लाख ग्रामीण, नक्सलियों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक 121 गांव सुकमा जिले के हैं। दंतेवाड़ा जिले 118 गांव, बीजापुर जिले के 115 गांव, बस्तर के 63 गांव, कांकेर के 92 गांव, नारायणपुर के 48 गांव, कोण्डागांव के 32 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 की स्थिति में नक्सल समस्या प्रदेश के दो तिहाई क्षेत्र में फैल गई थी। बड़ी-बड़ी नक्सल वारदातों में सुरक्षाबलों के जवानों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व एवं आम नागरिक मारे गए। नक्सलियों के हिंसक वारदात के चलते अनेक स्कूल एवं आश्रम बंद हो गए। इस दौरान सड़क, पुल-पुलियों को भी नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त किया। नक्सल आतंक के कारण बस्तर संभाग में वर्षों से बंद 363 स्कूलों में से 257 स्कूल फिर से बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए शुरू हो गए हैं, जिसमें से 158 स्कूल बीजापुर जिले के, 57 स्कूल सुकमा तथा दो कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हैं। इसके साथ ही 196 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। बस्तर अंचल में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रभावी कदम के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, बस्तर फाइटर्स एवं जिला पुलिस बल में भर्ती का अधिक अवसर मिलने से माओवादियों संगठनों की भर्ती में कमी आई है। छत्तीसगढ़ के बदलते हालातों के चलते बस्तर संभाग में माओवादी संगठन की गतिविधि दक्षिण बीजापुर,

नक्सली पड़े नरम

दक्षिण सुकमा, इन्द्रावती नेशनल पार्क का इलाका, अबुझमाड़ एवं कोयलीबेड़ा क्षेत्र के केवल अंदरूनी हिस्से तक सिमटकर रह गई है।

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार व अफसरों के नक्सलियों को रोकने के तमाम दावे फेल हो गए हैं। जिन नक्सलियों को बैकफुट पर बताया जा रहा था, वही तेलंगाना की सीमा पार कर छत्तीसगढ़ में

घुस आए। न केवल इन नक्सलियों ने पहली बार साथियों की याद में 64 फीट ऊंचा स्मारक बना दिया, बल्कि 12 हजार ग्रामीणों को साथ लेकर विशाल रैली भी निकाल दी। खास बात यह है कि इसमें 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक के ईनामी नक्सली शामिल थे। बावजूद इसके पुलिस और इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं लगी। दरअसल, नक्सलियों ने बस्तर में 3 अगस्त को शहीदी सप्ताह मनाया था। इस दौरान दक्षिण बस्तर के एक गांव में हजारों की संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे।

● रायपुर से टीपी सिंह

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, सिरोंज, जिला-विदिशा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, कुरावर, जिला - राजगढ़

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा, जिला - राजगढ़

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, खिलवीपुर, जिला - राजगढ़

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बेगमगंज, जिला - रायसेन

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, रायसेन

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, औबेदुल्लागंज, जिला - रायसेन

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया, जिला - हरदा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बनखेड़ी, जिला - होशंगाबाद

सरकार और अफसरों की लाख कोशिशों के बावजूद संगीन अपराध बेइंतहा फलने-फूलने लगता है, तो इस बात को पूरी तरह मुहरबंद करता है कि इसके पीछे

तस्करों के हौसले बुलंद

किसी बड़ी राजनीतिक ताकत या सरकारी विभागों के गठजोड़ का पहलू जुड़ा हुआ है। राजस्थान में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के बावजूद रोकथाम निरर्थक साबित हो रही है, तो इसकी भी यही वजह हो सकती है। इस मामले में राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी) एमएल लाटर की रेंज के महानिरीक्षकों से की गई जवाब तलबी इस बात की पुष्टि करती है। लाटर द्वारा जारी चिट्ठी में 'वर्दी में छिपे ब्लेक शिप्स' की रिपोर्ट मांगते हुए बड़ी बेबाकी से कहा गया है कि लगातार सामने आ रही घटनाओं से लगता है कि संगठित अपराध का इतना हौसलामंद होना पुलिस और व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों की जानकारी और मौन स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। भीलवाड़ा में तस्करों की फायरिंग में जिस तरह दो जवानों की मौत हुई, उसके बाद ही इस बात का खुलासा हुआ है। इसमें सीमावर्ती और नजदीकी जिलों के 13 थाने संदेह के घेरे में आए हैं।

सवाल उठा कि जब तस्करों की गाड़ियां इसी रूट से निकल रही थीं, तो पुलिस कैसे बेखबर हो सकती थी? पिछले दिनों भीलवाड़ा से निकल रहे ड्रग (मादक पदार्थ) तस्करों को रोका, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई। इसी गिरोह ने दूसरी जगह फायरिंग करके दूसरे कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। पड़ताल में सामने आया कि गिरोह ने नया रूट पकड़ा था, जिससे उनकी मिलीभगत का खेल नहीं चल सका। सुनील डूडी और कुख्यात राजू फौजी उर्फ राडू द्वारा गिरोह मिलकर पांच वाहनों में मादक पदार्थ ले जा रहे थे। सुनील डूडी के पकड़े जाने पर मिलीभगत का खेल उजागर हुआ।

मादक पदार्थ तस्करों का रास्ता सीमावर्ती जिलों से शुरू होता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ कोटा ग्रामीण क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही है। यहां अफीम को अवैध रूप से परिष्कृत कर ब्राउन शुगर और स्मैक बनाने का काम भी होता है। यहां से मादक पदार्थ दो हिस्सों में जाता है। इसमें एक हिस्सा मारवाड़ या अन्य इलाकों से होता हुआ पंजाब जा रहा है। भीलवाड़ा में मादक पदार्थ व पाली में तेल चोरी मामले की घटना में भयावह प्रमाण मिले हैं। गोपनीय जानकारियों से स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों की घुसपैठ व पुलिस तंत्र के भीतर तक है। पुलिस महानिदेशक ने यहां तक कहा कि हम जब तक सफल नहीं हो सकते, तब तक कि वर्दी में छिपे अपराधियों की पहचानकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए तथा पुलिसकर्मियों से सुपरवाइजरी अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्धारण भी करें। जवानों पर फायरिंग करने वाले कुख्यात राजू फौजी उर्फ डारा को कांस्टेबल ने ही फरार कराया था। उस पर 11 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीआरपीएफ का पूर्व जवान डारा पहली बार सन् 2017 में चर्चा में आया था, जब बाड़मेर में टोल प्लाजा पर फायरिंग की थी। फरारी में ही वह चित्तौड़ से मारवाड़ तक तस्करों कर रहा था। भीलवाड़ा की घटना के बाद राजू फौजी को जोधपुर रेंज के टॉप 10 अपराधियों में शामिल किया गया। मादक पदार्थ तस्करों से 13 थानों में मिलीभगत का खेल उजागर हुआ है। यह केवल दो गिरोह की पड़ताल में सामने आया है। ऐसे कई गिरोह क्षेत्र में सक्रिय हैं। पड़ताल में पता चला है कि हर थाने में एक ट्रिप के 5,000 रुपए देते थे। बंधी (इस धंधे) के लिए संपर्क (लाइजनिंग) खास सिपाही करते हैं, जिन्हें गिरोह अलग से भुगतान करते हैं। अब आला अधिकारी यह जानकारी जुटा रहे हैं कि इनमें थाना अधिकारियों की कितनी भूमिका है?

पड़ताल में यह भी सामने आया कि एस्कॉर्ट करने वाले ही थानों से सांठगाठ करते हैं। वे पहले किसी पुलिसकर्मी को पकड़ते, उसके जरिये एक से दूसरे थाने में मिलीभगत के रिश्ते बढ़ाते हैं।

चित्तौड़गढ़ से जोधपुर जाते समय पकड़े 43 किलो कुंतल (क्विंटल) डोडा (अफीम का पोस्त) पूरा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें जोधपुर के सफेदपोश भागीरथ जाणी का नाम सामने आया है। भागीरथ जाणी ने ही खेप जोधपुर में आपूर्ति (सप्लाइ) के लिए मंगाई थी। हालांकि उससे पहले ही सीआईडी ने उसे चित्तौड़ के मंगलवाड़ में पकड़ लिया। पड़ताल में भागीरथ का नाम सामने आया, तो उसे दर्ज मामलों में नामजद किया गया। तस्कर खेप जल्द पहुंचाने के लिए वाहनों को तेज गति से दौड़ाते हैं। वे ट्रक जैसे बड़े वाहनों के बजाय छोटे वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान माई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलाणी के समय किसान माई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बड़वानी, जिला-बड़वानी

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान माई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलाणी के समय किसान माई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर

ए कनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे अब अपनी पार्टी को बचाने

बिगड़ी बनाने उतरे आदित्य

में जुट गए हैं। इसके पूर्व उनकी इस बात के लिए आलोचना होती थी कि वे मुंबई में बॉलीवुड सितारों व हस्तियों के साथ व्यस्त रहते हैं, बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वक्त बिताने के, लेकिन बदले हालातों में वे पार्टी की बिगड़ी सुधारने में लग गए हैं। शिंदे खेमे की बगावत के बाद शिवसेना बहुत कमजोर नजर आ रही है। पार्टी पर कब्जे के कानूनी दांवपेच भी जारी हैं। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे शिवसेना का जनाधार फिर मजबूत करने के लिए खासतौर से बागियों के गढ़ों के दौरे कर रहे हैं। बागी शिवसेना विधायकों के इलाकों में दौरे कर वे पार्टी पर ठाकरे परिवार का कब्जा और पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा बरकरार रखना चाह रहे हैं।

शिवसेना की स्थापना ठाकरे परिवार के पितृ पुरुष स्व. बाला साहब ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे परिवार की दूसरी पीढ़ी के तो आदित्य ठाकरे तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। स्थापना के बाद से पार्टी में वैसे तो कई बार बगावत हुई, लेकिन इस बार पार्टी बड़ी बगावत से जूझ रही है। आदित्य के समक्ष न केवल पार्टी की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि खुद के भविष्य की राजनीति को भी आकार देना है। आमतौर पर शांत रहने वाले 32 वर्षीय आदित्य ठाकरे के स्वर पिछले डेढ़ माह में बदल गए हैं और वे आक्रामक तेवर दिखाने लगे हैं। वे मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवसेना के युवा क्षेत्रप पार्टी का डगमगाता जनाधार मजबूत करने के लिए निष्ठा यात्रा और शिव संवाद अभियान चला रहे हैं। आदित्य ठाकरे जब मंत्री थे, तब उनको अक्सर पतलून और शर्ट में देखा गया था। कभी-कभी एक ही रंग के जूतों के साथ एक काली जैकेट पहने हुए रहते थे। लेकिन, अब माथे पर लाल तिलक लगाने लगे हैं। इसका मतलब है कि शिवसेना न केवल हिंदुत्व की राह पर लौट रही है, बल्कि कांग्रेस व राकांपा के साथ गठबंधन व सरकार बनाने से पैदा हुए पहचान के संकट को खत्म कर असल रूप में आ रही है।

शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 ने जून में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया। इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई। इसी तरह पार्टी के 18 लोकसभा सांसदों में से 12 ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ जोड़ लिया है। यानी विधानसभा के साथ ही लोकसभा में भी पार्टी बड़े नुकसान की ओर बढ़ रही है। हालांकि, शीर्ष कोर्ट के बाद ही शिवसेना के

भविष्य पर फैसला होगा। इस बीच, शिवसेना के कई पूर्व पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों ने भी पाला बदल लिया है। ऐसे में आदित्य ने बगावत रोकने, पार्टी की साख बचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उन पर शिवसेना से पलायन रोकने की जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा यात्राएं नहीं कर पाते हैं। वे कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपने आवास मातोश्री पर ही मुलाकात कर रहे हैं।

21 जून को पार्टी में बगावत शुरू होने के बाद से आदित्य ठाकरे मुंबई और उसके आसपास लगने वाली शिवसेना की शाखाओं में जाने लगे हैं और स्थानीय पार्टी कार्यालयों के भी दौरे कर रहे हैं। मुंबई और क्षेत्र के अन्य बड़े शहरों में होने वाले नगरपालिका चुनावों से पहले वे कार्यकर्ताओं को रैलियां करने की कोशिश भी कर रहे हैं। स्थानीय शाखाओं में उनके द्वारा इस तरह के दौरे पहले कभी नहीं सुने गए थे। आदित्य ठाकरे मुंबई से बाहर निकलकर कोंकण और मराठवाड़ा में शिवसेना के गढ़ों, जहां से ज्यादातर बागी हैं, का भी दौरा कर रहे हैं। वे निराश कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बागियों को इस्तीफे देकर चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ है। विद्रोह की चिंगारी शिंदे गुट में सुलगनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के शपथग्रहण के 38 दिनों बाद किसी तरह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और 9 भाजपा के और 9 शिंदे गुट के विधायकों को शपथ दिलाई गई। अब मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटने में लगातार हो रही देरी 100 सवाल खड़े कर रही है। इस बीच मंत्री ना बनाए जाने से नाराज शिंदे गुट के संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे की तारीफ में एक ट्वीट कर दिया। बच्चू कडू पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। संजय शिरसाट ने अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे को 'महाराष्ट्र के परिवार प्रमुख' कहकर संबोधित किया और उनका एक वीडियो संलग्न किया। जब सवाल किए जाने लगे तो उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। अब यह बच्चू कडू और संजय शिरसाट का 'आ अब लौट चले' का सुर है या अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें स्किप ना किया जाए, इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश, यह या तो शिंदे जानें या संजय

शिरसाट। फिलहाल तो संजय शिरसाट ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वे मंत्री बनाने के लिए किसी तरह का दबाव बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि वे कैबिनेट मंत्री समेत औरंगाबाद का संरक्षक मंत्री बनना चाह रहे हैं। अब संजय शिरसाट ने यह भी सफाई दी है कि उन्होंने तकनीकी समस्या की वजह से ट्वीट कर दिया था।

● बिन्दु माथुर

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव

● भार साधक अधिकारी

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी, जिला-हर्दा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव

● भार साधक अधिकारी

अपील

- सही तौल एवं समय पर गुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

कृषि उपज मंडी समिति, बानापूरा, जिला-होशंगाबाद

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव

● भार साधक अधिकारी

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, इटारसी, जिला-होशंगाबाद

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव

● भार साधक अधिकारी

अपील

- सही तौल एवं समय पर गुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

कृषि उपज मंडी समिति, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद

आम चुनाव में अभी समय है। करीब दो वर्ष बाकी है। इसीलिए प्रदेश में चुनाव को लेकर कोई सियासी हलचल भी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी अथवा कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के नेता फिलहाल एयर कंडीशन रूम में बैठकर सियासी तकरीरें करने में लगे हैं। किसी भी दल के नेता को अपना खोया हुआ जनाधार कैसे वापस हासिल हो या फिर पार्टी में चल रही बगावत को कैसे थामा जाए इस बात की चिंता नहीं है। कोई परिवारवाद में उलझा हुआ है तो किसी पर ईडी का 'हंटर' चल रहा है। जबकि सियासत के खेल में भाजपा की इस समय 'बल्ले-बल्ले' है। उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सहित कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं या वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है।

मिशन 2024 में उप्र सबसे अहम



भाजपा संगठनात्मक रूप से काम कर रही है, जिसका उसे भरपूर फायदा भी मिल रहा है। पूरे देश में भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही है तो इसका सबसे अधिक श्रेय उप्र को जाता है, जो 2014 से आज तक वोटों से भाजपा की झोली भरती जा रही है। उप्र में योगी सरकार हो या केंद्र में मोदी की, दोनों ही जगह भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं अब तो देशभर में मोदी के गुजरात मॉडल से अधिक योगी के बुलडोजर वाले विकास के 'मॉडल' की चर्चा हो रही है। कई राज्य योगी के विकास मॉडल को अपने राज्यों में भी उतार रहे हैं। खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए योगी मॉडल कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। अब तो यहां तक कहा जाने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश में भले ही मोदी का चेहरा आगे रहे, लेकिन उप्र में मोदी के साथ योगी का चेहरा भी जुड़ा रहेगा। क्योंकि देश की जनता जितना विश्वास मोदी पर करती है, उप्र की जनता उतना ही भरोसा योगी पर करती है। इसीलिए अब से उप्र में आम चुनाव में मोदी-योगी दोनों ही चेहरे वोटों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे तो पीछे से पार्टी के रणनीतिकार मोर्चा संभालेंगे।

वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति का खाका भाजपा पहले ही खींच

चुकी थी, लेकिन बीते तीन दिनों (29 से 31 जुलाई तक) उप्र के चित्रकूट में चले भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में संगठन को और अधिक प्रशिक्षित किए जाने पर जोर दिया गया है। इस रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए भाजपा के महामंत्री सुनील बंसल ने ठोस कदम उठाए। 'भाजपा में सबके लिए काम' का संदेश प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने दिया जिसके मायने यह निकाले जा

सकते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होने हैं और नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। चुनावी रूपरेखा को प्रदेश की नई टीम ही धरातल पर उतारेगी। यह काम अतिशीघ्र पूरा हो जाने की उम्मीद है। वैसे भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना भाजपा की पारंपरिक गतिविधि है, लेकिन यह तीन दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मूड में पूरी तरह आ चुकी है। इस बार 80 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य और सारी 80 सीटें जीतने का हौंसला साथ लेकर चल रही भाजपा क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को पहले ही प्रशिक्षित कर चुकी है। उनके प्रशिक्षण वर्ग हो चुके थे और सबसे अंत में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। भाजपा के रणनीतिकार सारा जोर जनता के बीच भाजपा को मजबूत बनाए रखने, जनकल्याण की योजनाओं, सरकार और संगठन के समन्वय से जरूरतमंदों तक पहुंचाने और विपक्ष को उसकी गलतियों पर घेरने पर दे रहे हैं। माना जा रहा है जल्द ही योगी सरकार में बदलाव कर ऐसे मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है जिनका जमीन पर जुड़ाव कमजोर है या उनकी कहीं और उपयोगिता अधिक रहेगी, इसी तरह संगठन में भी बदलाव संभावित है। एक व्यक्ति, एक पद सिद्धांत के चलते वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह को यह पद छोड़ना होगा। वैसे स्वतंत्रदेव त्यागपत्र दे भी चुके हैं, लेकिन अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। स्वतंत्रदेव इस समय योगी सरकार में जलशक्ति मंत्री हैं। जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। उसी के साथ प्रदेश और छह क्षेत्रों में भी नई टीम बनाई जाएगी।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सही तैल एवं समय पर गुगतान पाएं।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

सविब • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, भोपाल

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सविब • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सविब • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, गंजबासौदा, जिला-विदिशा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सही तैल एवं समय पर गुगतान पाएं।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सविब • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, विदिशा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सविब • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, हरदा

नीतीश कुमार के पाला बदलते ही विपक्षी यकायक भाजपा के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। हालांकि, हमेशा की तरह इनमें एका होना बहुत मुश्किल है। दरअसल, भाजपा और मोदी के खिलाफ बोल-बोलकर ये दल भाजपा के ही वोटों की वृद्धि करते फिरते हैं। हर कोई जानता है कि इनमें एका नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ बातें होती हैं। वर्षों से। शरद पवार कह रहे हैं कि भाजपा छोटे दलों को खा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा तो नीतीश को प्रधानमंत्री पद के लिए लालटेन दिखाने से नहीं चूके। उन्होंने कहा- जनता दल क्या नहीं कर सकता। उसने तीन-तीन प्रधानमंत्री दिए हैं। वैसे जनता दल ने चार प्रधानमंत्री दिए हैं। देवेगौड़ा या तो खुद को भूल गए या वीपी सिंह को। पहले वीपी, दूसरे चंद्रशेखर, तीसरे गुजराल और चौथे खुद देवेगौड़ा। ये बात और है कि इनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया।

उधर तेजस्वी यादव तो बिफर ही गए। उन्होंने कहा- भाजपा का आजकल एक ही सूत्र है, जो डरे, उसे डराओ और जो बिके, उसे खरीदो! तेजस्वी जी को ये कौन समझाए कि राजनीति में ये सब कब नहीं हुआ? और खरीदने पर इतनी ही आपत्ति है तो किसी भी दल का विधायक या सांसद या पार्षद बिकता ही क्यों है? जनता तो उस प्रतिनिधि को जिस दल ने टिकट दिया, उसी का मानकर वोट देती है, फिर ये प्रतिनिधि पाला बदलकर इधर-उधर क्यों चले जाते हैं?

जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से तो तौबा कर ली,

मुखर होने लगे क्षेत्रीय दल...



लेकिन मोदी पर तंज जरूर कसा। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा कह रही है कि आपकी सरकार ज्यादा नहीं चलेगी तो जवाब में नीतीश ने कहा- जो 2014 में आए हैं वे 2024 में भी आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कुल मिलाकर निगाह तो है नीतीश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, लेकिन वहां कोई सहारा देने वाला नहीं है। गलती नीतीश की नहीं है। विपक्षी दलों में एकता होती ही नहीं है। खुद भाजपा भी जब विपक्ष में हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस के खिलाफ एकता की बातें ही होती थीं,

आपसी झगड़ों के चक्कर में एकता दूर की कौड़ी ही रहती थी। अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में ही विपक्षी एकता की कलाई खुल चुकी है। खैर, इस मामले में केजरीवाल का कोई जवाब नहीं। वे मोदी के खिलाफ नहीं बोलते। उन्हें पता है इससे भाजपा और मोदी की ही पब्लिसिटी होगी। वे बार-बार गुजरात जाते हैं और फ्री में कुछ न कुछ बांटने का वादा करके दिल्ली लौट आते हैं। रोजगार गारंटी, बेरोजगारों को पैसा देने के वादे के बाद वे इस बार गुजरात की गैर कामकाजी महिलाओं के खाते में हजार रुपए डालने का वादा कर आए हैं। ये बात और है कि चुनाव पूर्व इस फ्री की बंदरबांट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आता, केजरीवाल को कौन रोक सकता है? प्रधानमंत्री ने तो इस पर व्यंग्य भी किया। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा- कल को कोई पेट्रोल भी फ्री में देने लगे तो हैरत नहीं होगी!

नीतीश कुमार बिहार में राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से एक बार फिर खुद को महत्वपूर्ण बना लिए हैं। राजनीति में ये नीतीश कुमार के अभिलाक्षणिक गुण माने जाते हैं। ऐसी पेंतरेबाजी हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। रामविलास पासवान के बाद नीतीश कुमार में भी कुछ लोग राजनीति के मौसम वैज्ञानिक वाली खासियतें महसूस करने लगे थे। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन में ज्यादातर केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के साथ बने रहे, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति बिलकुल अलग है।

● विनोद बक्सरी

अपील

- ♦ सही तौल एवं समय पर मुग़तान पाएँ।
- ♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, महू, जिला-इंदौर

अपील

- ♦ सही तौल एवं समय पर मुग़तान पाएँ।
- ♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, गौतमपुरा, जिला-इंदौर

अपील

- ♦ सही तौल एवं समय पर मुग़तान पाएँ।
- ♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, गंधवानी, जिला-धार

अपील

- ♦ सही तौल एवं समय पर मुग़तान पाएँ।
- ♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

सचिव ● भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, भीकनगांव, जिला-खरगौन

श्रीलंका की दुर्गति में उसके शासक ही मुख्य किरदार हैं। राजपक्षे परिवार के चार भाइयों और उनके बेटों ने शासन की पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। वे किसी पारिवारिक कारोबार की तरह सरकार चला रहे थे। खुद ही बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से जुड़े रहे। इन अव्यावहारिक परियोजनाओं के लिए बेतहाशा कर्ज लिया। इसका नतीजा आर्थिक पतन के रूप में निकला। दो दशक तक राजनीतिक परिदृश्य पर वर्चस्व बनाए रखने वाले परिवार का रातोंरात बोरिया-बिस्तर बंध गया। ईंधन, खाद्य वस्तुओं, दवाओं और बिजली की किल्लत से श्रीलंकाई जनता इतनी आक्रोशित हो गई कि उसके अप्रत्याशित विरोध-प्रदर्शन ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। गत सप्ताह प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा जनता की उस शक्ति का प्रतीक है, जिसने उस खानदान को खदेड़ दिया, जिसकी तानाशाही, भाई-भतीजावाद, विकृत पूंजीवाद और अक्खड्डपन ने श्रीलंका को अंतहीन आर्थिक दुष्क्रम में फंसाकर घुटनों के बल ला दिया। राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति की शक्तियां निरंतर रूप से बढ़ाता रहा। इसके लिए 2020 में संविधान संशोधन तक किया गया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया। चीन से दोस्ती गांठ भरपूर लाभ उठाया। इतना कि अपने देश को ही कर्ज के जाल में फंसा दिया। राजपक्षे परिवार की सत्ता का नाटकीय पतन दुनियाभर में उन

श्रीलंका की बढहाली से सबक

राजनीतिक वंशवादियों के लिए चेतावनी है, जिनकी अपने देशों में सरकार या पार्टी पर वर्चस्व है, लेकिन जवाबदेही

और सुशासन से कोई सरोकार नहीं। एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका में ऐसे तमाम परिवारों की भरमार है, जिन्होंने सरकारों को पारिवारिक मामला और राजनीतिक दलों को पारिवारिक जागीर बना दिया। राजपक्षे परिवार की बात करें तो महिंदा राजपक्षे उसके राजनीतिक साम्राज्य के सूत्रधार रहे। एक दशक तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे और इस दौरान बहुत सख्ती से पेश आए। महिंदा 2015 का चुनाव मामूली अंतर से हार गए और परिवार को कुछ समय के लिए सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसी दौरान नई सरकार में संसद ने राष्ट्रपति के कार्यकाल को सीमित कर दिया। इसके चलते परिवार को महिंदा के छोटे भाई और उनकी सरकार में रक्षामंत्री रहे गोटाबाया को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना पड़ा। इस उम्मीदवारी की पात्रता प्राप्त करने के लिए गोटाबाया ने अपनी अमेरिकी नागरिकता भी छोड़ दी। 2019 में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद गोटाबाया ने महिंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महिंदा ने भी अपने दो बेटों, दो भाइयों और एक अन्य भाई के बेटे को सरकार में जगह दी। इस परिवार का यकायक हुआ अवसान इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि राजपक्षे बंधुओं ने अपनी पहचान नस्लीय राष्ट्रवादी के रूप में बनाई थी।

● ऋतेन्द्र माथुर

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, कसरावद, जिला-खरगौन

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, सेगांव, जिला-खरगौन

75
अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

कृषि उपज मंडी समिति, बेड़िया, जिला-खरगौन

अपील

- सही तौल एवं समय पर गुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, पंधाना, जिला-खंडवा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- सही तौल एवं समय पर गुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

कृषि उपज मंडी समिति, मूंदी, जिला-खंडवा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

कृषि उपज मंडी समिति, मनावर, जिला-धार

व या साल के आखिर में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शी जिनपिंग भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? पूर्वी लद्दाख के गैर-विवादित क्षेत्र में नो फ्लाई जोन में चीन के लड़ाकू विमानों ने हाल के दो हफ्तों में एक से ज्यादा बार भारतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ानें भरी हैं। इसके अलावा भूटान के रास्ते भारत को घेरने के इरादे से चीन ने डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर भूटान की अमो चू नदी घाटी में पिछले साल जो गांव बसाना शुरू किया था, अब वहां पूरा गांव बस गया है। चीन ने इसके अलावा सीमा पर कई निर्माण किए हैं, जिन्हें उसकी भविष्य की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। यह सब घटनाएं तब हो रही हैं, जब चीन भारत के साथ कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 16 दौर हो चुके हैं।

भारत को चीन से कितना खतरा!



चीनी सेना अपनी पहुंच डोकलाम पठार की रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण चोटी तक बनाना चाहती है। जुलाई के मध्य में भारत ने भूटान को डोकलाम पठार के पास विवादित त्रि-जंक्शन क्षेत्र में चीन के कार्यों को लेकर सचेत किया था। दरअसल चीन का बड़ा उद्देश्य दबाव की स्थिति बनाकर भारत के साथ 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और थिंपू के साथ 477 किलोमीटर की विवादित सीमा के साथ दशकों से उठाए जा रहे अपने सीमा दावों को ताकत देना है। चीन की गतिविधियों को लेकर चिंता केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी जता रहे हैं। सीमा के भीतर चीन के लड़ाकू जहाजों के उड़ान भरने की रिपोर्ट्स के बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके कहा- 'चीन की सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। क्या आप (मोदी) इसका परिणाम समझते हैं?'

सन् 2017 में सिक्किम के पास डोकलाम पठार पर भारत और चीन की सेना का आमना-सामना हुआ था। सैटेलाइट से हाल में ली गई जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे जाहिर होता है कि एलएसी के पास भूटान के साथ विवादित क्षेत्र में चीन ने पिछले साल जो निर्माण शुरू किया था, वहां अब पूरा गांव बस गया है और वहां उसने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को बसाया है। तस्वीरों में दिखता है कि वहां काफी घरों के आगे कारें और अन्य वाहन खड़े हैं। दरअसल चीन रणनीतिक रूप से

महत्वपूर्ण डोकलाम पठार को वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार कर रहा है। अब ये रिपोर्ट्स पुख्ता हो चुकी हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जीओसी-इन-सी, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का कहना है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) अरुणाचल प्रदेश सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता कहते हैं- 'तिब्बत में भी एलएसी के पार बुनियादी ढांचे में बहुत विकास हुआ है और हो रहा है। दूसरी ओर सड़कों और पटरियों, कनेक्टिविटी और नए हवाई अड्डों और हेलीपैडों का निर्माण कार्य हो रहा है। सशस्त्र बलों सहित हमारी सभी एजेंसियां लगातार इन हालात की निगरानी कर रही हैं।'

उनका कहना है कि चीन की इन गतिविधियों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल मामलों में हम भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। तकनीक (टेक्नोलॉजी) के तेजी से विकास के साथ ही वेलफेयर की प्रकृति बदल रही है, इसलिए तकनीक के साथ तालमेल रखने के लिए हमें अपनी खुद की कार्यप्रणाली और विभिन्न चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया विकसित करने की ही जरूरत है। साल के आखिर में चीन में अपने नेता (राष्ट्रपति) पद का चुनाव वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को करना है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उसके बाद वह अपनी कुछ योजनाओं को अमलीजामा पहनाना चाहते हैं। क्या इसमें भारत के खिलाफ युद्ध करना भी शामिल

है? यह एक जटिल सवाल है, क्योंकि भारत की पिछले दशकों में बढ़ती ताकत से भी चीनी नेतृत्व बेचैनी महसूस करता है। खुद चीन के खराब आर्थिक हालात की रिपोर्ट्स अब आने लगी हैं। यह कहा जाता है कि जिनपिंग अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर विवाद खड़े करते हैं। हालांकि बहुत से रक्षा विशेषज्ञ चेतावते हैं कि चीन की गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तनाव वाली तमाम गतिविधियों के बावजूद एक सच यह भी है कि चीन के साथ भारत का व्यापार आज भी जारी है। यूक्रेन में युद्ध के चलते हाल में भारत ने चीन की एक निजी कंपनी ताइयुआन को 500 करोड़ के रेल पहियों का ऑर्डर दिया है। वैसे यूक्रेन की कंपनी को यह ठेका इससे कहीं कम कीमत पर दिया गया था।

लिहाजा चीन के सीमा पर तनाव बढ़ाने के बावजूद कुछ विशेषज्ञ उसके व्यापारिक हितों का हवाला देते हुए मानते हैं कि वह युद्ध की सीमा तक शायद ही जाए। दूसरा भारत की सैन्य क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता। वैसे भी चीन के भीतर ही शी जिनपिंग के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। इनमें आर्थिक चुनौतियां भी शामिल हैं। यह कुछ ऐसे बिंदु हैं, जो उनके लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ा भी बन सकते हैं। क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उनके विरोधी कम नहीं हैं, खासकर उनकी आर्थिक नीतियों के। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन से बड़ी संख्या में व्यापारियों का दूसरे देशों को पलायन हुआ है।

● कुमार विनोद

75 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अमृत महोत्सव
सचिव • भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, सैलाना, जिला-रतलाम

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...
75 अमृत महोत्सव
सचिव • भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, दलौदा, जिला-मंडसौर

अपील
सही तैल एवं सक्कर पर गुणताम पाए।
• किसान भाई अपनी फसल का कृष-मित्रता मंडी प्रालय नै ली करें।
• नीलामी के समय किसान भाई अपने डेर पर उपस्थित रहें।

75 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
अमृत महोत्सव
सचिव • भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, पिपल्या, जिला-मंडसौर

मेहंदी का रंग

आज शकुंतला के सामने पिछली कई तीजों के दृश्य घूम गए। छोटी बहू श्यामली सबके हाथों में मेहंदी लगाकर अपने बाईं हथेली को सुंदर तरीके से मेहंदी से अलंकृत करती तथा पति तुषार से दाईं हथेली पर एक गोल टिक्की बनवाकर अपना और तुषार का नाम लिखवाती थी।

तीज के दिन उठकर दोनों बहूएं सबसे पहले सास के चरण स्पर्श करके उनकी मेहंदी देखती; फिर अपनी दिखाती। शकुंतला खूब खुश होकर दोनों को झोली भरकर आशीर्वाद देती। लेकिन पिछले वर्ष दिवाली से चार दिन पहले तुषार की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई सब बदल गया; श्यामली की मेहंदी का रंग उड़ गया। कितना समझाया सबने श्यामली को... आजकल कौन ऐसे रहता है? जमाना बदल गया है।

शकुंतला का मन बहू का यह रूप देख टूट जाता। उन्होंने भी पति के जीवित होते हुए खुद को विधवा का जामा पहना दिया। छोटी बहन ने समझाने की कोशिश की तो उसे भी एक डंट लगा दी। मेरे सामने जवान बहू का सिंगार चला गया और मैं सिंगार करूँ... मेरे दिल पर हथौड़े चलते हैं श्यामली का यह रूप देखकर। श्यामली ने अपने सिलाई के डिप्लोमा का उपयोग किया। कोने के घर में एक तरफ निकली हुई ससुर की बनाई हुई दो दुकानों में से एक दुकान में अपनी सिलाई की दुकान खोल दी।

श्यामली इधर आ 'शकुंतला की बड़ी बहू सुषमा बोली सुषमा ने श्यामली की हथेली पर जैसे ही मेहंदी का कोन छुआया, श्यामली ने अपना हाथ ऐसे खींचा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। तो सुन ले अगर आज तूने मेहंदी नहीं लगाई तो मैं कभी मेहंदी नहीं लगाउंगी चल लगा मेहंदी। अपने लिए नहीं तो दोनों बच्चों के लिए सज लिया कर सुषमा ने कहते हुए हाथ खींच कर श्यामली की हथेली पर मेहंदी लगा दी।

नव्या भी मां को खुश देखकर अपने आप छोटी सी हथेली पर मेहंदी लगाने लगी। श्यामली ने देखा उसके दोनों बच्चे आज कितने महीने बाद खुलकर हंसे हैं। नव्या तो आठ साल की है दस साल के आरव ने भी दादी की हथेली पर गोल टिक्की बना दी। सुषमा! आज तूने जो किया है उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है आ मेरे गले लग जा। शकुंतला स्नेह सिक्त स्वर में बोली। मम्मी जी! औरत को औरत बनकर ही समझना होगा; ना कि सास, जेठानी-देवरानी बन कर तब ही मेहंदी रंग जाएगी, सुषमा मुस्करा कर बोली।

- दीप्ति सिंह

भारतीय ध्वज संहिता

(Flag Code of India) के प्रमुख प्रावधान



- राष्ट्रीय ध्वज के मापदण्ड भारतीय झण्डा संहिता के पार्ट-1 के अनुसार हो।
- राष्ट्रीय ध्वज स्वादी, कॉर्टन, रेसम, पोलिएस्टर से निर्मित हो।
- राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक, निजी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन या विशेष अवसर पर फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज गौरव व आदर सहित दिन या रात के समय फहराया जाना चाहिए।
- तिरंगा आयात आकार में चौड़ाई व लंबाई क्रमशः 3:2 के अनुपात में फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को Half Mast (आधे डण्डे) पर नहीं फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल स्वेच पेन आदि से कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए।
- फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह नहीं फहराया जाए, जिससे ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो।
- राष्ट्रीय ध्वज को Single Mast पर फहराया जाना चाहिए तथा उस Mast पर अन्य कोई झण्डे के साथ में नहीं फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि झण्डा फहराने से कोई व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की स्थितियां निर्मित नहीं हो रही हों।
- राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरान्त सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाए, जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे।
- राष्ट्रीय ध्वज को धोकर तथा तदपश्चात् सहेजकर घर में ही सुरक्षित स्थान पर रक्षना चाहिए।

नगर पालिका परिषद, नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय नगरपालिका परिषद, इटारसी

● 15 अगस्त 2022, स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं ●

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर नगर के विकास का नया इतिहास रचने का संकल्प लेकर नगरवासियों की समस्यामुक्त जिन्दगी का हक दिलाने में प्रयासरत रहेंगे।



● नागरिक बन्धुओं से विनम्र अपील ●



- शहर में पॉलीथिन प्रतिबंधित है, कृपया पॉलीथिन का इस्तेमाल न करें।
- घर का कचरा बाहर न फेंकें। कचरा, एकत्रित कर कचरा, नगरपालिका के कचरा वाहन में डालें।
- नगर के विकास एवं केंद्र और राज्य सरकार की कार्य योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हुए कर्तव्य का भुगतान समय सीमा में करें।
- अतिक्रमण प्रथा पर रोक लगाने हेतु न तो स्वयं अतिक्रमण करें न ही दूसरों को अतिक्रमण करने दें।
- नलों में टॉटी लगावें, जल को व्यर्थ न बहने दें।
- निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करें।
- पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षों को न काटें और न ही काटने दें।
- वृक्षारोपण अंतर्गत पेड़ लगाएं।
- विवाह तथा जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन अवश्य ही करावें।

श्री पंकज चौरे
अध्यक्ष

श्रीमति हेमेश्वरी पटले
मुख्य नगरपालिका अधिकारी

एवं समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, नगर पालिका परिषद, इटारसी जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

लकखा सिंह युवा लेखक बिक्रम सिंह का नया उपन्यास है....

यहां दो सिंह एक साथ हैं....लकखा और बिक्रम.... थोड़ी बातें बिक्रम की.....ज्यादा बातें लकखा की....

लकखा सिंह बिक्रम सिंह का तीसरा उपन्यास है....अपना खून और यारबाज इनके पहले प्रकाशित दो उपन्यास हैं....चार कहानी संग्रह प्रकाशित हैं इनके....वारिस (2013), और कितने टुकड़े (2015), गणित का पंडित (2017) और काफिल का कुत्ता (2017)....

बिक्रम खूब लिखते हैं....और खूब छपते भी हैं....हिंदी की करीब करीब सभी पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ छपती रहती हैं....अपना खून पहले मंतव्य के लम्बी कहानी

जात न पूछो साधू की...

अंक में छपा....बाद में उपन्यास...थोड़े और विस्तार के साथ....इनकी कहानी बहू भी मंतव्य में ही छपी थी....बिक्रम अपनी रचनाओं में अपना अनुभव संसार रचते हैं....

लकखा सिंह पंजाब का एक साधारण खेतिहर मजदूर का बेटा रानीगंज के कोयले के खदान में नौकरी करता है....

उपन्यास हमें रानीगंज के मजदूरों के क्वार्टर में ले जाता है....जहां सूअर और कुत्तों के गू का साम्राज्य छाया हो जैसे...सड़क नाली तो छोड़िए....लोगों के घरों के दरवाजे के बाहर तक....नायिका सफाई पसंद है...धिन्न आती उसे....दिन भर जुटी रहती है इस गंदगी और

गंध से स्वयं को मुक्त करने में....मजदूर दिन भर खदान में हाड तोड़ मिहनत किया...रात में पत्नी का नाडा जबरन खोल दिया....उसकी मर्जी हो या नहीं...मायने नहीं रखता.....नतीजा....जितने कुत्तों और सूअरों के बच्चे उतने मजदूरों के....नायिका को इन्सान का जानवर होना पसंद नहीं....इस लिए चिड़चिड़ी सी रहती है...पूरे देश के लोग रहते हैं वहां...इसलिए भाषा संस्कृति भी मिली जुली है....

बिक्रम सिंह की लेखनी की खासियत ये है की वो अपने लेखन से हमें उस वातावरण में ले जाने में सक्षम होते हैं....वहां का जीवन स्वाभाविकता के साथ आता है....रूप रंग गंध सब....गरीबी

मजबूरी की परतें अपने आप खुलती चली जाती हैं....पर सब संतुलित सा रहता है....अतिरेक से बचते हैं.... क्वार्टर में रहने वाले सभी का काम एक सा ही है पर जाति भेद उनके व्यक्तित्व में भीतर तक समाया हो जैसे....मजदूर हैं तो क्या हुआ ब्राह्मण राजपूत और चमार एक से हो जाएंगे क्या....

कथा का नायक पंजाब का रहने वाला है...जिसके पिता बटवारे के समय पकिस्तान से आकर पंजाब के एक गांव में बस गए थे....वहां जाट सरदारों की जमीन के खेतिहर मजदूर बन गए....खेती में मजूदारी करने वाले पिता का खदान में काम करने वाला मजदूर बेटा है लकखा सिंह....लकखा के पिता की यादों में उनका अपना गांव है...जो अब पकिस्तान में है...।

- विक्रम सिंह

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...



75

अमृत महोत्सव

वंदे मातरम...

अपील

- सही तौल एवं समय पर मुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन

75

अमृत महोत्सव

जय हिंद...

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...




अपील

- सही तौल एवं समय पर मुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- समी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, देवास

म प्र में लोगों की औसत आयु 67 साल हो गई है। पिछले 10 साल में इसमें 5 साल का इजाफा हुआ। ये जानकारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के 2015-2019 के डेटा में सामने आई। इसके मुताबिक मप्र को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (औसत आयु) में 5 साल जोड़ने में करीब 10 साल लग गए। 2005-09 में यह 61.9 साल थी, जो 2015-19 में 67 साल हो गई। खास बात यह है कि पिछले 25 साल से राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औसत उम्र ज्यादा है, जबकि इससे पहले महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा जी रहे थे। इतना ही नहीं, गांवों के मुकाबले शहरी महिलाओं की उम्र लंबी है।

ग्रामीणों की औसत आयु शहरी आबादी के मुकाबले कम क्यों है? इस पर सीनियर पल्मनोलॉजिस्ट डॉ. लोकेंद्र दवे बताते हैं कि गांव के लोगों की औसत आयु कम होना उनके जन्म

महिलाएं स्ट्रेस नहीं लेती...

से ही शुरू हो जाता है। गांव के लोगों को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। यहां ज्यादातर महिलाएं एनीमिया का शिकार होती हैं। सबसे बड़ी वजह न्यूट्रिशन की कमी है। डॉ. दवे कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी महिलाओं खासकर लड़कियों की बीमारी को परिवार गंभीरता से नहीं लेता। यदि बेटी को टीबी की बीमारी है, तो उसका इलाज शुरू करने में देरी की जाती है। शिक्षा का स्तर कम होना भी ग्रामीण महिलाओं की आयु कम होने के लिए जिम्मेदार है। 1970-75 में मप्र की जन्म के समय प्रत्याशा दर 47.2 साल थी। अगले 45 साल के दौरान इसमें करीब 22 साल से ज्यादा का इजाफा हुआ। 2015-19 के आंकड़ों में राज्य की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष हो गई है। दिल्ली की जीवन प्रत्याशा 75.9 साल है, जो देश में सबसे

ज्यादा है। इसके बाद केरल, जम्मू और कश्मीर का नंबर आता है। सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में मप्र का नंबर तीसरा है, जबकि उम्र का नंबर दूसरा है। छत्तीसगढ़ की जीवन प्रत्याशा देश में सबसे कम है। बता दें कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 69.7 साल है।

कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट मानते हैं कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से इसलिए ज्यादा होती है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में नवजात बालकों की अपेक्षा नवजात बालिकाओं के जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है। महिलाओं को यह लाभ ज्यादातर जैविक तथ्यों के चलते मिलता है। हार्मोन खासकर एस्ट्रोजेन, जो संक्रामक बीमारियों के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दिल की बीमारी भी कम होती है। इसकी एक वजह महिलाओं का स्ट्रेस नहीं लेना भी है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, रतलाम

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, आगरा, जिला-शाजापुर

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, जावरा, जिला-रतलाम

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, शुजालपुर, जिला-शाजापुर

अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव, जिला-देवास

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75
अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, तराना, जिला-उज्जैन

यदि शब्दकोश से ऐसे शब्द का चयन करने के लिए कहा जाए जो सर्वाधिक भ्रामक है तो निःसंदेह वह होगा - 'धर्म'। धर्म शब्द का जितना उपयोग हुआ है उतना ही दुरुपयोग। धर्म के उपयोग ने मनुष्य को देवता बनने का रास्ता बताया तो उसके दुरुपयोग ने दानव बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। धर्म के कारण अनेक सभ्यता-संस्कृतियां उदय हुईं, कलाओं का विकास हुआ तो धर्मांध युद्धों ने एक झटके में इन सबका विनाश भी कर दिया। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए धर्म के दुरुपयोग का वही परिणाम होता है जो धर्मांध युद्धों का हुआ है। ऐसी स्थिति में धर्म की सही और सम्यक समझ आवश्यक है।

भगवान ने जिस वस्तु को जिस प्रयोजन के लिए रचा है उसकी पूर्ति करना ही उस वस्तु का स्वभाव है और इसे ही उसका धर्म कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है तो प्रकाश देना सूर्य का धर्म है। अग्नि अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को भस्म कर देती है तो जलाना अग्नि का धर्म है। यह स्वभाव सृष्टि में स्वमेव प्रकट हुए हैं, अपरिवर्तनीय हैं। इस नियम-तंत्र को उस वस्तु या जीव (व्यष्टि) का धर्म कहते हैं। दूसरी ओर भारतीय दर्शन में माना जाता है कि चर और अचर, मनुष्य, प्राणी, पेड़-पौधे, पर्वत, नदी आदि सभी में अर्थात् कण-कण में परमसत्ता व्याप्त है जिसे ब्रह्म कहते हैं। परमसत्ता के नियमों के अनुसार ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। इन नियमों के कारण ही सूर्य समय पर उगता है, मौसम बदलते हैं, मृत्यु और जन्म होते हैं, कर्म अपना फल देते हैं आदि। समष्टि का यह स्वभाव या नियमतंत्र धर्म का शाश्वत रूप है।

सृष्टि में मनुष्य को छोड़कर जितने भी चर-अचर, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, पर्वत, नदियां आदि हैं वे प्रकृति के नियमों और अपने स्वभाव से बंधे हैं, वही उनका धर्म है। उन्हें कुछ और करने की स्वतंत्रता नहीं है। नदियां पानी से भरकर समुद्र की ओर ही दौड़ेगी, अग्नि दहन करेगी, आम का पेड़ आम ही देगा अमरूद नहीं, पक्षी वैसा ही चोंसला बनाएंगे जैसी उसकी नस्ल शुरू से बनाती रही है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, आदि। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि, विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है इसलिए उसका धर्म है जगत के समस्त प्राणियों, जीवजगत को जीवन जीने का अवसर देने और प्रकृति को संरक्षित रखते हुए सांसारिक सुखभोग करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म से अभिन्न हो जाना। इस स्वतंत्रता के कारण मनुष्य समष्टि के नियमों के अनुकूल भी चल सकता है और उसके विपरीत भी। इन नियमों के अनुकूल किया गया आचरण धर्म कहलाता है।

इस प्रकार धर्म के दो रूप हैं- आंतरिक व बाह्य। जैसे प्रकृति का स्वभाव विज्ञान है जो पूरे संसार में एक सा है इसी प्रकार ब्रह्म का स्वभाव अध्यात्म है जो पूरी सृष्टि में एक सा है। यह धर्म का शाश्वत रूप है, परम सत्य है जो देश काल की सीमाओं से परे है। ईश्वर की उपासना की विशिष्ट विधियों जैसे यज्ञ, दान और तप आदि से धृति, क्षमा, ऋजुता, शम, दम आदि यम-नियम जीवन में शनैः-शनैः अवतरित होने लगते हैं। इससे आंतरिक धर्म की वृद्धि होती है, चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। शुद्ध चित्त में ही परमात्मा की झलक मिलती है। अंतिम स्थिति में सृष्टि के कण-कण में ब्रह्म की सत्ता का सतत् दर्शन होने लगता है। यही धर्म का परम लक्ष्य है। यहां उल्लेखनीय है कि ईश्वर की पूजा, स्तुति, यज्ञ आदि अपने-आप में पूर्ण धर्म नहीं हैं यह तो धर्माचरण का एक अंग मात्र है।

परम सत्य का अनुभव करने की योग्यता पैदा करने के लिए जो सांसारिक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं वह धर्म का बाह्य रूप है जो परिवर्तनीय है व देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति के स्वभाव, आयु, सांसारिक दायित्व आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। खान-पान, रहन-सहन व व्यवहार संबंधी नियम व कर्तव्य धर्म के बाह्य व परिवर्तनशील रूप के अंतर्गत आते हैं।

सामान्य धर्म- अस्तित्व के स्वभाव के आधार पर व्यवहार के कुछ नैतिक नियम हैं जो सभी पर एकसमान लागू होते हैं, इन्हें सामान्य धर्म कहते हैं। श्रीमद्भागवत में सत्य, दया, तपस्या आदि तीस धर्म बताए गए हैं। मनुस्मृति (6.92) में धर्म के दस लक्षण बताए हैं- संतोष, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (शरीर की स्वच्छता), इन्द्रियनिग्रह, धी (शास्त्रज्ञान), विद्या (आत्मज्ञान), सत्य और अक्रोध। (महा.शांति.162/8-9) में धर्म के 13 रूप बताए गए हैं- सत्य, समता, दम, अमात्सर्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा (सहन-

अनेक रूप होते हैं धर्म के

शीलता), अनसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, श्रेष्ठ आचरण, धैर्य और अहिंसा। यह अपने स्वरूप में न हिंदू हैं, न मुस्लिम, न ईसाई और न ही कोई अन्य। यह तो ऐसे जीवन-मूल्य हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी हैं।

● ओमप्रकाश श्रीवास्तव



स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- ♦ सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- ♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, नीमच

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- ♦ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- ♦ सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हक्काल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर, जिला-उज्जैन

75

अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, मंडसौर

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- ♦ सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- ♦ किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- ♦ नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें।

सचिव • भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर, जिला-उज्जैन



भोपाल विकास प्राधिकरण

विज्ञापन क्रमांक 3179/संफवा/भोविप्रा/22

भोपाल, दिनांक 02.08.2022

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत

मूल्य पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य दर पर ऑनलाईन आमंत्रित रिक्त सम्पत्ति जैसे- प्रकोष्ठ/डुप्लेक्स/हॉल/पी.एस.पी. भूखण्ड/दुकानें, जो कि निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन ऑफर वेबसाइट <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से नियत दर/प्रस्ताव दिनांक 4.08.22 से दिनांक 22.08.22 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 23.08.22 को खोले जावेंगे। निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट www.bda.org.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र.	योजना का नाम	ऑफर/नियत दर	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति की संख्या	रिमार्क
1	गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, साकेत नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
2	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स (पी. एण्ड टी चौराहा)	ऑफर	हॉल	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
3	सोनिया गौधी परिसर (कोटरा सुल्तानाबाद)	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
4	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स (पी0एण्ड0टी चौराहा)	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
5	एम0जी0 रुसिया नगर, पीपलनेर	ऑफर	डुप्लेक्स	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
6	कटारा हिल्स सेक्टर-ए एवं सी	ऑफर	दुकानें	31	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
7	आई.एस.बी.टी. (कूशभाऊ ठाकरे टर्मिनल)	ऑफर	दुकानें	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
8	गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर परिसर (साकेत नगर)	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
9	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स (पी0एण्ड0टी चौराहा)	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
10	पंचशील नगर	ऑफर	दुकानें	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
11	महर्षि पतंजलि	ऑफर	दुकानें	35	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
12	पंडित भीमसेन जोशी परिसर, साकेत नगर (एम्स के पास)	ऑफर	दुकानें	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
13	माता मंदिर (न्यू मार्केट)	ऑफर	दुकानें	08	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
14	आमेर कॉम्प्लेक्स नाले के ऊपर जॉन-2, एम.पी.नगर	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
15	बस स्टॉप नं0-7	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
16	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स, (भवन)	ऑफर	भवन	25	रेरा पंजीयन क्र.- पी-बी.पी. एल-21-2845
17	स्वामी विवेकानन्द परिसर, कटारा हिल्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	45	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
18	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स स्थित डुप्लेक्स भवनों	ऑफर	भवन एमआईजी/एचआईजी	05	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
19	एयरोसिटी योजना में (एयरो रेसीडेंसी)	ऑफर	डुप्लेक्स भवन	69	रेरा पंजीयन क्र.- पी-बी.पी. एल-17-246
20	लॉयर्स चेंबर	ऑफर	चेंबर	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
21	विद्या नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ क्र.- 13-ए	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
22	महर्षि पतंजलि, गौदरमड	नियत दर	प्रकोष्ठ	22	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
23	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स स्थित ई.डब्ल्यू.एस	नियत दर	ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ	12	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
24	अमरावद खुर्द	नियत दर	एल.आई.जी डुप्लेक्स	21	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
25	नवीभाग योजना (बैरसिया रोड)	नियत दर	2 बीएचके प्रकोष्ठ 1 बीएचके प्रकोष्ठ	21 01	रेरा पंजीयन क्र.- पी-बी.पी. एल-17-837

नोट-वेबसाइट पर दिये गये लिंक को ओपन करने के पश्चात् आपको योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदर्शित होगी। जिसमें सम्पल फार्म, योजना के मानचित्र तथा प्रकोष्ठ/दुकान/हॉल के मानचित्र व अपलोड करने हेतु विभिन्न आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देखी जा सकती है। ऑनलाइन फार्म भरने हेतु प्राधिकरण की आई.टी. सेल से सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकतानुसार जानकारी हेतु सम्पर्क-

1-श्री रवि सिंह मो.-8770234380

सम्पदा अधिकारी

काँ मनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारत की खाते में 5 मेडल आए। और, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज समेत कुल 61 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। वहीं, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले स्थान पर दबदबा कायम रखा। बताना जरूरी है कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने मेडल टैली में 66 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर कब्जा किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारत के खाते में चार गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल आए। लेकिन, वो क्या वजहें रहीं जो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाया? आइए जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत के लिए कैसा रहा? और, किन इवेंट्स में भारतीय सूरमाओं ने गोल्ड का मौका गंवाया? भारत को मेडल टैली बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है ट्रेक बदलना?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शूटिंग और आर्चरी ऑप्शनल स्पोर्ट्स में शामिल थे। जिसके चलते इस बार बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया था। पुराने आंकड़ों को देखा जाए, तो शूटिंग के सहारे भारत का मेडल टैली में स्थान और मजबूत हो सकता था। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को शूटिंग में 16 मेडल मिले थे। जिनमें 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल थे। इस लिहाज से देखा जाए, तो भारत को शूटिंग के कॉमनवेल्थ गेम्स में न शामिल किए जाने से बड़ा झटका लगा था। लेकिन, इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल टैली में भारत को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया। ये अपने आप में देश के खिलाड़ियों का एक बड़ा प्रदर्शन ही कहा जाएगा। कुश्ती के खेल में भारत का हमेशा से ही दबदबा रहा है। तकरीबन हर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को शूटिंग के बाद सबसे ज्यादा मेडल कुश्ती में ही मिलते रहे हैं। इस बार भी कुश्ती के खेल में भारत के खाते में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। कुश्ती के अलग-अलग वेट कैटेगरी के 12 इवेंट में उतरे भारतीय पहलवानों ने हर इवेंट में कोई न कोई पदक जीता ही है। वैसे, कुश्ती के खेल में जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है। उसे देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि भारत के पास सिल्वर और ब्रॉन्ज को गोल्ड में बदलने का मौका था। लेकिन, ऐसा हो नहीं सका। वैसे, भारत के लिए 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि, संभव है कि शूटिंग के बाद कुश्ती को भी कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा न बनाया जाए। और, ऐसा होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तो, भारत को दूसरे खेलों में अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा।

2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को वेटलिफ्टिंग में 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत 14 मेडल मिले थे। वहीं, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 9 मेडल भारत के खाते में आए थे। आसान शब्दों में कहा जाए, तो 2018 में भारत के गोल्ड मेडल बढ़े थे। लेकिन, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल घट गए थे। वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को केवल 3 गोल्ड ही मिले। वहीं, अलग-अलग वेट कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों को 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज ही मिल सके। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछले प्रदर्शनों के हिसाब से भारतीय वेटलिफ्टरों का प्रदर्शन इस बार कुछ खास नहीं रहा।

कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रेक एंड फील्ड इवेंट में भारत का प्रदर्शन चौंकाने वाला कहा जा सकता है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। लेकिन, इसके

भारत को ट्रेक बदलना जरूरी



बाद से ट्रेक एंड फील्ड इवेंट में भारत का प्रदर्शन लगातार घटता ही रहा। वहीं, इस बार जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड ला सकने वाले नीरज चोपड़ा चोटिल होने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं हुए थे। तो, यह भारत के लिए ट्रेक एंड फील्ड इवेंट में बड़ा झटका था। इसके बावजूद भारत ने एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल कब्जा लिए। वैसे, भारत को ट्रेक एंड फील्ड में मिली सफलता को बरकरार रखना होगा। क्योंकि, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को हटाए जाने की संभावना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने बैडमिंटन में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं, 2018 में भारत को बैडमिंटन में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। देखा जाए, तो इस बार भारत का गोल्ड बढ़ा है। लेकिन, 2018 की तुलना में एक मेडल का नुकसान ही हुआ है। लेकिन, भारत में खेलों को लेकर बदले माहौल में उम्मीद की जा सकती थी कि ये सभी मेडल गोल्ड में तब्दील हो सकते हैं। और, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का मेडल टैली ऊपर बढ़ेगा।

● आशीष नेमा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

75
अमृत महोत्सव



श्री गगन बिसेन
एसडीएम

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान माई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री आर.के. सैयाम
सचिव

कृषि उपज मंडी समिति, दमोह

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

75
अमृत महोत्सव



श्री विजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
सचिव

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।

- सभी किसान माई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री सी.पी. पटेल
भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़



सही शॉट न देने की वजह से डायरेक्टर ने सैफ अली खान फिल्म से निकाल दिया था

रेस, ओमकारा, हम तुम और लव आजकल जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले सैफ अली खान फिल्मों के साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं।



सैफ को फिल्म बेखुदी से निकाल दिया गया था। डायरेक्टर राहुल रवैल जो कि अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते थे उन्होंने सैफ को फिल्म से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने फिल्म का पहला ही शॉट गलत दे दिया था। बाद में इस फिल्म के लिए सैफ की जगह पर एक्टर कमल सदाना को कास्ट किया गया।

जाने जाते थे उन्होंने सैफ को फिल्म से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने फिल्म का पहला ही शॉट गलत दे दिया था। बाद में इस फिल्म के लिए सैफ की जगह पर एक्टर कमल सदाना को कास्ट किया गया।

12 साल बड़ी एक्ट्रेस से की थी गुपचुप शादी-सैफ अली खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही खुद से 12 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह को दिल दे दिया और उनसे शादी कर ली। सैफ के परिजन इस शादी के खिलाफ थे जिसकी वजह से इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई। बाद में दोनों ने सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के रूप में दो बच्चों को जन्म दिया। पर बाद में 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया था।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री उदयभान चतुर्वेदी
सचिव

श्री वीरेंद्र बघेल
भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, गुना

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री हरेंद्र सिंह रातौर
सचिव

श्री गणेश जायसवाल
भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, शिवपुरी

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री पंजाब सिंह दादीरिया
प्रभारी सचिव

श्री शिवलाल शावक
भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, मुरैना

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

गिरिजा गोयल
प्रभारी सचिव

श्री लोकेंद्र सिंह सरल
भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, श्योपुर

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री भागीरथ प्रसाद अहिरवार
सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, अशोकनगर

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

75

अमृत महोत्सव

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- सभी किसान भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।

श्री कुंजविहारी शर्मा
सचिव

श्री प्रदीप शर्मा
भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, डबरा



साहित्य के विरुद्ध सियासत की साजिश

लोकतंत्र में साहित्य की गरिमा गिरी है। अब से लोकतंत्र के मंदिर में किसी को कोई चोर-उचक्का नहीं कह सकता। यहां तक कि पाखंडी, बेशर्म, भ्रष्ट और मूर्ख कहना वर्जित है। ये सारे शब्द अब बेहद शरीफ हो गए हैं।

मेरे एक परम मित्र हैं, जो पहुंचे हुए आलोचक हैं। साहित्य और राजनीति में उनका एक समान दखल है। जब भी उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, फायरिंग करने मेरे पास आ जाते हैं, पर कल तो गजब हो गया। वे नहीं आए, उनका फोन आ गया। हलो कहते ही शुरू हो गए, भाई, बात ही कुछ ऐसी है कि मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें बताने आऊंगा, तब तक सारी गर्मी निकल जाएगी। इसलिए सोचा फोन पर ही निपट लेते हैं। मैंने पूछा, क्या बात है दोस्त? उधर पानी नहीं गिर रहा क्या? मित्र के लहजे में अचानक तलखी आ गई। मेरे ऊपर बरसने लगे, पानी गिर रहा हो या न गिर रहा हो, रुपया रोज गिर रहा है। बाजार गिर रहा है। हम भी कब तक बचेंगे? ऐसा कहकर वे लंबी-लंबी सांसें लेने लगे। तुम भी जल्द गिरने वाले हो मित्र! सुना है, इस साल का सूरमा भोपाली सम्मान तुम पर ही गिरने जा रहा है। बिल्कुल अंदर की और सौ टका पक्की खबर है। मैंने यूँ ही हवा में तीर चलाया। वे कराह उठे-कभी तो सीरियस रहा करो दोस्त! होटलों में सरकार गिर रही है और सड़क पर संगठन। सारे देश में गिरावट का दौर है और तुम्हें मसखरी सूझ रही है। बड़ी गंभीर स्थिति है। देश को बचाने के लिए हमें एक होना होगा। उन्होंने अपना फरमान सुना दिया।

यह सुनकर मेरा सिर चकरा गया। सनद रहे, यह वही सिर है, जिसके ऊपर आलरेडी जमाने भर का भार लदा है। उसी पर आलोचक-मित्र ने गिरावट बचाने का भार भी लाद दिया। मैंने उन्हें बताया, इससे भी बड़ी और ताजा खबर हमारे पास है। साहित्य का भुखर-सम्मान घोषित हुआ है। इस बार यह सम्मान दूसरे गुट के प्रखर लखनवी ले उड़े हैं, जिनकी पिछली किताब की तुमने धिञ्जियां उड़ाई थीं। अब वही तुम्हें गिरा हुआ आलोचक साबित करने पर तुले हैं। यह सुनकर मित्र हिल गए। कहने लगे, पहले मुझे संदेह था अब भरोसा हो गया है। तुम भी पूरी तरह गिर चुके हो। मैं तो अपनी मानहानि की कहीं न कहीं भरपाई कर ही लूंगा। फिलहाल मुझे अपनी नहीं,

देश और समाज की चिंता है। लोकतंत्र में साहित्य की गरिमा गिरी है। अब से लोकतंत्र के मंदिर में किसी को कोई चोर-उचक्का नहीं कह सकता। यहां तक कि पाखंडी, बेशर्म, भ्रष्ट और मूर्ख कहना वर्जित है। ये सारे शब्द अब बेहद शरीफ हो गए हैं। सड़क पर किसी को गुंडा कह दो तो उसे टिकट मिल जाता है। वही टिकट लेकर वह माननीय हो जाता है। सड़क पर इन शब्दों से कोई बुरा तक नहीं मानता। ऐसे पवित्र शब्दों को सदन में गिरने से रोका जा रहा है। कहते हैं इससे संसदीय गरिमा गिरती है। ऐसे शब्दों के जीते-जागते प्रतिमान वहां सशरीर बैठ तो सकते हैं, पर ये निर्जीव शब्द सदन में नहीं घुस सकते।

यह साहित्य के विरुद्ध सियासत की साजिश नहीं तो और क्या है? इसके विरुद्ध हमें मिलकर लड़ना होगा। तभी हम अपने हिस्से का सम्मान खींच पाएंगे। उनकी आवाज कमजोर होती हुई महसूस हुई।

उधर मित्र ने फोन होल्ड पर धर दिया। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। मूल्यों की गिरावट इतनी हो गई और मुझे टमाटर तक के दाम गिरने की खबर नहीं मिली। खुद को गिरा हुआ फील करता, तभी उधर से उनकी चहकती हुई आवाज सुनाई दी, दोस्त, तुम्हारा लेखन भले टू जी स्तर का हो, नेटवर्क बिल्कुल फाइव जी टाइप है। तुम्हारी खबर पक्की निकली। अभी भोपाल से ही फोन आया था। वे बस मुझे सम्मानित करने की सहमति चाहते थे। अब इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि सामने से आ रहे सम्मान-प्रस्ताव को तुकरा दूँ! इसलिए मैंने बड़ी विनम्रता से उनको हां कर दी। अब बस बैंक जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बीच में टोका, मगर इस समय बैंक जाने की क्या जल्दी है? मित्र तुरंत बोल उठे, भई, आधुनिक सम्मान है। उसे पाने में तन-मन-धन से लगना पड़ता है। यह बस सामान्य प्रक्रिया है। तुम नहीं समझोगे। कभी सम्मानित हुए हो तो जानो! इतना कहकर वे निकल लिए और मैं तभी से साहित्य में अपनी गिरावट पर चिंतन कर रहा हूँ। उनकी बात सोलह आना सच निकली। वाकई गिरावट की कमी नहीं है देश में!

● प्रमोद दीक्षित 'मलय'

mycem
cement

 **Zuari Cement**

HEIDELBERGCEMENT
INDIA

We renew our commitment and continue contributing towards building durable foundations of resilient India that last centuries.





**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA₂ and HbF

Flexible
to solve more testing needs


Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA₂/FIA₂ testing using primary tube sampling—so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress—and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

 C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5  Email : shbple@rediffmail.com
 Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687